हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 मार्च, 1989

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 2 मार्च, 1989

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एव उत्तर	(8)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(8)24
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)25

विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(8)27
वाक आउट	(8)27
विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(8)28
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
बीड़ श्योंठी के जंगल में नील गाय तथा बन्दरों पर रोक संबंधी	(8)28
वक्तव्य–	
वन तथा वन्य प्राणी संरक्षण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(8)29
गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ) –	
प्रेषित माल पर कर सम्बन्धी	(8)32

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 2 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्ष ता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, अब सवाल होंगे।

Roads Damaged by Rains/Floods

***670. Shri Rattan Lal Kataria :** Will the Minister for. P.W.D. (B & R) be pleased to state the total mileage of roads damaged due to recent rains and floods in the State togetherwith the steps, if any, taken or proposed to be taken to repair the said roads ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज): राज्य में वर्ष 1988 में वर्षा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की कुल लम्बाई 4087 किलोमीटर है। बाढ़ से हुई हानि के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 17.95 करोड़ की राशि के विरुद्ध भारत सरकार ने केवल 4.50 करोड रुपये उपलब्ध कराये हैं। तदानुसार सड़कों की मुरम्मत करने बारे योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा मुरम्मत उच्च स्तर पर आरम्भ कर दी गई है ताकि मुरम्मत का

कार्य जितना शीघ्र संभव हो, अगले वर्षा ऋतु से पहले किया जा सके।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर सम्बन्धित गांव की पंचायत अर्थ वर्क करा दे और सरकार को जमीन के लिए मुआवजा न देना पड़े तो कग अगले वर्षा के मौसम से पहले छोटे छोटे टुकड़ों को पूरा कर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर सर, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि 4087 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें वर्षा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं और 17. 95 करोड रुपये का नुक्सान हुआ है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वर्धा ऋतु आने से पहले इन सड्कों को ठीक कर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, वर्षा से पहले सारी जरूरी सड़कें ठीक कर दी जायेगी।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि वर्षा तथा' बाढ़ के कारण 4,087 किलोमीटर सड़क खराब हुई हैं और उनकी रिपेअर करने के लिए भारत सरकार ने 17.50 करोड़ की मांगी गई राशि के विरुद्ध 4.50 करोड रुपये

उपलब्ध कराये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेनी सीजन से पहले इतनी लम्बी सड़कें पूरी हो जायेंगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः जो बहुत जरूरी सड़कें हैं वे ठीक हो जायेंगी लेकिन जिस पैमाने पर सारी सड़कें ठीक होनी चाहिएं, वैसा होना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री जय सिंह राणाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कौन सी सड़कें जरूरी हैं और कौन सी जरूरी नहीं हैं, इसका फैसला किस प्रकार किया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः जो सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं उनकी प्रायरिटी लैवल पर मुरम्मत की जायेगी।

श्री भाग मलः स्पीकर साहब, शाहबाद, बराड़ा, सढौरा और कालाआम वाली सलूक वहुत बुरी तरह से बरसात यन दिनों टूट गई है। इस सड़क पर सरावां के नजदीक काम लगा हुआ है, वहुत सारा काम अभी भी बाकी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उसे जल्दी से पूरा करवायेंगे? दूसरे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो तीन चार किलोमीटर का टुकडा वाइड होना है क्या उसे भी जल्दी चौड़ा करवायेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर सर, 1,240 रोडज डैमेज हुए थे। इनमें से 829 रोडज का काम मंजूर हुआ था जिनकी लम्बाई 1,801.32 किलोमीटर है। 189 रोडज का काम कम्पलीट हो गया है। जहां तक भागमल जी की सड्कों की

मुरम्मत फराने का सवाल है, वह तो सारी सड्कों की ही करवानी है लेकिन सड़कों को वाडड करने के बारे में अगले साल में विचार किया जायेगा।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बरसात के अन्दर जो सड़कें टूट गई हैं और जिन्हैं प्रायरिटी बेसिज पर बनाना है क्या वह लिस्ट बना ली है या बनाने जा रहैं हैं? यदि बना ली है तो किन सड़कों को पहले बनाने जा रहैं हैं ?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर सर, 20,360 किलोमीटर सड्कों की लम्बाई है जिनमें से 4,087 किलोमीटर सड़कें बरसात और फ्लड से डैमेज हुई हैं। मेरा प्रायरिटी पर बनाने का मतलब यह है कि जहां पर सड़कें बहुत ज्यादा टूटी हुई है या जहां पर कही उन्हैं रेज करने की आवश्यकता है वहां पर उन्हैं प्रायरिटी पर बनायेगे और जहां पर छोटे–मोटे पैचिज हैं उन पर काम बाद में होता रहैंगा।

श्री कैलाश चन्द शर्माः मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो 4,087 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें टूटी हुई हैं, इनमें से जिला महैंन्द्रगढ़ में कितने किलोमीटर की सड़कें टूटी हुई हैं और उनके लिए कितना रुपया दिया गया **श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः** स्पीकर साहब, महैंन्द्रगढ़ जिले में 94.53 किलोमीटर सड़कें डैमेज हुई हैं। (व्यवधान व शोर)

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ से जो सड़कें खराब हुई है, उनकी रिपेयर के लिये राज्य सरकार ने कितने पैसे प्रोवाइड किये हैं और विशेषकर फरीदाबाद जिले के लिये कितने पैसे रखे गये हैं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, फरीदाबाद जिले में 134.12 किलोमीटर सड़कें डैमेज हुई हैं। इन पर 31–1– 1989 तक 21.87 लाख रुपये का ऐक्सपैंडीचर हो चुका है।

श्री कैलाश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिला महैंन्द्रगढ़ की सड्कों की मुरम्मत के लिए कितनी राशि तय की गयी हैं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, पहले तो मैं यह क्लीयर कर दूं कि चार जिले, रोहतक, भिवानी, महैंन्द्रगढ़ और गुडगावां, बाढ़ग्रस्त जिले डिक्लेयर नहीं हुए हैं लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि महैंन्द्रगढ़ में रोडज की रिपेयर के लिये कितना पैसा निर्धारित किया गया है इसलिए मैं उनको बता देना चाहता हूं कि स्टेट ऐक्सचौकर से 2.43 लाख रुपया महैंन्द्रगढ़ जिले के लिये निर्धारित किया गया है।

Police recruitment in the State

***704. Shri Mangal Sein :** Will the Minister far Home be pleased to state whether the Government has taken any decision to conduct an enquiry into the police recruitment

madej durng the month of October 1988; if so, the details thereof ?

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : No. Sir.

श्री मंगल सैनः क्या गृह मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन दिनों पुलिस की भर्ती हुई थी, उस भर्ती की प्रक्रिया पर आदरणीय मुख्य मंत्री ने कोई टिप्पणी की थी?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, टिप्पणी हुई. थी और अखवारों में भी इस विषय में कुछ चर्चाए आयी थीं।

श्री मंगल सैनः आपने ठीक ही फरमाया कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने टिप्पणी की थी। अखबारों में यह भी टिप्पणी आयी थी कि एस० पी० महोदय से आरदणीय गृह मंत्री की टेलीफोन पर वार्ता हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो वार्ता हुई थी, क्या वह सही थी या गलत थी?

प्रो० सम्पत सिंहः जहां तक अखवारों में छपने की बात है और एस० पी० से बात करने का ताल्लुक है, कोई भी सिफारिश एस० पी० से टेलीफोन पर नहीं की गयी। अखबारों में ही ऐसी टिप्पणी थी, जो गलत थी। डाक्टर मंगल सैन जी के नोटिस में ठीक बात नही आयी।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, इस सम्बन्ध में अखबारों में खबर आयी थी और उस खबर में भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद के सम्बन्ध में भी छपा था। साथ ही यह भी छपा

था कि इसमें पैसे चले है। क्या मंत्री महोदय अखबारों में छपी बात का नोटिस लेते हैं और अगर लेते हैं तो क्या नोटिस लिया गया? दूसरे क्या कोई इस बारे में जांच की गयी और अगर नही की गयी तो क्यों नहीं की गयी?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अखबारों में जो भाई–भतीजावाद की और पैसे के लेन–देन की खबर आयी थी, वह बिल्कुल गलत थी। इसमें कोई सच्चाई नही थी। वहा पर कोई भाई–भतीजावाद नही चला और कोई पैसे का लेन–देन नहीं हुआ। ये सब खबरें गलत थी।

श्री मंगल सैनः गृह मंत्री महोदय ने ठीक ही फरमाया है कि आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कोई टिप्पणी की थी। क्या उस टिप्पणी के संदर्भ में मन्त्री महोदय उस भर्ती की जांच करवाने के लिये तैयार हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः उससे अगले दिन स्वयं मुख्य मन्त्री महोदय ने ध्यान दे दिया था कि मुझे जो गलतफहमी थी, वह दूर हो गयी है।

श्री महा सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस भर्ती में जिलावाइज संख्या क्या है और हल्का राई की क्या संख्या है ?'

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, भर्ती में हल्कावाइज संख्या नही हुआ करती।

श्री मंगल सैनः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास भर्ती के बारे में कोई शिकायत आई है और अगर आई है तो क्या उस शिकायत के बारे में जांच कराने को सरकार तैयार हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत नही आई है। अगर डा० मंगल सैन या कोई और आदरनीय सदस्य कोई शिकायत करेगा और बाकायदा सौलिड प्रूफ होंगे तो इंक्वायरी करवाएंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मन्त्री महोदय बनाने की कृपा करेंगे कि पिछले दिनों इसी सम्बन्ध में कुरुक्षेत्र के जो लड़के सिलैक्ट हुए थे उनके पेरैन्ट्स का डैपुटेशन मुख्य मन्त्री जी से मित्रा था और अगर मिला था तो उनकी क्या शिकायत थी और उस शिकायत को द्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, वहां का डेपुटेशन वाकायदा मिला था। यह डैपुटेशन मुख्य मन्त्री जी, मुझे और डी० जी० पी० को भी मित्रा था। उनकी यह शिकायत थी कि उनके लड़के रिक्रूटमैंट मे नही लिए गए। स्पीकर साहब, बात ऐसी है कि हमें फालतू लड़कों का सिलैक्शन करना पड़ता छै। यह मार्जिन इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि कोई लड़का मैडीकल में अनफिट हो जाए या पुलिस वैरीफिकेशन में अनफिट हो जाए। मुख्य मन्त्री जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि आइंदा

जो भी वेकैन्सी होंगी पहले उन लड़कों को लिया जाएगा। इसीलिए जी० आर० पी० की जो वेकैन्सी आई उनमें उनको पहले लिया गया।

श्री महा सिंहः क्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिक्रूटमैंट में जिलावाईज संख्या क्या है और राई थाने से कितने हुए हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह बताना पौसीबल नहीं है। सारे हरियाणा में साढ़े सत्ताईस हजार फोर्स है। थाने वाईज कितनी फोर्स है यह कराना मुश्किल है।

श्री अध्यक्षः आप जिला वाईज बता दें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक भर्ती का सवाल है वह हजारों की संख्या में भर्ती हुई है। अलग–अलग जिलों की टोटल स्टैरग्थ मैं नहीं बता सकता।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह माना है कि भर्ती में हुई अनियमितताओं के बारे मे अखबारों में छपा था। स्पीकर साहब, बाद में उसको डिनाई किया गया यह अलग बात है। मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि अगर इस के बारे में कोई शिकायत नोटिस में लाई जाएगी तो इंक्वायरी करवाई जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब,

Mr. Speaker : Not to be recorded.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः सरकार को अपनी पोजीशन क्लीयर करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के लिए तैयार रहना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आज हरियाणा के लोगों में भ्रम है। अतः दोनों द्रष्टि से क्या इसकी जांच कराने के आदेश सरकार देगी?

प्रो० सम्पत सिंहः सारे हरियाणा में कोई भ्रम नहीं है। मैंने कहा है कि जब कोई माननीय सदस्य वाकायदा प्रूफ के साथ शिकायत करेगा तो इंक्वायरी करवाई जाएगी। स्पीकर साहब, इनके. वक्त में क्या होता था वह मैं बता देता हूं। मैं मोड औफ रिक्रूटमैंट भी बता देता ह्न। सारी बात करीयर हो जाएगी।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ सबूत दे सकना हूं.....

Mr Speaker : Please do not give the proof to me. .Give the proof to the Government.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं रिक्रूटमैंट का तरीका बता देता है और पहले क्या होता था वह भी बता देता हूं।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः औन एर प्वायंट आफ आर्डर। मैं तो जनता की बात कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No point of order during question hour.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रह

.....

Mr Speaker : Nothing is to be recorded. Please take your seat.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं भर्ती का तरीका बता देता हूं। जो शक है वह दूर हो जाएगा। स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल की सरकार के आने के बाद भर्ती का जो तरीका है और पहले जो तरीका था वह मैं बता देता हूं। पहले यह होता था कि हर एस० पी० को चण्डीगढ़ से टेलीफोन जाता था कि इतने आदमियों की लिस्ट भेज रहा टू इनको सिलैक्ट करना है, पहले यह क्राइटेरिया था। लेकिन आज यह क्राईटेरिया है कि दो जिले जो नजदीक लगते पैं, जैसे हिसार और सिरसा या सोनीपत और रोहतक, उनके दो एस० पी० तथा एक डी० आई० जी० का एक बोर्ड बनाया जाता है। उसके अन्दर 5 फुट 7 इंच कद क्लीयर करना पड़ता है, 33–34½ इंच चौस्ट क्लीयर करनी पड़ती है, उमर और ऐजुकेशन की शर्तें क्लीयर करनी पड़ती हैं। फिर 1, 500 गज की दौड़ और सौ गज की दौड़ क्लीयर करनी पड़ती है। फिर लौंग जम्प और हाई जम्प क्लीयर करना पड़ता है तथा निर्धारित लिमिट तक गोला फैकना पड़ता है। स्पीकर साहब, इन शर्तों को जिन्होंने पूरा किया सिर्फ उन लड़कों को लिया गया।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, पुलिस भर्ती को ले करके एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छपा था कि माननीय गृहमन्त्री महोदय ने एक पुलिस अधिकारी को पुलिस भर्ती के सम्बन्ध में विशेष रूप से टेलीफोन पर कहा शै। यदि यह गश्त छपा था तो क्या उस अखबार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी और यदि यह ठीक छपा था तो गृह मन्त्री महोदय जी का टेलीफोन टेप हुआ होगा? यह एक बड़ा ही गम्भीर मसला है। इससे राज्य के लोगों का चिन्तित होना स्वामाविक है। वह टेलीफोन कैसे टेप हुआ? क्या वह राईट टू प्राईवेसी पर्टीकुलरली होम मिनिस्टर के सम्बन्ध में, विरुद्ध नहीं था? इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही हैं ?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, न तौ कोई टेलीफोन टेप हुआ है और न ही ऐसी कोई बात थी कि किसी एस० पी० को भर्ती के लिये कहा गया हो। इसके अलावा एक और बात मैं क्लीयर कर देना चाहता हूं कि हमारा जो भर्ती का स्टैण्डर्ड है, वह आर्मी तथा पैरा मिल्टरी फोर्सिज की भर्ती का जो हिन्दुस्तान में स्टैण्डर्ड है, उस से भी बढ़ कर है। सब से०पर का भर्ती का स्टैण्डर्ड हमारे हरियाणा प्रदेश ने रखा है।

Mr Speaker : Very good.

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक गृहमन्त्री महोदय ने बड़ी साफ बात कही है और यह बड़े सन्तोष का विषय है कि भर्ती में कोई अनियमितताएं नहीं हुई हैं। इन्होंने बताया कि

भर्ती का हमारा स्टैण्डर्ड आर्मी की भर्ती या पैरा मिल्टरी फोर्सिज की भर्ती के स्टैण्डर्ड से भी०पर का है। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस अखबार में इस तरह की खबर छपी है, जैसाकि भाई रघु यादव जी ने कहा है, क्या उस अखबार के खिलाफ आपने कोई केस किया णै? उसने गल्त क्यों छापा जबकि कोई टेलीफोन किया ही नही गया। दूसरी बात इन्होंने नौर्मज के बारे में बतायी है। क्या इनके पारा उनको वायलेट करने की कोई शिकायत आई है?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह): नहीं जी, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। जहां तक अखबार को सू करने का सवाल है, इस बारे में मैं यह कह सकता हू कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार फ्रीडम औफ दी प्रैस पर पूरा विश्वास रखती है। इस तरह की खबरें छपती ही रहती हैं। इस तरह से हम अखबारों को सू नहीं करते।

Veterinary Hospital, Cohana

***692. Chaudhri Kishan Singh Sangwan :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be peased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the present building of Veterinary Hospital at Gohana is in a dilapidated condition ;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building

of Veterinary Hospital there; and

(c) whether there is also any proposal under consideration of the Government to auction the present building; if so the time by which it is likely to be auctioned ?

पशु पालन राज्य मन्त्री (श्री अजमत खां):

(क) जी हां।

(ख) जी हां, गोहाना के किसी अन्य स्थान पर।

(ग) जी हां, जितनी जल्दी सम्भव हो।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री' महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस में यह बान है कि जगाधरी का जो वैटरिनरी हस्पताल है, उसकी हालत बहुत खराब है?

श्री अजमत खां: स्पीकर सर, यह सवाल 'तो गोहाना, सोनीपत, जिले से ताल्लुक रखता है। इसके लिये सैपरेट नोटिस दें तो हम इनको बता देंगे।

Opening of Treasury at Israna

***683. Chaudhri Satbir Singh Kadian :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a 'Treasury at Israna in District Karnal ; and

(b) if so; the time by which the aforesaid Treasury is likely to be opened ?

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(ए) हां, जी।

(बी) ईसराना, जिला करनाल में नया उप खजाना खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस उप खुजाने को खोलने के लिये सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं, सिवाय इसके कि इस पर उप खजाने के सरकारी लेन देन के कार्य को औरियण्टल बैक औफ कौमर्स की (राष्ट्रीयकृत बैक) शाखा के माध्यम से करवाने के लिये रिजर्व बैक औफ इंडिया की सहमति अभी तक अपेक्षित है। यह सहमति प्राप्त होने उपरांत इस स्थान पर नया उप खजाना खोल दिया जायेगा।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैंने पिछले साल भी यह सवाल पूछा था। अब मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस एक साल के दौरान रिजर्व बैक के साथ इनकी 'क्या कौरसपौंडैसं हुई और उनका क्या जवाब आया?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के बाद हमने यह प्रोग्रैस की है कि वहां पर मकान का प्रबन्ध कर दिया गया है। स्टाफ की नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है और हम रिजर्व बैक को रिमाइंडर भी दे चुके हैं। जैसे ही हमें उनकी सहमति मिलेगी हम उप–खजाना खोल देंगे।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, क्या वहां पर स्टेट बैक औफ इंडिया की दूसरी सबसिडियरी ब्रांच नहीं खोली जा सकती ताकि उप–खजाना जल्दी खुल सके?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बैक या उसकी शाखा खोलने का अधिकार हमें नहीं है। यह तो रिजर्व बैक के नौर्म्ज के मुताबिक खुलता है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं उप–मुख्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने भी अलेवा गांव में एक सब–ट्रेजरी खोलने का लिखित अनुरोध किया था। क्या उस पर कोई अमल किया गया है, अगर नहीं तो उसकी क्या शर्तें हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, उप–खजाना खोलने के लिए पहले तो परम्परा यह थी कि तहसील या उप–तहसील लैवल पर खोला जाता था लेकिन हमने इसको कुछ लिबरल कर दिया है। अब चाहें तहसील हो, उप–तहसील हो या इससे नीचे और जगह हो अगर वहां पर लेन देन काफी हो और वहां की जनता को दूर जाना पड़ता हो तो वहां उप–खजाना खोल दिया जाता है। वर्क लोड देख लिया जाता है कि कितना है। अलेवा के बारे में ऐग्जामिन किया जा रहा है। अगर वहां पर वर्क लोड होगा तो वहां पर भी उप–खजाना खोल दिया जाएगा।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि मतलौडा में कब तक उप–खजाना खोल दिया जाएगा? इसके अलावा इसराना में उप–खजाना न खोलने की वजह से पिछले दो साल से रैवेन्यू का कितना नुक्सान हुआ है क्योंकि वह उप–तहसील भी है और वहां पर मंडी भी हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इसमें लौस वाली बात नहीं है, लोगों को तकलीफ हो सकती है दूर आने जाने की। जहां तक मतलौडा की पोजीशन का सवाल है उसकी पोजीशन भी इसराना वाली ही है। मैं यह भी बता दूं कि सारे हरियाणा प्रदेश में पांच स्थान ऐसे हैं जहां पर उप–खजाने खोलने विचाराधीन हैं। ये स्थान हैं भिवानी में बाढडा, महैंन्द्रगढ़ में अटेली, नीसिंग, इसराना और मतलौडा करनाल में। इनके बारे रिजर्व बैक औफ इंडिया की सहमति के बारे में लिखा हुआ है। उनकी सहमति आते ही इन स्थानों पर उप–खजाने खोल दिए जाएंगे।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र सारा ग्रामीण है और उसमें बबैन एक ऐसी जगह है जिसके आस पास सैकड़ों गांव लगते हैं। क्या वहां पर भी उप–खजाना खोलेंगे?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रस्ताव भेजें। हम उसको ऐग्जामिन करवा लेग। अगर जरूरत समझी जाएगी तो वहां भी जरूर खोलेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 818

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नही थे।

Oil Refinery, Karnal

***800. @Seth Lachhman Dass Bajaj and Shri Harnam Singh and Shri Raghu Yadav :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether the construction work of Karnal Oil Refinary has been started; if so, since when togetherwith present stage of construction. ?

उद्योग मन्त्री (डा० किरपा राम पुनिया): जी नही।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, वहुत से गांवों के जमींदारों को उजाड़ने के बाद भी उस रिफाइनरी को बनाने का– काम शुरू नही किया गया है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिफाइनरी को बनाने का काम शुरू न करने के क्या कारण हैं और उसको बनाने का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह क्वैश्चन पिछले सैशन में भी पूछा गया था। उस वक्त भी मैंने काफी

विस्तार से इस बारे में बताया था। यह प्रोजैक्ट हमारी स्टेट के लिए बड़ा अहम प्रोजैक्ट है लेकिन गवर्नमैंट औफ इंडिया इस प्रोजैक्ट को इम्पलीमैंट करने में वहुत ढील कर रही है। हमने गवर्नमैंट औफ इंडिया के साथ कई बार यह मामला टेक अप किया है, फिर भी इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस प्रोजैक्ट को बनाने का काम तो गवर्नमैंट औफ इंडिया ने ही करना है, हम तो केवल उनसे रिक्वैस्ट ही कर सकते हैं लेकिन गवर्नमैंट औफ इंडिया ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेन सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा है ''नो सर''। लेकिन सप्लीमैंटरी के जवाब में मंत्री जी ने फरमाया है कि यह गवर्नमैंट औफ इंडिया का प्रोजैक्ट है, इसका काम तो गवर्नमैंट औफ इंडिया ने ही करना है, हम तो केवल उनसे रिक्वैस्ट ही कर सकते हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रोजैक्ट का काम शुरू करवाने के बारे में मंत्री जी की मुलाकात केन्द्र में इस महकमे के मंत्री के साथ हुई, अगर हुई तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में केन्द्र में इस महकमें के मंत्री के साथ इनकी कोई खतो– किताबत हुई?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, उनके साथ कई बार खतो–किताबत हुई है। जिस समय हमारी पार्टी पावर में आई तो हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जी ने 4

सितम्बर, 1987 को प्रधान मन्त्री को सीधा डी० ओ० लैटर लिखा था। उसका जवाब पैट्रोलियम मिनिस्टर श्री ब्रह्मदत्त ने 27–10–1987 को दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट का काम जल्दी ही शुरू करवाया जाएगा। हमने एक साल तक उसका इन्तजार किया लेकिर उन्होंने काम शुरू नही करवाया। उसके बाद फिर हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जो ने 27–9– 1988 को एक और डी० ओ० लैटर लिखा कि इस प्रोजैक्ट का काम जल्दी शुरू करवाया जाए। उसका जवाब 27– 12– 1988 को आया कि इस प्रोजैक्ट की डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट को चूंकि फिर स्टडी करवा ने हैं इसलिए इसमें समय लगने की सम्भावना है। उसके बाद हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने 2– 1– 1989 को प्लानिंग कमीशन के मैम्बर से मुलाकात की और कहा कि इस प्रोजैक्ट के काम में बहुत विलम्ब हो रहा है, इसको आप जल्दी शुरू करवाएं लेकिन उन्होंने भी जवाब दिया कि वे चूंकि इसकी डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट क्रो दोबारा स्टडी करवा रहैं हैं इसलिए इसमें समय लगेगा। पिछले दिनों प्लानिंग कमीशन के मैम्बर श्री आबिद हुसैन यहां पर आए थे। उनके साथ मेरी और आदरणीय मुख्य मन्त्री जी की बात हुई थी। मुख्य मन्त्री जी ने उनको कहा था कि आप इस प्रोजैक्ट का काम जल्दी शुरू करवाएं। मैंने खुद भी उनसे पिछले महीने की 19 तारीख को मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि आप अपनी गुड औफिसिज का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजैक्ट का काम जल्दी शुरू करवाएं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, केन्द्रीय पैट्रोलियम मिनिस्टर ने इनको जवाब दिया है कि इस प्रोजैक्ट का काम शुरू होने में समय लगने की सम्भावना है क्योंकि इसकी डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट फिर स्टडी करवाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 1987 से पहले की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रोजैक्ट की डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट कब ली थी?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इस प्रोजैक्ट की डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट 1982 में तैयार की गई थी। आप सबको मालूम है कि हरियाणा विधान सभा के चुनावों से कुछ दिन पहले यानी 30 मार्च, 1987 को प्रधान मन्त्री ने इस प्रोजैक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। उसके बाद उन्होंने इसको इम्पलीमैंट करने के लिए कार्यवाही शुरू करनी थी लेकिन कोई काम नही किया गया केवल वहां पर 2 हजार 80 एकड़ जमीन ऐक्वायर कर ली गई। उसका चार करोड़ और कुछ रुपया कम्पनसेशन का दिया गया। स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से जो छोटी–छोटी फारमैलिटीज मुकम्मल करनी थी, जैसे वाटर पोल्यूशन बोर्ड की, इन्वायरमेंट की, क्लीयरेंस देने की, वह पूरी कर ली गई थी। फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद 22 मई, 1987 को उन्होंने इंडियन आयल कार्पोरेशन और टाटा कैमिकल लिमिटिड के साथ मैमोरैंडम औफ अण्डरस्टैडिंग साइन कर लिया जिसके तहत एक नई कम्पनी का गठन करना था जिसका नाम टाटा आयल

रिफायनरी होना था। वह कम्पनी गठन करने का फैसला तो हो गया लेकिन वह गठित नही की गई। हमें पता चला हैं कि शायद इंडियन आयल कार्पोरेशन और टाटा कैमिकल लिमिटिड दोनों मिल कर इस प्रोजैक्ट का काम शुरू करने के बारे में पुनर्विचार कर रहैं हैं।

10.00 बजे।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अभी दों–चार रोज पहले केन्द्रीय कृषि मन्त्री का अखबारों में एक व्यान करनाल में पंजाबी सम्मेलन में बोलते हुए छपा है कि मैंने अबोहर–फाजिल्का लिए बगैर चण्डीगढ़ छोड़ने से इन्कार कर दिया था और प्रधान मन्त्री की बात नहीं मानी थी जिस कारण मेरे को मुख्य मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधान मन्त्री का रवैया हरियाणा के प्रति भेदभाव का है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसी ऐन्टी हरियाणा एटिच्यूड होने की वजह से ही तो यह तेल शोधक कारखाना लगाने में डिले नहीं की जा रही?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, मुझे यह समझ नहीं आया कि इनकी इस बात का इस सवाल के साथ क्या सम्बन्ध है?

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से बताया है कि इस प्रोजैक्ट की मैमोरेन्डम औफ

अन्डरस्टैण्डिग मई, 1987 में तैयार हो गई थी और अब उनकी जानकारी के मुताबिक इस काम को पैट्रोलियम डिपार्टमैंट और टाटा वाले मिल कर करने की योजना बना रहैं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या यह डिले जानबूझकर तो नहीं की जा रही और अगर यह डिले जानबूझकर की जा रही है तो क्या इसके लिए हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के साथ कोई प्रोटैस्ट किया है कि इस तेल शोधक कारखाने को लगाने में डिले क्यो की जा रही है?

डा० किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, यह उनकी बिल्कुल डिलेइंग टैक्टिक्स हैं क्योंकि पुराने शिड्यूल के मुताबिक यह प्रोजैक्ट मई, 1992 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय., पिछले साल अगस्त के महीने में भी इस तेल शोधक कारखाने के बारे में सवाल पूछा गया था। उस वक्त मैंने कहा था कि अब तक की प्रोग्रैस के मुताबिक यह प्रोजैक्ट 3 साल डिले हो गया है और अव तकरीबन एक साल और निकल गया है। इस प्रकार यह प्रोजैक्ट अब तीन–साढ़े तीन साल डिले हो चुका है। इस डिले के बारे मे बहुत बार अखबारों में भी आया है और मुख्य मंत्री जी ने भी अपने पत्रों में लिखा है कि इस प्रोजैक्ट को डिले क्यो किया जा रहा है। मैं अपने आदरणीय साथियों की सूचना के लिए बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार जिस तरह से एस० वाई० एल० नहर के मामले को डिले कर रही है उसी प्रकार से इस मामले में भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब हमारी प्लानिंग कमीशन के साथ अगली प्लान के बारे में डिस्कशन हो रही थी तो उस समय हमारे उद्योग मन्त्री उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। उस डिस्कशन के दौरान हमने इस प्रश्न को उठाया था कि क्यों नहीं इस प्रोजैक्ट को शिड्यूल के मुताबिक लगाया जा रहा? अध्यक्ष महोदय, उस समय उन्होंने हमें यह बतलाया कि अभी इस कारखाने की फिजिबिलिटी वर्क आउट की जा रही है, आया इस कारखाने को यहां पर लगाना फिजिबल है भी या नहीं। इस बात पर हमने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। उस मीटिंग में प्ल–निंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन श्री सोलंकी हैं, वे भी थे। हमने सोलंकी साहब को कहा कि आप एक प्रदेश के मुख्य मंडी रहें हैं और आपको पता है कि जब किसी प्रोजैक्ट का फाउंडेशन ले हो जाये तो क्या उसके बाद भी उसकी फिजिबिलिटी वर्क आउट की जा सकती है? हमने यह भी कहा कि किसी प्रोजैक्ट की फिजिबिलिटी वर्क आउट होने के बाद ही प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री उस प्रोजैक्ट का शिल्यान्यास करने हैं। इस प्रोजैक्ट की पहले ही सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। फिर हमने कहा कि आज ऐसी कौन सी स्टेज है कि अब फिर इस कारखाने के लगाये जाने के बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करें। हमने यह भी कहा कि हमें सन्देह होता है कि जिस प्रकार से हरियाणा से कोच फैक्टरी शिफ्ट करके दूसरे प्रदेश में ले गए शायद उसी प्रकार से इस कारखाने को किसी और स्थान पर ले

जाना चाहते हो। हमारे बार बार सन्देह करने के बाद भी उन्होंने एक बार भी सहमति व्यक्त नहीं की और न ही यह कहा कि इस तेल शोधक कारखाने को समय पर लगाया जायेगा। वे अपनी ही बात पर अड़े रहैं। अध्यक्ष महोदय, पैट्रोलियम विभाग में एक औफिसर ऐडवाइजर के तौर पर काम कर रहैं हैं। मैं उस औफिसर का नाम नही जानता। वे हमारेको यह कन्वीन्स कराने के लिए हरियाणा भवन तक आये कि यह राष्ट्र के हित में नही है कि वाहर से क्रूड आयल आये और वह हिन्दुस्तान में रिफाइन हो। इससे खर्चा ज्यादा बढ़ेगा और राष्ट्र का नुक्सान होगा। मुख्य मन्त्री जी ने उसको डांटकर कहा कि हम यह बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नही हैं। हम इस बात के लिए पूरी तरह से जोर लगाएंगे कि यह कारखाना यहीं लगाया जाए। यदि यह कारखाना आप यहां नहीं लगायेगे तो हम इसके लिए पूरे देश के अन्दर आन्दोलन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि उद्योग मन्त्री जी को पता है कि यह विलम्ब करने की इनकी चाल है और केन्द्र जानबूझकर देर कर रहा है। जैसे एस० वाई० एल० नहर के काम को ही ले लीजिए, जिस तेज गति से वहां काम चलना चाहिए था वह नही चल रहा है। ये लोग वही हथकंडे इस काम में भी अपना रहैं हैं।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अमी उप मुख्य मन्त्री महोदय जी ने यह बताया है कि प्लानिंग कमीशन की बैठक में वे गये थे और उसमें उद्योग मंत्री श्री पुनिया साहब, शामिल नहीं थे।

इनकी प्लानिंग कमीशन के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा है कि चौधरी देवी लाल जी ने प्लानिंग कमीशन के ऐडवाईजर को कहा था कि यदि वे इस प्रोजैक्ट को डिले करेंगे तो हम आन्दोलन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा उप–मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस आन्दोलन की रूप–रेखा क्या होगी, जरा यह भी बता दीजिए?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अभी यह स्टेज आई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब आन्दोलन होगा तो वह डाक्टर साहब के साथ मिल कर ही करना है। (विघन)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक सप्लीमेंटरी करने का मौका दीजिए। मैं कई बार प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्षः नहीं, महैंन्द्र प्रताप जी, आप प्लीज बैठें।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, पता नहीं मुझे आप क्यों बोलने नहीं दे रहैं हैं? रेशो परपोर्शन के हिसाव से भी तो मुझे प्रश्न पूछने दीजिए।

Mr. Speaker : No, no. Please take your seat. This question has already taken about 15 minutes.

Chaudhri Mahender Partap Singh : Speaker Sit

* * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. यदि रेशों

परपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका नम्बर चौथे दिन आता है जा कि आपको रोज ही बोलने का मौका दिया जाता है। इस सवाल पर 15 मिनट से ज्यादा समये से सप्लीमैंटरी पूछे जा रहैं है।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, whatever Mr. Mahender Partap Singh has said is highly objectionable. It is a reflection on the Hon'ble Speaker which is intolerable. Sir, it should be expunged.

Mr. Speaker : I have already ordered that it should not be recorded. Next question please.

Degree College at Cannaur

***734. Shri Ved Singh Malik :** Will the Minister for Education be please to state wh ether there is any proposal under consideration of the Government to open a Co-educational Government Degree College at Ganaur in District Sonepat; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized.

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): हां जी, प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विचार किया जायेगा।

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जमीन ऐक्वायर करने के लिए इन्होंने क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, अभी जमीन ऐक्वायर करने की कार्यवाही नहीं की है। मैंने बताया कि अभी हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहैं हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इसके लिए इसका निरीक्षण करवाया जा रहा है।

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री साहिबा से जानना चाहूंगा कि डिग्री कालेज खोलने का क्या क्राईटेरिया है तथा अगर हम इनकी सभी शर्तें पूरी कर दें तो क्या तरावड़ी में भी कालेज खोलने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, कालेज खोलने के लिए कोई लिखित और तयशुदा आधार नहीं है। आमतौर पर जिन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता हए वे ये हैं कि उस इलाके की मांग क्या है, वहां के स्थानीय लोगों से हमें क्या सहायता मिलेगी, हमारे पास कितने फण्डज अवेलेबल हैं और भूमि कितनी अवेलेबल है। इन चार पांच बातों को ध्यान में रख कर क्राईटेरिया बनाया जाता है। अगर ये तरावड़ी में कालेज खोलना चाहते हैं तो इन तमाम चीजों का ब्योरा देते हुए हमारे पास प्रस्ताव भिजवा दें, हम जरूर इसका निरीक्षण करेंगे।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सोनीपत मे जो डिग्री कालेज खोला जा रहा है, वह सोनीपत शहर में खोला जा रहा है या गन्नौर हल्के में?

श्रीमती सुषमा स्वराजः यह सोनीपत का नहीं बल्कि गन्नौर का प्रस्ताव है और मैंने स्पैसिफिक जवाब गन्नौर के लिट दिया है।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या करनाल में बी० ए० बी० एड०, ओ० टी० या जे० बी० टी० की कोई ट्रेनिंग क्लासिज स्टार्ट करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, बी० ए० बी० एड० का तो कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही हमारे पास इसके लिए कोई प्रावधान है। ओ० टी० के बारे में मैंने परसों एक सवाल के जवाब में बताया था कि डाईट हम हर जिले में खोल रहैं हैं और इसमें ओ० टी० और जे० बी० टी० दोनों का प्रावधान होगा। यह इन्स्टीच्यूशन करनाल में भी खोजा जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार फरीदाबाद जिले मैं कोई सह शिक्षा और विशेष कर लड़कियों के लिए डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी क्योंकि वहां कोई गवर्नमैंट गर्ल्ज कालेज नहीं है? साथ ही हमारे यहां जमीन भी उपलब्ध गै, फण्डज भी दे सकते हैं अर्थात् सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं। क्या वहां पर गर्ल्ज कालेज खोलने को विचार है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः सारे जिले के लिटरेसी रेट को देख कर कालेज खोला जाता है। फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ से मांग आयी है, उस का हम निरीक्षण कर रहें हैं।

श्री कैलाश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, जिना महैंन्द्रगढ़ में अटेली और नांगल चौधरी में प्राईवेट कालेजिज हैं। उन कालेजिज में अव्यवस्था और अनियमिततायें हैं। क्या उन कालेजिज को टेक–ओवर करने पर सरकार विचार कर रही है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगली पंचवर्षीय योजना के तहत किन किन जिलों में कालेज खोलने का विचार है और क्या गुंडगावा में भी खोलने का विचार है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल किये हैं। उनका दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार गुडगावा में कालेज खोलने के लिए विचार कर रही है? वहां से महिला कालेज खोलने की मांग आयी है, हम निरीक्षण कर रहें हैं। इन्होंने यह भी पूछा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने कालेज खोलने का विचार है? अभी तो आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह बनी नहीं है लेकिन सातवीं योजना में पांच कालेजिज खोलने का प्रावधान था और हमारी कोशिश यह है कि आठवी पंचवर्षीय योजना में पांच से ज्यादा खोलेगे। जहां तक सारे प्रदेश का सवाल है, इस समय तेरह कालेजिज के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिनका हम निरीक्षण कर रहें हैं। इनमें अलग अलग जिले के कालेजिज शामिल हैं। उनके सवाल का दूसरा खण्ड यह

था कि क्या अटेली और नांगल चौधरी के कालेजिज को टेक–ओवर करने के बारे में विचार रहैं हैं या नही? अध्यक्ष महोदय, टेकिंग ओवर का बाकायदा कानून बना हुआ है। हमारे यहां टेकिंग ओवर मैनेजमैंट सैल है, उसमें शिकायत आती है तो वहां से निरीक्षण करवाते हैं कि वहां पर कितनी अनियमितताये, या मिस–मैनेजमैंट है। आप वहां से शिकायत भिजवाये, उस शिकायत पर इन्कवायरी होगी, उसके बाद शो–काज नोटिस दिया जायेगा। उसके बाद अगर हम को लगता है कि यह मैनेजमैंट कालेज नहीं चला सकता तो हम टेक–ओवर करते हैं। ऐसी अनियमिततायें हैं तो हमारे पास शिकायतें भिजवाइये। हम उनका निरीक्षण करवायेगे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने फरमाया कि बल्लभगढ से मांग आयी है कि वहां पर लड़कियों के लिए गवर्नमैंट कालेज खोला जाये। नैं आपके माध्यम से पूछना चाहचा हूं कि तीन साल पहले गवर्नमैंट कालेज में गर्ल्ज विंग के तौर पर क्लासिज चालू की गई थीं, क्या उस कालेज में इस सैशन में या नैक्सट सैशन में कुन फलैज्ड कालेज चालू किया जायेगा क्योंकि वहां पर कालेज खोलना अति आवश्यक है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः यह प्रस्ताव विचाराधीन है। अगले सैशन में या इसमें कर देंगे या नहीं कर देंगे जवाब अभी नहीं दे सकती लेकिन यह प्रस्ताव आया है, हम इस पर विचार कर रहैं हैं।

श्री भागी रामः मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जो 13 कालेजिज हरियाणा स्टेट में खोलने के बारे में निरीक्षण किया जा रहा है, उसमें क्या ऐलनाबाद की मांग भी शामिल है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः जी हां, उसमें बिल्कुल शामिल है। अगर माननीय सदस्यों को सभी कालेजिज की जगह पूछने की अधिक जिज्ञासा है तो मैं उनके नाम पढ़ देती हूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सनी 13 के बारे में बता दें कि कहां–कहां खोलने जा रहैं हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराजः गुडगावां जिले में कन्या महाविद्यालय, फरीदाबाद जिले में बल्लबगढ़ में, भिवानी जिले में तोशाम और जुई में, करनाल जिले में असंध में, सोनीपत जिले में गन्नौर में, सिरसा जिले मैं ऐलनाबाद में, सिरसा जिले में मंडी कालांवाली में, रोहतक जिले में सांपला में, महैंन्द्रगढ़ जिले में सहलंग में, सिरसा जिले में नाथूसरी चौपटा में, करनाल जिले में इन्द्री में और महैंन्द्रगढ में कन्या महाविद्यालय खोलने के बारे में निरीक्षण कर रहैं हैं। इस प्रकार से ये 13 कालेजिज हैं।

श्री योगेश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सन् 1989–90 में बल्लभगढ़ में विमैन या को–ऐजूकेशन कालेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, 1989–90 में बिल्कुल विचार है लेकिन वह ताउडू और मंडी डबवाली के लिये ऐप्रूव हुए हैं। बल्लभगढ में नहीं खोला जायेगा।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हथीन के पिछड़ेपन और मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के पास पड़े फन्डज को ध्यान में रखते हुए क्या वहां पर कोई कालेज बनाया जायेगा क्योंकि दूसरे जिलों में दो–दो कालेज खोलने की स्वीकृति इन्होंने दी है। क्या ऐसी कोई प्रोपोजल फरीदाबाद के लिये भी बनायेंगे ताकि हथीन में भी गर्ल्ज कालेज खोला जा सके।

श्रीमती सुषमा स्वराजः हथीन से प्रस्ताव आया था लेकिन वह रद्द कर दिया गया। वह इसलिये रद्द किया गया क्योंकि वहां पर लैड और बिल्डिंग की नौन–अवेर्लीबलिटी थी। अगर माननीय सदस्य लैड और बिल्डिंग के लिये कोई व्यवस्था करवा दें तो हम इस प्रस्ताव का पुनः निरीक्षण करवा सकते हैं।

Cases referred to Anti-corruption Board

***743. @Shri Raghu Yadav and Comrade Harpal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases, if any, referred to Anti-Corruption Board for enquiry/investigation during the period from the constitution of Board to-date togetherwith the details of cases and the charges levelled in each case;

(b) the number of the cases, out of those referred to in part (a) above, in which action has been taken on the basis of the en**qu**iry conducted by the said Board togetherwith the details thereof; and

(c) the number of cases still pending for enquiries/investigations with the said Board togetherwith the period since when these are pending ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : The requisite information is laid on the Table of the House.

Information

(a) 172 enquiries were instituted by the Anti-Corruption Board from the date of its constitution i.e. 22-9-1987 to 10-1-1989. It is not in public interest to give the details of all these cases including thc allegations levelled in each case.

(b) 145 enquiries out of those referred to in part (a) above have been completed. Qf these 2 enquiries have been sent to the Administrative Departments concerned for taking necessary departmental action against the delinquent officers/officials, 7 cases were sent to the Administrative Departments concerned for suitable action. In 3 cases, criminal cases were registered against the delinquent officers/ officials and 133 cases were filed.

(c) 27 cases are still pending with the Anti-Corruption Board for enquiries/investigations. Of these 11 cases are over 6 months old, 6 cases are over 3 months old

and 10 cases are less than 3 months old,

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह सूचित किया है कि 172 मामले भ्रष्टाचार उन्मूलन बोर्ड को जांच के लिये दिये गये थे। उनमें से 145 मामलों में जांच पूरी हो गयी है और 12 केसिज में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गयी है। इनमें से 3 केसिज में एफ० आई० आर० लौज हो गयी है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि यह एफ० आई० आर्ज० किन–किन आरोपों में लौज की गयी हैं और किन–किन अधिकारियों के खिलाफ लीन की गयी

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, तीन एफ० आई० आर० दर्ज हुई हैं। इनमें से एक एफ० आई० आर० तो अन्डर इन्वैस्टीगेशन है। दो एफ० आई० आर० का चलान पुट–अप किया जा चुका है। एक एफ० आई० आर० नं० 171 अन्डर सैक्शन 409, 468 और 471 आई० पी० सी० पुलिस स्टेशन यमुना नगर में लौंज को गई एं। इसमें ऐक्यूज्ड हैं, कैलाश चन्द्र कालरा, क्लर्क और सतीश कुमार, औडिट क्लर्क। दूसरी एफ० आई० आर० है नं० 268 डेटिड 12– 12– 1988 अन्डर सैक्शन 52 प्रिवैंशन आफ कुरप्शन ऐक्ट और सैक्शन 165 आई पी० सी०। ऐक्पूज्ड हैं, श्री दलीप सिंह, ड्राईवर हरियाणा रोडवेज, डिपो हिसार।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन–जिन अधिकारियो/कर्मचारियो के०पर यह आरोप लगाये गये हैं, उनमें कैटेगरीवाईज यानी फर्स्ट

क्लास, सैकिण्ड क्लास और क्लास–थ्री के कितने अफसर व कर्मचारी हैं और उनके खिलाफ क्या चार्जिज हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरे पास फर्स्ट क्लास, सैकिगड क्लास और क्लास–थी की इन्फर्मेशन कैटेगरीवाईज तो नहीं है। हां गजटिड और नौन–गजटिड की है। गजटिड 63, नौन–गजटिड 62, प्राइवेट पर्सन 12, एम० एल० ए० 1 और नौन–औफीशियल 1 हैं जिनके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि हरियाणा को जनता को इस भ्रष्टाचार उन्मूलन बोर्ड के बनने से क्या कोई विशेष लाम हुआ है और दूसरे यह कि क्या ऐसा कोई बौर्ड पहली सरकार ने भी बनाया था या इसा सरकार ने बनाया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मौजूदा सरकार के नेता चौधरी देवी लाल का तो यह नारा है कि ''भ्रष्टाचार बन्द और बिजली–पानी का प्रबन्ध''। नारे का जो पहना पार्ठ है, उसको अमली जामा पहनाने के लिये ऐन्टी कुरप्शन बोर्ड बनाया गया है। पिछली सरकार का तो चूंकि विपरीत नारा था इसलिये उन्होंने यह बोर्ड किस लिये वनानी था ? वे तो पैसा खींचते थे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने यह फरमाया हैं कि 172 इन्कवायरियां हुई हैं जिनमें से 145 कम्पलीट हो गयी हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जौ 145

इन्क्वारीज कम्पलीट हो गयी हैं, वे फाईल कर दी गयी है या किसी के खिलाफ केसिज भी दर्ज हुए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डा० साहब, इसमें सब कुछ लिखा है। अगर आप जवाब ध्यान से पढ़ें तो इसमें सब लिखा है कि फाइल कितने केसिज हुए, एफ० आई० आर० कितने के बारे में दर्ज हुई और डिपार्टमैंट को क्या लिखकर भेजा। Everything has been reduced in writing in the reply.

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि इतने औफिसर्ज गजटिड और इतने नौन–गजटिड थे। साथ में इन्होंने एक एम० एल० ए० का भी जिक्र किया। सारे सदस्य उस एम० एल० ए० का नाम जानने के इच्छुक होंगे कि वह कौन मैम्बर है? अगर कोई एतराज न हो तो क्या मन्त्री महोदय उस एम० एल० ए० का नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, एम० एल० ए० साहब वाली कम्पलेंट फाल्स पाई गई है और वह केस फाइल कर दिया गया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि आदरणीय चौधरी देवी लाल ने भ्रष्टाचार बाद करने का नारा दिया था और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ऐन्टी कुरप्शन बोर्ड की स्थापना की लेकिन जन प्रतिनिधियों, मन्त्रियों और मुख्य मन्त्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहैं हैं और अब भी लगते हैं।

इसलिए विशेष रूप से पब्लिक में इमेज ठीक करने के लिए लोकायुक्त नियुक्त करने में क्या आपत्ति है? क्या मन्त्री महोदय लोकायुक्त अप्वायंट करने के बारे में विचार करेंगे?

Mr. Speaker : This question is not rclevant.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन बोर्ड बनाया था और उसके जो पहले सचिव थे उन्होने एक जगह कहा था कि हरियाणा से भ्रष्टाचार बन्द नही हो सकता। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने यह बात किस परिस्थिति में कही थी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यादव जी पत्रकार हैं यह बात उन्हीं से पूछ लें।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह बोर्ड हरियाणा सरकार ने बनाया थी और उसका सचिव सरकार ने अप्वायंट किया था। वे कहते हैं कि हरियाणा के अन्दर भ्रष्टाचार बन्द नही हो सकता। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह यह बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मन्त्री महोदय ने कह दिया कि यादव जी उनसे जाकर पूछ लें कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यो कहा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुझे इसका ज्ञान नही है किं उन्होंने कहो कहा और क्यों कहा। मैं इस बारे में क्या बता सकता हूं।

Construction of Roads to Link Neighbouring States

***762. Shri Kailash Chand Sharma :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to construct new roads for linking the neigh bouring States;

(b) if so, the number of such roads which link the Rajasthan boundary in district Mohindergarh; and

(c) whether any new road has been constructed to link Rajasthan boundary, as referred to in part (b) above, during the year 1988-89 ?

Public Works Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj) :

(a) Yes.

(b) Five roads.

(c) One Interstate road to Rajasthan boundary in Mohindergarh district has been constructed during 1988-89.

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह गिरना रहता है कि मैं सवाल के जवाब में हां नही कहता लेकिन मैंने हां कह दी है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने आज पहली बार हां कहा है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हू।

क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जो पांच सड़कें इन्होंने बताई हैं वे कौन सी हैं और उनकी लम्बाई कितनी–कितनी है?

श्री ओम प्रकाश भारदाजः स्पीकर साहब, ये रोडज है–ढाना से राजस्थान बोर्डर जिसकी लम्बाई 0.60 किलोमीटर है। दूसरी सड़क रामबास से गोरिर जिसकी लम्बाई 0. 81 किलोमीटर है और तीसरी सड़क है खडेरवा से सिरयानी जिसकी लम्बाई 1.55 किलोमीटर है। स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री कैलाश चन्द शर्मा ने रिक्वैस्ट की थी कि उनकी दो सड़कें और मन्जूर की जाएं। वे दोनों सड़कें विचाराधीन है और इन पर काफी गौर किया गया है और इनकी मन्जूरी दे दी जाएगी। ये सड़कें है बयाल से राजस्थान बोर्डर और दूसरी सड़क नांगल चौधरी गोहतरी रोड से गांव तसिंग राजस्थान बोर्डर तक।

श्री कैलाश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो सड़कें इन्होंने बतायी हैं क्या वे अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएंगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, भगवान खैर रखे तो शायद इससे भी जल्दी ही बना देंगे।

Construction of Cremation ground at Panchkula

***874. Shri Kanti Parkash Bhalla :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred for the construction of cremation ground in Sector 19 of Panchkula; and

(b) whether it is a fact that said cremation ground has been closed at present; if so, the reasons thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) The total expenditure incurred for the construction of cremation ground in Sector-19, Urban Estate, Panchkula is Rs. 10.90 lacs.

(b) Yes, it is a fact tht the said cremation ground has been closed at present and this has been done as its close proximity to a residential colony of Housing Board in Sector-19, Urban Estate, Panchkula was objectionable.

श्री कान्ति प्रकाश भल्लाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू कि जिन अफसरान ने पंचकुला शहर के बीच में जहां दोनों जगहों पर आबादी थी, गलत जगह पर प्लान करके शमशान घाट बनाया है और जिसके कारण सरकार को लगभग 10 लाख रुपये का नुकसान भी हुआ है क्या उन अफसरान व प्लानर्ज के खिलाफ सरकार ऐक्शन लेने जा रही हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, यह क्रीमेशन ग्रांउड विभाग ने तो सोच समझ कर, सही ढंग से और सही जगह पर ही बनाया था लेकिन कुछ रैजीडैन्ट्स की तरफ से औज्जैकशन हुआ

और उस समय के मुख्य मन्त्री ने 1986 में यह आर्डर किये कि इस क्रीमेशन ग्राउंड को यहा से उठा लिया जाए। अफसरान या प्लानर्ज ने गल्त प्लान करके इसको बनाया, इस तरह की कोई शिकायत सरकार के यास नही है। रैजीडैन्ट्स ने इस का एतराज किया और मुख्य मन्त्री महोदय के आर्डरों से उसे क्रीमेशन ग्राउंड को वहां से उठा लिया गया।

Issuance of Pass-books to Farmers

***836. Shri Tek Chand :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under Consideration of the Government to issue Pass-books to the farmers regarding their land holdings in the State; and

(b) if so, the time by which the. said proposal is likely to be materialized ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) About one year since the draft bill will have to be referred to Govt. of India and again for the consideration of the President of India.

श्री टेक चन्द: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का इसमें क्या

दखल है जबकि लैन्ड होल्डिंग हरियाणा की है और पास बुक्स भी हम ही इशू करते हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, केन्द्र सरकार का इसमें दखल इसलिये है क्योंकि इसमें इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट और बैन्क्रस की इन्वौल्वमैन्ट है।

श्री हजार चन्दः अध्यक्ष महोदय, 1977 में भी इसी तरह की पास बुक्स किसानों को दी गई थीं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि वही पास बुक्स अब इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इससे पहले जो पास बुक्स इशू की गयी थीं उनमें सिर्फ उनकी जमीनों का ही ब्यौरा होता था लेकिन अब जो पास बुक्स इशू की जानी है उनमें बहुत सारी इम्प्रूवमैन्टस अन्डर कसिड्रेशन हैं?

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब ऐग्रीकलचर एक स्टेट सबजैक्ट है तो फिर यह मामला केन्द्र को रैफर करने की क्या आवश्यकता थी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जैसाकि मैंने पहले वताया कि इसमें एक दो बातें इंवौल्वड थीं। एक तो इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट और दूसरी बैन्कस की इस में इंवौल्वमैन्ट थी जिस कारण यह मामला केन्द्र को रैफर करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने फरमाया कि पहली पास बुक्स से नयी पास बुक्स इमप्रूव्ड होंगी। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि ये पास बुक्स केवल लैण्ड रिकार्ड के लिये ही हैं या बैन्क से या किसी दूसरी एजेन्सी से यदि किसी किसान ने लोन वगैरह लेना हो तो उससे लिये भी वैलिड डौकुमैंट्स होंगी या किसी सरपंच, किसी दूसरी एजेन्सी या लोकल एम० एल० ए० से उसको तसदीक करवाने की आवश्यकता भी होगी? क्या ये प्रमाणित पास बुक होंगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जी हां ये प्रमाणित पास बुक्स होंगी। इस बारे में बैक्स से बातचीत चल रही है ताकि किसानों को लोनिंग की फैसिलिटीज भी पूरी तरह से मिल सके।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Number of Male and Female J.B.T. Teachers

***881. Shri Shiv Parshad :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of male and female J.B.T. Teachers allocated to Haryana State at the time of the re-organization of Punjab State during the year 1966;

(b) the number of Teachers, as referred to above, who have been given seniorty from the date of their first

appointment togetherwith the number of Teachers promoted as Head Master amongst them; and

(c) the criteria, if any, fixed for granting them Selection Grades ?

Interim Reply

D . O . No. 2203-EM-89

"Sushma Swaraj,

Minister,

Education Department, Haryana,

Chandigarh.

Dated the 1st March, 1989.

Dear Speaker Sir,

Starred Question No. 881 relating to the Education Department has been fixed for the Second of March, 1989. Efforts have been made to collect the necessary data from the Various districts to answer this question. But as the record dates back to the time of re-organisation, it has not been possible for us to get the entire record scrutinised and verified properly.

In view of the above, I shall be grateful if we are allowed a month's extension for sending a reply to this question.

Yours sincerely,

Sd/-

(Sushma Swaraj)

Shri H.S. Chatha,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Advertisements given to Newspapers

121. Mangal Sein : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the advertisements have been released by the Government to the Monthly/Weekly/Daily Newspa pers being published in or outside the State during the period from 1-7-87 to-date; and

(b) if so, the criteria fixed for releasing advertisements for publication in the Monthly/Weekly/Daily Newspapers, as referred to in part (a) above ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल):

(क) जी हां।

(ख) विभिन्न समाचार–पत्रों तथा पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन देते समय लोकहित, सरकारी बोर्डों एवं निगमों के

व्यापारिक हितों, समाचारपत्र की प्रसार संख्या, उसका पाठक वर्ग, विज्ञापनों की तुलनात्मक दरें तथा सरकार कैर इसके बोर्डों एवं निगमों में उचित एवं प्रतियोगी लागत सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखा जाता है, ताकि समूचे तौर पर विस्तृत प्रचार के उद्देश्य की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

Construction of Residential Colonies at Faridabad

128. Shri Yogesh Chand Sharma : Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state whether there is any proposal under consideration of The Government to construct residential colony for the employees working in the Industries at Faridabad; if so, the steps so far taken to. construct the aforesaid colony ?

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह): जी नहीं।

Opening of New Schools in the State

130. Shri Yogesh Chand Sharma : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open new schools for boys/girls in the State during the year 1989-90; if so, the names thereof separately; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to upgrade the Schools for

boys/ girls in the State duringe the year 1989-90; if so, the names thereof separately ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) वर्ष 1989–90 में केवल लड़कियों के 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जिनके लिए गांवों का अभी चयन किया जाना है

(ख) हां, वर्ष 1989– 90 में 100 प्राईमरी तथा 50 मिडल स्कूलों को क्रमशः मिडल तथा उच्च स्तर तथा 25 हाई स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी तक स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ऐसे स्कूलों के नामों का अभी चयन किया जाना है।

Construction of Tourist Complex at Ballabgarh

131. Shri Yogesh Chand Sharma : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Tourst Complex at Ballabgarh; and

(b) if so, the time by which the said Tourist Complex is likely to be constructed ?

उद्योग मन्त्री (डा० किरपा राम पुनिया):

(क) हां।

(ख) यह पर्यटक कम्पलैक्स वर्ष 1989–90 मैं बनाए जाने की सम्भावना है।

Opening of Government College for Women at Ballabgarh/Palwal

132. Shri Yogesh Chand Sharma : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the criteria, if any, adopted for opening the Government Colleges for Women in the State; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College for Women at Ballabgarh/Palwal ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) राज्य में राजकीय महाविद्यालय खोलने बारे कोई निर्धारित मापदण्ड नही अपनाया गया है। तथापि प्रायः एक नया महाविद्यालय खोला जाना क्षेत्र की आवश्यकता, कम से कम 10 से 12 एकड़ उपयुक्त भूमि, भवन, इक्विपमैन्ट तथा स्टाफ के लिये पर्याप्त धन–राशि, की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(ख) बल्लबगढ़ में महिलाओं के लिये एक राजकीय महाविद्यालय आठवीं पंचवर्षीय योजना में खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, परन्तु पलवल में महिलाओं के लिये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने एक प्रिवलेज मोशन का नोटिस आज सुबह दिया था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः वह मेरे अंडर कसिड़ेशन है।

वाक आउट

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने फरीदाबाद जिले के अनंगपुर तथा पाली गांवों में बजरी तथा सिलका रेत के लिये खानें पट्टे पर देने के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दिया था लेकिन उसको आपने डिस–अलाउ कर दिया है। इसमें ग्रांउड दिया गया है कि यह मामला रिसैट अक्रैंस का नहीं है।

Mr. Speaker : It has been disallowed and you cannot challenge my ruling.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बारे में सबूत है। (शोर)

Mr. Speaker : If you want to say anything, give it in writing.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः आप इसे रिव्यू करने की कृपा करें। (शोर)

Mr. Speaker : I am sorry you can come to my Chamber, and discuss it with me.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः .....

Mr. Speaker : Please take your seat. Nothing is to be recorded.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः फिर हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते है

(इस समय चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह, सर्वश्री बलवीर' पाल शाह तथा मोहम्मद असलम खां सहित सदन से वाक आउट कर गए)

विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने करनाल में. एक जातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधान मन्त्री ने चंडीगढ पंजाब को देकर हरियाणा के हितों के साथ अन्याय करना चाहा लेकिन मैंने उस समय मुख्य मन्त्री पद से इस्तीफा देकर के हितों की रक्षा की। उन्होने यह भी कहा कि हरियाणा के वर्तमान मुख्य मन्त्री हरियाणा के हितों की अनदेखी कर रहैं हैं। उनके इस कथन से हरियाणा के लोगों का चिन्तित होना स्वभाविक है। इसलिए हम रूल 84 के तहत इस पर आधे घंटे की बहस चाहते है। इस बारे में मैंने आपको लिख कर भी दिया है।

Mr. Speaker : It has just been received and will be examined.

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया है। जो गवर्नमैंट सर्विस से रिटायर हो चुके हैं उनको पैन्शन का एरियर कैश की बजाए 6 सालो के बौंड की शकल मे दिया जाएगा। स्पीकर साहब, रिटायर होने वाला आदमी तो पहले ही उमर पूरी कर लेता है, पता नहीं कब भगवान के घर चला जाए। वह उन बौडज का क्या करेगा? इस कारण से पैन्शनर्ज में बहुत भारी बेचौनी है, मैं चाहता हू कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्षः मैं इसे ऐग्जामिन कर रहा हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बौड़ श्थोठी कें जगल में नील गाय तथा बन्दरों पर रोक सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, **I** have received a notice of calling attention motion No. 10 from Sarvshri Gurdial Singh and Harnam Singh, M.L,As regarding check on Neel Gal and Monkeys in the forest of Behar Sounthi. I admit it. Now Shri Gurdial Singh or Shri Harnam Singh may read the notice and the Minister concerned may make a statement thereafter,

श्री गुरदयाल सिंह सैनी तथा श्री हरनाम सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन का ध्यान बीड श्योंठी के जंगल में हजारों की संख्या में नीलगाय एव बन्दरों की ओर दिलाना चाहते हैं। क्योंकि इन वन्य प्राणियों द्वारा आसपास के दर्जन गांव की

हजारों एकड़ भूमि की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाई जा रही है। यदि इनको मारते हैं तो वन विभाग के कर्मचारी हजारों रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। नीलगाय एवं बन्दरों की संख्या बढ़ रही है। यदि इसे नियंत्रित न क्रिया गया तो फसल का और अधिक नुकसान होगा। सरकार इस बारे तुरन्त कार्यवाही करे।

वक्तव्य–

वन तथा वन्य प्राणी संरक्षण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Forest and Wild Life Preservation Minister (Shri Parma Nand) : Sir, the Govern mcnt is fully aware of the problem caused by Neel Gai and Monkeys in damaging the crops not only around Sounthi forest area hut alto in all other parts of the State partrcularly in the districts of Bhiwani, Mohindergarh, Rohtak, Jind, Hisar, Sirsa and Kurukshetra. The number of Neel Gai in Sounthi forest area is approximately 100 and that of Monkeys is about 200. The area of this forest is about 477 acres.

With, the enactment of Wild Lire (Protection) Act, 1972, Neel Gai and Monkeys were included in Schedule-II and III and partial protection was provided to these animals. However, keeping in view the low population of Neel Gai at that time, its huntrng was completely banned by the Government from 22-6-73 alongwith all other species of Deer and antelope. However, during the last one decade, the population of Neel Gai (Rojh) has increased manifold and a large number of complaints have been received -regarding the

damage caused to the standing crops by the Neel Gai.

The Neel Gai is a fast running animal and, as such, is difficult to catch. Normally, a tranquilizer gun is used to catch this animal.. However, there are instances when death occurred due to the use of tranquilizer gun. This caused a great resentment amongst the people of the area concerned because some religious sentiments are attached with these animals. Hunting licence can also be given for shooting of Neel Gai under Section 9(2) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 but keeping inj view the sentiments of the people, Government had banned their hunting vide notification dated 22-6-73.

In most of the meetings with the farmers and in almost every session of Vidhan Sabha there has been discussions regarding the damage caused to crops by Neel Gai. The Wild Life Preservation Department has been endeavouring to find a practical and feasible solution for the last 4-5 years. In this respect; Wild Life Institute of India; Dehradun was also requested to study this problem and suggest solution. Accordingly, a Study Team of two experts visited the State during August, 1986 and again during May, 1987 to find out the extent of the problem and how to overcome it. The Wild Life Institute of India, Dehradun proposed the following possible solutions :—

(i) Controlled culling of Neel Gai;

(ii) Capture and subsequent translocation of Neel Gai;

(iii) Fertility control to reduce reproduction rate;

(iv) Fencing in order to confine Neel Gai to forest area;

(v) Fencing/protection of crop land.

About the above solutions, it is stated that the culling of Neel Gai may cause some problems due to religious sentiments of the people. About capture and subsequent translocation of Neel Gai to some other area, as there is no such demand from any part of the country, therefore, this solution is not feasible. About fertility control, this is a long term measure because it does not deal with the present population of Neel Gai. About fencing of the forest area rn order to confine Neel Gai therein, though this will involve an huge expenditure, but it is being proposed to arrange for the required funds for the purpose in the Eighth Five Year Plan. While proposing the above solutions, the Wild Life Institute of India concluded that all capture operations as well as enclosing wild animals will cause a proportion of fatalities due to accidents, stress etc. and some Neel Gai will expire no matter how much care is taken.

The matter was also discussed in the meeting of Haryana State Wild Life Advisory Board on 19-12-88 at Sultanpur Lake, District Gurgaon wherein it was proposed that the permission for shooting of Neel Gai should be given under Section II (i)(b) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 to the persons where Panchayats unanimously recommend for such an action. It was also proposed that members of the Advisory Board will propogate in the general public that Neel Gai are, in fact, wild animals and belong to Deer species and, therefore, they are. not scared as cows. The Board will consider the matter again after receiving the public opinion about this animal in due course.

About monkeys, everybody is aware that as they symbolise Lord Hanuman, therefore, some religious-sentiments are involved if they are killed/hunted. However, the damage caused to the crops by the monkeys is negligible.

In conclusion, it is mentioned that wide publicity should be given to the public regarding the nature of the species and the damage being caused. The problem is being aggravated by their fast growth. Controlled culling on the request of the people through the panchayats seems to be the only solution at this stage.

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में इन नील गायों से बचने का एक उपाय तार लगाना बताया है और जंगल को तार लगाने की इनकी स्कीम अगली पंचवर्षीय योजना में है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तार लगाने की योजना पर जब काम शुरू किया जायेगा तो उस पर कितना खर्च आयेगा और तार न लगाने तक फसलों का कितना नुकसान होगा? मैं मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि यदि तार लगाने तक फसलों का तार लगाने के खर्चे से अधिक नुकसान होता है तो यह तार लगाने का काम अभी से शुरू क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि फसलों का अधिक नुकसान न हो सके?

श्री परमा नन्दः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसके बारे में मैंने अपने जवाब में वताया है कि इस बारे में हमने वाइल्ड लाईफ इन्स्टीच्यूट औफ इण्डिया,

देहरादून से सम्पर्क स्थापित किया था और उन्होंने अपने इन्स्टीच्यूट से दो विशेषज्ञ नियुक्त करके हमारे राज्य में भेजे थे। उन्होंने यहां का दौरा करने के बाद नील गायों से बचने के लिए 4– 5 इलाज बताये थे। इन 4–5 इलाजों में से ही एक इलाज था कि जंगल के चारों तरफ तार लगाये जायें और उनमें ये रखी जायें। इस बारे में स्टडी करने के बाद यह निर्णय हुआ कि 10,000 गायों के लिए 10,000 एकड जंगल में तारे लगा कर इन गायों को रखा जाये। इस काम पर पहले साल में 7 करोड़ रुपये खर्च होंगे और फिर हर साल 5 करोड़ रुपये का खर्च होगा, यह काम एक दम से पौसिबल नहीं है। हम फण्ड लेने की कोशिश कर रहैं है। यदि हमें फण्ड मिल जाएं तो इस काम को अगली पंचवर्षीय योजना में हम शुरू कर सकते है। अध्यक्ष महोदय, ये नील गाय अपनी अपनी फैमिली में अलग अलग रहती हैं। इनको जंगल में एक जगह पर अगर रखेंगे तो ये आपस में लड़ती हैं और लड़ने पर ये घायल हो जाती हैं। घायल होने पर इनमें अनेक प्रकार की बीमारी फैल जायेगी जिसके कारण आसपास के देहातों में बीमारी फैलने का खतरा है। इसलिए तार लगाने का उपाय और इनको एक जगह बंद करने का उपाय भी ठीक नही लगता। स्पीकर साहब, मैंने अपने सुझावों में यह भी बताया है कि इन गायों के द्वारा जो बड़ा भारी नुकसान होता है उससे बचने के लिए एक इलाज यह भी है कि अगर इनको रोकने के लिए गांवों वालों की तरफ से कोई युनानीमस फैसला यानी पंचायतों की तरफ से कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव आ जाये तो फिर हम उनको सैक्शन 11

(1) (बी) औफ दी वाइल्ड लाइफ (प्रोटैक्शन) ऐक्ट, 1972 के तहत शूटिंग के लाइसेंस दे देंगे और ज्यादातर पब्लिक ओपिनियन इस प्रकार की बनाई जाये। सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में आज इस वारे यूनानीमस प्रस्ताव पास किये जा रहैं हैं कि थू –आउट दि स्टेट लाईसैसं देने के लिए इसे यदि वाइल्ड लाईफ (प्रोटैक्शन) ऐक्ट के शड्यूल में से निकालना भी पडे नो ऐसा किया जाना चाहिए।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, इस समये करीब 100 नील गाय और लगभग 200 बन्दर होंगे जिन्हैं पकड़ने परं ज्यादा खर्च नही आएगा। क्या सरकार इन्हैं पकड़ कर कहीं और भेजने पर विचार करेगी ओं'

श्री परमा नन्दः स्पीकर साहब, नीत गाय शरीर से जितनी बडी और शक्तिशाली दिखाई देती है, तजुर्बे से यह साबित हुआ है कि इसका दिल उतना ही कमजोर होता है। उनको पकडने की कोशिश की गई लेकिन पकड़ने से पहले ही इनकी मौत हो गई। यह इंडिपैडैट रहने वाला पशु है। हम विचार कर रहैं हैं कि इन्हैं कैप्टिबिटी में रखा जाए और इनके लिए पिंजरे वनाए जाएं। इनको पकड़ने पर खर्च तो ज्यादा नहीं आता लेकिन पब्लिक ओपीनियन और सैंटिमैंटस इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी उपेक्षा नही की जा सकती। दूसरे इनको पकड़ कर कहां छोड़ा जाए यह भी समस्या है क्योंकि कोई भी दूसरी स्टेट इनको लेने के लिए तैयार नहीं है।

गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

प्रेषित माल पर कर संबंधी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब कन्साइनमैंट टैक्स के बारे में श्री रणजीत सिह एम० एल० ए० के रैजोल्यूशन पर जो 24–3–88 को मूव किया गया था, डिस्कशन रिजयूम की जायेगी। On 7th April, 1988 when the House adjourned, the Home Minister was on his legs. He may please resume his speech.

11.00 बजे।

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, पिछले मार्च सैशन के दौरान मेरे आदरणीय साथी चौधरी रणजीत सिंह ने यह प्राईवेट रैजोल्यूशन पेश किया था। यह बहुत ही बढ़िया रैजोल्यूशन है। केवल हरियाणा स्टेट ही नही बल्कि दूसरी बहुत सी स्टेट्स भी इससे अफेक्टिड होंगी। जब सन् 1982 में संविधान में 46वां संशोधन हो जाने से कन्साइनमैंट टैक्स की पावर स्टेटों को दिये जाने की बात पास हो गई थी तो सैटरल सेल्ज टैक्स कानून में अमैंडमैंट करके कन्साइनमैंट टैक्स लागू करने का अधिकार कभी का राज्यों को मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज देश का यह दुर्भाग्य है कि हरियाणा जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट जो कि विकास की ओर अग्रसर है और जिसने अभी और विकास करना है उसके विकास की ओर बढ़ते हुए कदमों को चौक करने के लिए उसमें रुकावट डालने के लिए, उसके रिसोर्सिज को लिमिटेशन में बांध दिया जाए ऐसा नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते

हैं कि हमारी हरियाणा स्टेट बहुत छोटी सी स्टेट है। देश की कई म्यूनिसिपल कमेटियां जैसे बम्बई और कलकला है, हरियाणा स्टेट से बड़ी हैं। यह स्टेट छोटी है इसके रिसोर्सिज भी बहुत कम हैं, साधन भी बहूत कम हैं। लेकिन जो सीमित साधन हैं अगर उन पर ही चौक लगा दी जाए तो इस स्टेट की क्या हालत होगी इसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है? जब कन्साइनमैंट टैक्स के लिए संविधान में संशोधन हो गया तो फिर उसे लागू करने में क्या दिक्कत है, क्या रुकावट है? उस समय बहुत विचार–विमर्श और सोचने–समझने के बाद ही यह संशोधन किया गया था। इस विचार–विमर्श में देश के सभी भागों के चुने हुए नुमाइंदे थे जिन्होंने बहुत सोच–समझ कर सैट्रल गवर्नमैंट को पावर दी थी। सभी स्टेटों के नेता इसमें शामिल थे जिन्हैं लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन कर पार्लियामैंट में भेजा था। उन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख कर, लोगों के हितों को ध्यान में रख कर ही और लोगों को दिए आश्वासन के आधार पर ही उन लोगों ने यह अमैंडमैंट की थी और सैट्रल गवर्नमैंट को यह अधिकार दिया था। इसके बावजूद आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, आज तक इस देश की यह परम्परा रही है कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश की आजादी के लिए लोग लड़ाई लड़ रहैं थे, उनके मन में एक ही भावना थी कि मेरा देश आजाद हो, मुझे स्वतन्त्रता मिले। उस समय जो परम्परा थी उसकी बदौलत देश को आजादी

मिली। कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं और हुक्मरानों ने वही नीति अपनाई जो आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमैंट की थी। हम लोगों को कष्ट होता था कि कैसे इस देश के साधनों को, इस देश के रिसोर्सिज को, इस देश के रा मैटीरियल को ब्रिटिश सरकार बाहर ले जाती थी। इस देश का कच्चा माल बाहर त्वे जाया जाता था ताकि इस देश में कारखाने न लग सकें। यदि कारखाने लगेंगे तो माल तैयार होगा, इस देश के लोगों को टैक्स आएगा, देश के खजाने में आमदनी होगी और यह पैसा देश के विकास पर खर्च होगा। इससे सड़कें बनेगी, रुल बनेंगे, बांध बनेंगे, नहरें बनेगी और रेल– गाड़ियों का बन्दोबस्त होगा। लेकिन उस वक्त की सरकार यही सोचती थी कि यदि हिन्दुस्तान में तरक्की हो गई, हिन्दुस्तान के पास साधन हो गये, रिसोर्सिज हो गये तो ये साधन सम्पन्न लोग एक जुट हो कर अंग्रेजी हकूमत के खिलाफ जबरदस्त बगावत करेंगे। इसलिए जानबूझ कर अंग्रेजी हकूमत ने ऐसा नहीं होने दिया और सारे का सारा कच्चा माल विदेशों में ले जाया जाता था। कपडा वनाने का काम कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी भारी टैक्नालाजी नहीं है, गांव का एक जुलाहा भी कपड़े पैदा कर सकता है लेकिन कपड़ा बनाने के लिए यहां से कच्चा माल विदेशों में ले जाया जाता था। कोई भी कारखाना इस देश में अंग्रेजों ने नहीं लगने दिया था क्योंकि उन्होंने साधनों को सीमित करना था और लोगों में एक हीन भावना पैदा करनी थी। माल को तैयार करके उसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए वे विदेशों में भेजते थे। वे समझते थे कि इस देश के

लोग इलने योग्य नही जो उस माल को प्रोडक्टिव बना सकें। इस तरह की भावना पैदा करके वे एक अंकुश देश के साधनों पर बनाये रखना चाहते थे और सारा माल विदेशों में चला जाग था। ऐसा होने से इस देश में बेरोजगारी पैदा हो गई थी। जितने भी साधन बनने थे, जो भी कारखाने बनने थे, जिनमें लोगों को रोजगार मिलना था चाहैं वे लोग अनपढ़ थे, तकनीकी शिक्षक थे या गैर–तकनीकी शिक्षक थे, उन्हैं रोजगार नहीं मिल जाये, इसलिए. उन्होंने कारखाने यहां पर नहीं लगने दिये। इन कारखानों को देश में लगाने की इजाजत नहीं दी गई। वे दूसरे देश में लगते रहैं। यह सब इसलिए किया जाता रहा ताकि हिन्दुस्तान की आमदनी में अंकुश हो और इस देश के लोगों को रोजगार न मिल सके। आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और राजनैतिक तौर पर जहां देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी कि हमारे साधनों को विदेशों में ले जाया जा रहा है वहां दूसरी लड़ाई भी साथ साथ लड़ी जा रही थी। राजनैतिक संघर्ष के लिए जहां लोगों ने लड़ाई लड़ी उसके साथ साथ आर्थिक स्ट्रगल भी शुरू थी कि इस देश की पूंजी विदेशों में ले जायी जा रही है। बुरी तरह से अंग्रेजों की हकूमत लूट रही थी। इसके लिए हमारे देश के लोग एक लम्बी लड़ाई लड़ते रहैं। हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, सैकड़ों लोगों ने अपने सिर दे दिये, हजारों लाखों लोगों ने जेलें भर दीं। इसके अलावा इस देश में कुछ और भी लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दूसरे ढंग से दी थी। हमारे किसानों ने भी कुर्बानी दी चाहैं उन्होंने राजनैतिक मूवमेंट में

कन्ट्रीब्यूट नहीं किया, वे जेलों में नहीं गये लेकिन वे खेतों में काम कर रहैं थे। वे इसलिए काम कर रहैं थे कि मेरे देश में अनाज ज्यादा पैदा हो। मेरे राजनैतिक लीडर, मेरे सामाजिक लीडर इस बात की चिन्ता न करें कि देश में अनाज की दिक्कत बै, उन्हैं यह चिन्ता न हो कि देश के लोगों का कैसे पेट भरेगा। वे राजनैतिक लौंगों को इस चिन्ता से की रखना चाहते थे। इस तरह से किसानों ने चूंकि हमारे नेताओं को की कर दिया इसलिए उन का भी इस देश की तरफ ध्यान था। वे भी राजनैतिक लड़ाई लड़ रहैं थे। जब किसानों ने अच्छा अनाज पैदा किया, 23–24 घन्टे मेहनत की, मजदूरों ने मेहनत की तो राजनैतिक लोगों को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला वरना अंग्रेज जो लोगों का शोषण कर रहैं थे उनके खिलाफ ऐसे टाईम पर लड़ाई लगनी बहुत मुश्किल थी। अगर किसी घर में चार आदमियों का परिवार था तो उनमें से एक आदमी खेत में काम कर रहा था दूसरा पाली का काम कर रहा था, पशु चरा रहा था और कोई दूसरा काम कर रहा था.। वे मुश्किल से एक आदमी को स्पेअर कर पाते थे ताकि वह राजनैतिक और सामाजिक कामों के लिए समय दे सके और इस देश की आजादी की लड़ाई खाली हो कर, घर की चिन्ता किये बगैर, लड़ सकें। यह साल काम किसान भी कर रहा था। मजदूर भी कर रहा था। मैं तो यह कहूंगा कि देश का एक–एक बच्चा उस वक्त का स्वत्रन्त्रता सेनानी का यह काम कर रहा था। चाहैं उसका नाम स्वतन्त्रता सेनानियों की किताब के अन्दर न आया हो क्योंकि नाम तो केवल उन्हीं लोगों के आये हैं जिन्होंने

जेलें काटी हों या राजनीतिक मूवमैंट में भाग लिया हो लेकिन उस किसान की कुर्बानी और उस मजदूर की कुर्बानी भी बहुत बड़ी थी। अपने बेटों, अपने भाइयों और अपनी बहनों को इस लायक बनाया कि वह राजनीतिक आन्दोलन में कूद पड़े। फ्री माईन्ड से हिस्सा लें। उनका अपना एक जबरदस्त कन्ट्रीव्यूशन था। इसके साथ–साथ जो आर्थिक मार अंग्रेजी हकूमत द्वारा हमारे०पर मारी जा रही थी, अफसोस तो यह है कि वह आज भी जारी है। उस हकूमतरू के खिलाफ हमने लड़ाई की थी, संघर्ष किया। उसके बाद इस देश के लोगों की कुर्बानी का फल आया। यह मौका आया कि हम अपनी सरकार बना सकें। लोग अपने प्रतिनिधि चुन सकें। वह प्रतिनिधि इस देश की सरकार को चलायें लेकिन ऐसे प्रतिनिधि चुने गये और सैट्रल गवर्नमैंट भावनावेश में आकर ऐसी बनी जो इस कारण से या किसी मैनीफैस्टो की वजह से नहीं, भावना की वजह से यह नारा देकर आयी कि हम गरीबी को हटायेंगे। कभी दूसरा कोई नारा दिया गया। जात–पात को फैला कर, धर्म की बात कह कर, धार्मिक सदमावना को बिगाड़ कर और इस तरह के इशू को सामने रखकर ये लोग सत्ता में आये हैं। आर्थिक इशू को भुला कर साईड ट्रैक करके उन चीजों को भुला दिया गया कि इस देश के अन्दर बेरोजगारी है, इस देश के अन्दर भुखमरी है या इस देश के अन्दर महंगाई है। इन सब बातों को अलग करके लोगों को भावनाओं में बहाकर, लोगों को भावनावेश करके, कांग्रेस की सरकार ने लोगों से वोट मांगे। 1984 में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो रहा था। हर तरफ

यह सोच थी कि कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जायेगी लेकिन उसके बाद स्पीकर सर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई कि इस देश के प्रधान मन्त्री पर गोली चली और स्पीकर सर, यह नहीं कि एक आदमी के दिमाग में उसी दिन यह बात आ गयी कि आज मैंने गोली मारनी है और उसी दिन उसने गोली मार दी। नहीं ऐसी बात नही है। इसके लिए व्यवस्था जिम्मेवार है। जो कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था पैदा की थी, वह इसके लिए जिम्मेवार है। उसकी वजह से देश के अन्दर भाई–चारा बिगड़ा और देश के अन्दर जाति–पाति पैदा की गयी, धार्मिक संभावना बिगाड़ा गयी और जिस ढंग से एक' धर्म विशेष के किसी एक कट्टरपंथी आदमी को जो खुलकर यह कहा करता था कि यह करा दूंगा, वह करा दूगा, हिंसा की भावनाएं फैलाया करता था, उस आदमी को नेता का दर्जा दिया गया, सन्त उसको कहा गया कि यह तो सन्त है, बहुत बड़ा महात्मा आदमी है। भिंडरावाला को महात्मा कह कर उसका जलूस निकाला गया। सैट्रल सरकार की पुलिस प्रोटैक्शन में जलूस निकाला गया। स्पीकर सर, आपको याद होगा दिल्ली के अन्दर सैकड़ों ट्रकों के अन्दर हथियारबन्द लोगों का जलूस निकाला गया। कांग्रेस सरकार को उस वक्त यह दिखता नही थी कि इस प्रकार की जो हिंसा की गतिविधियां करने की वे उसको इजाजत दे रहैं हैं, एक किस्म से उसके साथ मिलकर काम कर रहैं हैं, इसका परिणाम क्या होगा? उस वक्त की सरकार सोच तो यह रही थी कि देश के अन्दर जो भुखमरी है, देश के अन्दर जो बेरोजगारी है, इससे देश के लोगों का ध्यान किसी तरह से

हटाया जाये और लोगों का ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाया जाये। कांग्रेस के नेताओं ने वह ध्यान बांटने की समस्या को लेकर उस नेता की वजह से एक नयी समस्या पैदा कर दी। इन्होंने सोचा कि बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिये जातीय दंगे करा दो। भुखमरी और मंहगाई की समस्या को खत्म करने के लिये धर्म के नाम पर कहीं पर दंगे करा दो। कहीं मेरठ में करा दो और कहीं अहमदाबाद में करा दो। कहीं हिन्दू और मुसलमान में दंगे करा दो और किसी दूसरी जगह पर हिन्दू और सिख में करा दो। इस तरह का नंगा नाच साम्प्रदायिक सदभावना को बिगाड़ने का कांग्रेसी किया करते थे। इनकी मेन इन्टैंशन यह रहती थी कि अपना राजनैतिक उल्लू किस तरह से सीधा किया जाये। किस तरह से राजनैतिक तवा गर्म रखा जायें। इसी वजह से आतंकवाद का सारे का सारा तमाशा हुआ और उस बात का राजनैतिक फायदा उठाने की, इन लोगों ने कोशिश की। यही कारण था कि देश का बहुत बड़ा नुक्सान हुआ। एक अविश्वास पैदा हुआ वरना क्या किसी भी मिनिस्टर या प्राईम मिनिस्टर को उसका अपना ही बौडी गार्ड गोली मार सकता है? इस किस्म का एक माहौल इस देश के अत्दर अपने तुच्छ इरादों को पूरा करने के लिये किया गया। क्यों पैदा किया ? क्योंकि यह सारे वोट लेना चाहते थे। वोट कोई रोजगार का नाम लेकर इनको नहीं मिल सकते थे। महंगाई भी बहुत बढ़ रही थी, इसलिये इस नाम पर भी इनको वोट नही मिल सकते थे। इनको कोई दूसरा तीर मारने के लिये चाहिये था। इस देश में आतंकवाद का गर्म तवा है। उस पर

राजनैतिक रोटियां सेंक लो। यह सेंकने की कोशिश करते–करते अपने हाथ ही जला बैठे और अपने ही हाथ नहीं जलाए बल्कि सारे देश के हाथ जला दिए। स्पीकर साहब, इस देश में इनसिक्योरिटी की भावना आ गई। इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। आज सैन्ट्रल गवर्नमैंट हरियाणा प्रदेश के साथ ज्यादती कर रही है। जो देश की मूल समस्याएं हैं उनसे जनता का ध्यान हटाकर तरह तरह के तमाशे और नारे लगा कर लोगों को बहकाया जाता है। स्पीकर साहब, टेलीवीजन पर जगह–जगह शव याता दिखाई गई, फूलों से ढका हुआ शव दिखाया गया, लोगों को रोते हुए दिखाया गया और खुद राजीव को रोते हुए दिखाया गया। इस दृश्य को देखकर लोग उदास हो गए और उनकी आखों में आसू आ गए। वोट लेने के लिए यह तमाशा किया गया। अभी देश के लोग अपने आमू न सुखा पाए थे कि प्रधान मन्त्री ने इलैक्शन्ज की घोषणा कर दी ताकि इंदिरा गांधी की मौत का कुछ फायदा उठाया जा सके। आसू पूछने से पहले ही इलैक्शन का एलान कर दिया गया। जब आख में आमू हौते है तो कोई चीज साफ नजर नहीं आती। लोगों ने सोचा कि बेचारे की मां मर गई है इसी को वोट दे दो। मां मरने की भावना से लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। आख मे जब आसू थे तो लोगों को नजर नही आ रहा था कि हमने कहां वोट डालना है। इन्होंने लोगों की भावना का फायदा उठाया। स्पीकर साहब, आज हालत यह है कि केन्द्रीय सरकार स्टेट्स को कोई अधिकार नहीं देना चाहती। स्टेट्स को पंगू बनाना चाहती है। पिछलें दिनों हमारे

आदरणीय मुख्य मन्त्री ने सभी विपक्षी स्टेट्स के मुख्य मण्डियों के साथ दो तीन बार मीटिंग्ज की। आसाम स्टेट में गोहाटी में मीटिग हुई, कर्नाटक प्रान्त में बंगलोर में मीटिंग हुई, पश्चिमी बंगाल प्रान्त मे कलकत्ता में मीटिंग हुई, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्ज उन मीटिंग्ज में नहीं आए। हालांकि वे आना चाहते थे। वे भी चाहते हैं कि प्रदेशों को ज्यादा अधिकार मिलें लेकिन साफ तौर पर वे कुछ नहीं कह सटते। वे तो नौमिनेटिड सूबेदार हैं। स्पीकर साहब, देश के अन्दर अजीब तमाशा हो रहा है। पिछने दिनों आपने देखा कि कभी विन्देशवरी दूबे को हटाया जा रहा है और कमी उस हो भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस बार तो गजब ही हो गया। पहने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री अर्जुन सिंह को सैन्टर में लिया, फिर उसको गवर्नर बना दिया और वहां का चीफ मिनिस्टर बोहरा कॉ बना दिया। फिर अर्जन सिंह को चीफ मिनिस्टर वना दिया और वोहरा को सैन्टर में ले लिया। उसके बाद अर्जुन सिंह को हटा दिया और वोहरा को मुख्य मन्त्री बना दिया। जिस पर प्रधान मन्त्री की मोहर लग जाए उसी दिन उसको मुख्य मन्त्री बना दिया जाता है। अगर किसी दिन प्रधान मन्त्री किसी मुख्य मन्त्री पर नाराज हो जाए तो उस मुख्य मंत्री को उसी दिन हटा दिया जाता है। स्पीकर साहब, इससे राज्य कमजोर हो रहैं है। उनको पंगु बनाया जा रहा है। राजनैतिक सत्ता के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है और यही कारण है कि प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर पब्लिक ओपीनियन का ध्यान नही रखते, क्योंकि उनकी लाचारी है। उन्हैं पता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नही कर सकते। उन्हैं पता है

कि हम आज हैं कल शायद रहैंगे या नही। जिसका नाम प्रधान मन्त्री रख दे वही मुख्य मन्त्री बन जाता है। इसी कारण वे लोगों का काम नही करते और लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नही देते। वे सोचते हैं कि काम करने का कोई फायदा नही है क्योंकि रोज अदला बदली हो रही है। वे तो प्यादों की तरह हैं जिसको जहां चाहैं रख दिया जाता है। प्रधान मन्त्री जिस प्याऊ को जहां चाहैं रख देता है। इसका अर्थ यही निकलता है कि स्टेट्स कमजोर हों और कोई स्टेट सिर न उठा पाए, उनकी भावनाएं०ंची न होने पाएं और उनके अन्दर हीन भावनाएं बनी रहैं। स्पीकर साहब, पिछले दिनों बिहार मे एक अच्छा तमाशा रहा। वहां पर 374 कांग्रेस के लोगों में हिम्मत आ गई। पता नही उनमे हिम्मत कैसे आ गई? हो सकता है चौधरी देवी लाल ने वहां पर जो दौरे किए और उन्होंने इनके विचार सुने उसके कारण से हिम्मत आ गई या चौधरी देवी लाल के चरित्र को देखकर उनमें थोड़ी बहुत हिम्मत आ गई हो औंर उनमें कुछ अच्छी भावना आ गई हो। उन प्यादों ने कहा कि हम उस चीफ मिनिस्टर को नही चाहते। वह चीफ मिनिस्टर राजीव गांधी का आदमी है। राजीव गांधी ने अपने आदमी वहां दौड़ाए। प्रधान मन्त्री का जो डैलीगेशन वहां गया उन लोगों ने उस डैलीगेशन से मिलने से इन्कार कर दिया। जब तक चौधरी देवी लाल उस तरफ रहैं उन कांग्रेस मे लोगों में कुछ खुद्दारी आई और कुछ हिम्मत आई लेकिन जैसे ही चौधरी देवी लाल उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ आए वह खुद्दारी और हिम्मत खत्म हो गई। पुरानी कांग्रेस के सारे आदर्श खत्म हो गए।

अभी तक वह मामला साफ नही हुआ है उसका कुछ भी हशर अभी नही निकला है। स्पीकर साहब, नौन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्ज की जो कांफ्रैस हुई थी उसमें देश के लोगों के सामने बड़ी ही सीरियस बातें चौधरी देवी लाल ने रखीं। लोगों को उन बातों का पता ही नही था। स्पीकर साहब, हर आदमी यह सोचता है कि इंकम टैक्स का शेयर हर स्टेट को मिलना है हर आदमी के दिमाग में यह बात है। हम लोग भी सोचते हैं कि शायद यह इन्कम टैक्स का हिस्सा हर स्टेट गवर्नमैंट को सैन्टर से मिलता होगा क्योंकि इस पैसे पर स्टेट्स का अधिकार है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)। इन्कम टैक्स को डकट्टा करने के प्रिये सारे का सारा साधन स्टेट्स मुहैय्या करवाती हैं, सारे साधन तो स्टेट की सरकारें ही जुटाती हैं। कोई भी काररखाना स्टेट के अन्दर लगेगा, कोई भी फिर स्टेट के अन्दर लगेगी, कही सड़कें बनेगी, कही जमींन देने की बात आयेगी, बिजली देने की बात आयेगी, ईट पत्थर, रोड सीमैंट देने की जहां बात आयेगी तो ये सारे साधन स्टेट की तरफ से ही मुहैया किये जाएंगे लेकिन इसके वावजूद जब इन्कम टैक्स लगाते हैं तो उसका सारा पैसा केन्द्र सरकार के खजाने में चला जाता है। इसलिये जब सभी प्रकार के साधन स्टेट्स के हों, तो उसके लिय हर आदमी यह सोचेगा कि इस इन्कम का पैसा भी स्टेट गवर्नमैंट को मिलना चाहिये लेकिन हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। पता क्या लगा कि जो 'आदमी अपना व्यक्तिगत इन्कम टैक्स देता है, उसका हिस्सा तो देते हैं और वह भी केवल नाममात्र ही होता है। चौधरी भजन लाल जैसे सलीके के

लोग इंकम टैक्स की चोरी कर जाते है और सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाते। इससे हमें मिलेगा क्या? नगण्य मात्रा में ही पैसा मिलेगा। असली पैसा तो कारपोरेट टैक्स का है। जो कंपनियों का टैक्स होता है उसका हिस्सा स्टेट गवर्नमैंट को मिलना चाहिये लेकिन केन्द्र सरकार स्टेट्स को अपने कब्जे में पंगु बनाकर रखने के लिये जो कम्पनियों से इन्कम टैक्स की आमदनी होती है, उसे केन्द्रीय खजाने में जमा करवाती थे और उसके बदले में किसी भी स्टेट को एक पैसा भी नही मित्रता है। यही बात हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने चीफ मिनिस्टर्ज कांफ्रेस में भी कही थी कि सबसे बड़ी हमारी समस्या यही है कि स्टेट्स के साधनों से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, वह सारा ही केन्द्रीय खुजाने में जमा हो जाता है और हमें उसका एक पैसा भी नही मिलता है। हम यह नहीं चाहते कि स्टेट्स का डोमीनेशन हो। हम तो यह चाहते हैं कि यह जो रिसोर्सिज है, अधिकार है इनको इतना सीमित क्यों किया जा रहा है? उन अधिकारों से स्टेट्स को केन्द्र द्वारा वंचित क्यों रखा जा रहा है जिन पर स्टेट्स का पूरा अधिकार है। अपने अधिकारों के लिये स्टेट्स केन्द्र से कटोरा लेकर क्यों मांगती रहें? केन्द्र को अपने आप ही स्टेट्स का शेयर देना चाहिये। हम कोई भिखमंगे तो नही है। इस तरह की बातें प्राईम मिनिस्टर के सामने चौधरी देवी लाल जी ने कही थी क्योंकि चौधरी देवी ताल जी कोई नौमीनेटिड चीफ मिनिस्टर नहीं है। चौधरी देवी लाल हरियाणा की एक करोड़ चालीस लाख जनता द्वारा चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। चौधरी देवी लाल जी एक

मास लीडर हैं, इसीलिये उन्होंने प्राईम मिनिस्टर को ललकारा था। डिप्टी स्पीकर साहब, शायद देश के इतिहास में यह पहली बार ऐसे मुख्य मन्त्री आए हैं जिन्होंने प्राईम मिनिस्टर को ठोक कर यह कहा हो, वरना ये लोग तो कायर हैं। ठोक कर कहने की बात तो दूर रही, प्राईम मिनिस्टर अगर बैठे रहते हैं तो उन लोगों को कंपकपी सी उठी रहती है कि न जाने कौन सी हमारी हरकत सें प्राईम मिनिस्टर नाराज हो जाएं और डिसमिसल की चिट्ठी पकडा दी जाए। लेकिन हमारे लोकप्रिय नेता चौधरी देवी लाल जी ने उस वक्त भी ठोक कर उन्हैं कहा था कि प्राईम मिनिस्टर साहब हम चुने हुए लोग हैं, मास के लीडर हैं। हम आपकी कठपुतली नहीं हैं। आगकी हां में हां मित्राने वाले हम लोग नहीं हैं। जो हमारी स्टेट्स की समस्याएं हैं, उनको बाकायदा आपके सामने रखकर ही रहैंगे। यह पहली बार चौधरी देवी लाल जी ने कहा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कद्रु रहा था कि कंपनी टैक्स में से भी हर स्टेट्स को अपना–अपना हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि इस आमदनी के लिये सभी प्रकार के साधन तो स्टेट गवर्नमैंट्स ही जुटाती हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार इतनी कोशिशें करती है कि इन साधनों को सीमित किया जाए। और तो और पिछले दिनों डिप्टी स्पीकर साहब इन्होंने क्या किया कि एक नेशनल ड्राउट रिलीफ फण्ड बनाने की कोशिश की ताकि जो स्टेट्स से पैसा इकट्ठा हो, वह इनके खजाने में आ जाए। इसी तरह के और भी टैक्स लगाने का प्रयत्न किया ताकि स्टेट्स से जो पैसा इकट्ठा हो, वह केन्द्र के बजाने में जमा होता रहैं और स्टेटस बाद में इनके पास झोली

फैला कर जाती रहैं कि हमारी स्टेट में सूखा पड़ा हुआ है, कुछ न कुछ हमें दो। उन्होंने सोचा कि स्टेट्स इस तरह की चमचागिरी करेंगी, खुशामद करेगी लेकिन इसका विरोध भी हमारे आदरणीय मुख्यमन्त्री चौधरी देवी लाल जी ने किया कि यह नैशनल ड्राउट रिलीफ फण्ड योजना स्टेट की ही होनी चाहिये ताकि इससे जो पैसा इकट्ठा हो उस पर अपनी स्टेट्स का ही हक होना चाहिये। इस पैसे को स्टेट्स ही अपनी मर्जी से खर्च कर सकें। अगर कहीं स्टेट के अन्दर सूखा पड़े, ड्राऊट की स्थिति हो तो हम उस इकट्ठे किये पैसे का स्वयं इस्तेमाल कर सकें क्योंकि हमें सैन्टर पर विश्वास नही है। क्यों विश्वास नही है इसका एक उदाहरण है कि पिछले दिनों जब सूखा पड़ा था तो उसका असर सभी जगहो पर हुआ था लेकिन हरियाणा के अन्दर कोई पशु नही मरा, कोई आदमी नहीं मरा। इसका मतलब यह नहीं कि हरियाणा के अन्दर सुखा नहीं पड़ा था लेकिन चूंकि चौधरी देवी लाल जी का हरियाणा के अन्दर नेतृत्व था, उनका स्वच्छ प्रशासन था इसलिये हरियाणा के अन्दर हमने एक पशु, एक आदमी भी सूखे के कारण मरने नही दिया लेकिन साधनों में वाकई में कमी थी। सब जगह सूखा ही मूखा नजर आ रहा था। दूसरी स्टेट्स के अन्दर भी सूखा पडा था, हम नही कहते कि नहीं पड़ा था। सूखा ममी स्टेट्स में पड़ा था लेकिन दूसरी स्टेट्स की निस्बत हरियाणा के साथ केन्द्र द्वारा सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया थो। यह चकेन्द्र चाहता था कि हरियाणा को पूरी तरह से पंगु बना कर रखा जाए ताकि वे हमारे सामने झोली फैलाएं। इसका मैं उदाहरण

डिप्टी स्पीकर साहब देता हू कि राजस्थान को 480 करोड़ रुपया सूखा राहत के लिये दिया गया और हरियाणा प्रदेश को केवल माल 35 करोड़ रुपए दिए। यह सैंटर के लिए बड़ी शर्म की बात है। इस तरह से ये लोग काम करते हैं और दूसरी तरफ नेशनल ड्राउट रिलीफ फंड पैदा करने की कोशिश कर रहैं थे ताकि सारा पैसा उनको मिल जात्। अगर उनको सारा पैसा मिलता तो वे तो खा जाते। आज तक क्हा हरियाणा में ड्राउट नहीं पड़ा, फ्लड नहीं आए। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड पहले भी होग था। भजन लाल भी सात साल इस प्रान्त के मुख्य मन्त्री रहैं। यह देश का दुर्भाग्य था कि इस देश का एक क्रप्ट और क्रिमिनल आदमी इस प्रदेश में सात साल तरु मुख्य मन्त्री रहैं। उसने लोगों की जेबें काटीं। उसने रिलीफ फंड इकट्ठा करके यह नहीं किया कि स्टेट के खजाने में जमा करवा दिया हो बल्कि उसने अपनी जेबें भरने का काम किया। ब्लैक मार्किट करने वाले लोग भी लाखों रुपयों को थैलियां उसको दे दिया करते थे। उस समय नौकरियों को बेचा जाता था, पोस्टिग्ज को बेचा जाता थो। लोगों को उजाड़ कर उनकी जमीन ली जाती थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पंचकूला के साथ लगती हुई जमीन हुड्डा के लिए ऐक्वायर की गई थी। किसानो ने विरोध किया कि हमें हमारी जमीन वापिस की जाए। सरकार ने इसके लिए मना कर दिया और सैक्शन 4 और 6 के नोटिस भी जारी हो गए। उसके बावजूद दो आदमियों ने दर्खास्त दी कि फलां जमीन वापिस दी जानी चाहिए। मामला भजन लाल के पास पहुंच गया और उन्होंने वह 26 एकड़ जमीन वापिस

करने के आर्डर दे दिए। उसके बाद वहां पर एक कालोनी बनाने की मंजूरी दे दी। उस कालोनी से उन लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए और भजन लाल को उसका हिस्सा दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप रिकार्ड देखें तो उस वक्त का रिलीफ फंड या तो आपको किसी साल में 50 लाख रुपये मिलेगा या 40 लाख रुपये मिलेगा लेकिन चौधरी देवी लाल जी के टाईम में डेढ़ साल में साढ़े सात करोड़ रुपया रिलीफ फंड का आया। यह नहीं कि पहले यह फंड नहीं आता था, पहले भी आता था लेकिन वह जेबों में चला जाता था और ताज सरकारी खजाने में जाता है। यह पैसा भी जो लोग देते हैं, उनके पास दुगुना होकर जाता है। आज गांव गांव के अन्दर मूवमैंट चल पड़ी है और लोग दो–दो, चार–चार, दस–दस और बीस–बीस लाख रुपया इक्ट्ठा करते हैं। चौधरी देवी लाल, ने खुला निमन्त्रण दे रखा है कि जितना पैसा इकट्ठा करके दोगे उसके बराबर का सरकार देगी। इस रिलीफ फंड में भी हम बराबर का पैसा दे रहैं है। यहां तक कि लड़के और लड़कियों के स्कूलों के लिए तीन गुना रिटर्न करते हैं। उनकी तरह नहीं कि यह जेब भी भर ली और वह जेब भी भर ली। सारा पैसा सरकारी खजाने में जाता है यानी सारे रिसोर्सिज खजाने में जाकर इकट्ठे होते हैं। इस कन्साइनमैंट टैक्स के बारे में भी सैट्रल गवर्नमैंट की नीयत खराब है, वह चाहती है कि हमारे साधन सीमित हो जाएं। वह हम लोगों को पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। कन्साइनमैंट टैक्स ऐक्ट में 1982 में अमैडमैंट हुई थी, आज सात साल हो गए उसको लागू नही किया है। यह कितनी

सीरियस बात थी और हरियाणा के जीवन और मौत का सवाल था। पहले हम फैक्टरी वालों को जमीन ऐक्वायर करके देते हैं, आप खुद किसान है। शहर के साथ लगती हुई जमीन लाखों रुपए के हिसाब से बिकती है। तो किसान की जमीन ऐक्वायर करके इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाते हैं और इंडस्ट्रियलिस्टस को बुला कर न जाने कितने कन्सैशन देते हैं, टैक्स की रियायत देते हैं। पहले डैफरमैंट की थी अब तो ऐग्जैम्पशन भी दे दी है। इलैक्ट्रिसिटी डियूटी की दी है, लोन कम दर के ब्याज पर देते हैं, मार्किट देने की कोशिश कर रहैं हैं। हरियाणा सरकार उनको पांवों पर खड़ा करती है। उसके बाद जब मौका आता है तो उसका फल दूसरी स्टेट्स को चला जाता है, कितने दुर्भाग्य की बात है। फरीदाबाद हमारा एक शहर शै। उसे हम औद्योगिक नगरी कहते हैं। वहां पर हम इंडस्ट्रीयलिस्टस को कनसैशन दे कर, जमीन दे कर और दूसरे साधन देकर इंडस्ट्रीज सैट–अप करवाते हैं लेकिन उन इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टस जा कर दिल्ली में बिक जाती है। इसका कारण यह है कि सैट्रल सरकार ने जानबूझ कर यह तमाशा किया हुआ है। हरियाणा प्रदेश दिल्ली के तीन तरफ लगता है। दिल्ली बोर्डर के साथ लगते हुए फरीदाबाद, गुडगावां, रोहतक और सोनीपत चार डिस्ट्रिक्टस हैं जिनके अन्दर मेन इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनकी सारी प्रोडक्टस दिल्ली में जा कर बिक जाती है। दिल्ली की बजाय हरियाणा स्टेट में टैक्स ज्यादा है इसलिये दिल्ली बोर्डर के साथ लगते हुए इंडस्ट्रीयलिस्टस को प्रोत्साहन मिल जाता है जिसके कारण वह अपनी प्रोडक्टस हरियाणा की बजाय दिल्ली में

बेच देते हैं। इंडस्ट्रीयलिस्टस को इंडस्ट्रीज लगाने के लिये जमीन हम देते हैं, कनसैशन हम देते हैं और दूसरी सुविधाएं हम देते हैं लेकिन वे अपनी सारी प्रोडक्टस दिल्ली में जा बेच देते हैं। यह हमारी कमजोरी है, हमारी मजबूरी है कि हम सारे साधन देने के बावजूद भी उनसे टैक्स नही ले सकते। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार उनको सारे साधन जुटाती है। इंडस्ट्रीज के हिसाब से दिल्ली को कैपीटल नहीं माना हुआ लेकिन साधन के हिसाब से कैपीटल माना हुआ है। दिल्ली की सरकार यह पाबन्दी लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली के साथ–साथ लगते हुए 50 किलोमीटर के एरिया में कोई इंडस्ट्री नही लगेगी क्योंकि दिल्ली की पापुलेशन बढ़ रही है इसलिये उसका विकास करना है। डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी अजीब बात है। एक तरफ तो जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनकी प्रोडक्टस का फायदा उनको मिल रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार हमारे अधिकारों को कम करने के लिये पाबन्दी लगा रही है। तरह–तरह की कमेटी बैठा कर उनकी रिपोर्ट लेती है और कहती है कि चूकि दिल्ली की पापुलेशन बढ़ रही है इसलिए दिल्ली को आगे तक फैलाना है। लोगों को रहने के तिये जमीन चाहिये उनको जमीन देनी है। यदि इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो लोगों को रहने के लिये जमीन कहां से देंगे? दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा प्रदेश की जमीन लगती है उस जमीन पर यदि कोई इंडस्ट्रीयलिस्ट अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिये दिल्ली की सरकार कह रही है कि यहां पर इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ने कई बार उनके साथ

यह मुद्दा उठाया है। एक बार एन० सी० आर० की मीटिंग में मैं भी गया था। उस मीटिंग में मैंने खुद कहा था कि एक तरफ तो आप यह कह रहैं हो कि इंडस्ट्रीज नहीं लगनी चाहिये और दूसरी तरफ दिल्ली में इंडस्ट्रीज लगती जा रही हैं। हर रोज यहां पर इंडस्ट्रीज लग रही हैं। उस समय उस मीटिंग में मि० कपूर, जो दिल्ली के लैफ्टीनैट गवर्नर थे, कहने लगे कि हमने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने की इजाजत दे रखी है। बड़ी इंडस्ट्री लगाने पर हमने बैन लगा रखा है। मैंने कहा कि आप यह बात किसी अन–पढ़ आदमी के सामने कहैं तो दूसरी बात है अगर आप हमारे सामने यह बात कह रहैं हैं तो हम यह जानते हैं कि आज कुल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। यदि किसी इंडस्ट्रीयलिस्ट को एक बड़ी इंडस्ट्री लगानी है तो वह बड़ी इंडस्ट्री क्यों लगाएगा 7 वह एक बड़ी इंडस्ट्री की जगह तीन– तीन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लग लेगा। दिल्ली में इंडस्ट्रीज लग रही हैं जबकि दिल्ली में इंडस्ट्रीज लगाने पर बैन है। हमने उनसे कहा कि दिल्ली में इंडस्ट्रीज लगाने पर कम्पलीट बैन होना चाहिए तभी जा कर दिल्ली की पापुलेशन पर कुछ फर्क पड सकता है। फरीदाबाद दिल्ली के बौर्डर पर है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो जाते रहते होंगे और आपने यह भी देखा होगा कि फरीदाबाद बौर्डर पर एक गज दिल्ली की तरफ एक टैलीफोन लगा हुआ है। उस टैलीफोन से आप लंदन, वाशिंगटन मैक्सिको यानी किसी भी देश या प्रदेश मैं बात कर सकते हैं। उस टैलीफोन से किसी भी देश या प्रदेश की राजधानी और शहर में एक मिनट में बड़ी साफ बात कर

सकते है। दूसरी तरफ बौर्डर के एक गज अन्दर की तरफ जो हमारा टैलीफोन लगा हुआ है उससे आप दिल्ली भी बात नही कर सकते। इसलिए कोई इंडस्ट्रीयलिस्ट फरीदाबाद मे क्यों अपना दफतर खोलेगा? इडस्ट्रीयलिस्टस को तो टैलीफोन की सुविधा अवश्य चाहिए ताकि वह फरीदाबाद से दिल्ली बात कर सके और दिल्ली वाले फरीदाबाद बात कर सके लेकिन ऐसा नही है। फरीदाबाद वाले दिल्ली बात नही कर सकते और दिल्ली वाले फरीदाबाद बात नहीं कर सकते। किसी भी इडस्ट्रीयलिस्टस का काम टैलीफोन के बगैर नही चल सकता। जब तक टैलीफोन दूरी सुविधा में सुधार नही होगा तब तक इस बारे में कौई सुधार नही होगा। जब फरीदाबाद लें टैलीफोनों में बात करने की प्री सुविधा होगी तब ज कर दिल्ली की पापुलेशन पर कुछ फर्क पड़ेगा। जब तक वहां पर टैलीफोन की सुविधा ठीक नही होगी तो इंडस्ट्रीयलिस्टस अपना माल दिल्ली ले जाएंगे, अपने दफ्तर भी दिल्ली मैं खोलेगे और कारखाने भी वहां पर लगाएंगे। इस बात को पोलिटिकल तौर पर भी चौक नही किया जा सकता और न ही इसका कोई हल निकल सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, कन्साइनमैंट टैक्स के बारे में इतने साल हो गए, कोई फैसला अभी तक नही हुआ है इसके लिए सी० एस० टी० रुल्ज में अमैंडमैंट करनी पड़ेगी। वह अमैंडमैंट करके हमें अधिकार देना है और यह कहना है कि ठीक है कन्साइनमैंट टैक्स में इतनी परसैटेज आप ले लीजिए। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि यह कम और ज्यादा टैक्स की बात नहीं होनी चाहिए। यह कम

और ज्यादा टैक्स की बात क्यो है वह मैं बताता हूं। दिल्ली वालों ने तो टैक्स की दर इसलिए कम रखी हुई हैं क्यौंकि उनका खर्च बिल्कुल नही होता बल्कि उनको आमदनी होती है। मिसाल के तौर पर जो इंडस्ट्रीज हरियाणा में लगी हुई हैं उनको ऐस्टेब्लिश करने में तो हमने मदद की है लेकिन उनके सेल्ज औफिस दिल्ली में खुले होने के कारण हमें टैक्स का घाटा हो रहा है और दिल्ली वाले उसका फायदा उठा रहैं हैं। अगर दिल्ली वाले इन इंडस्ट्रीयलिस्टस को ये सारी सुविधांऊ बिजली,पानी और सड्कों वगैरा की जुटायें तो उनको अरबों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, किसी कारखाने को बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जून, 87 के चुनावों से पहले हरियाणा में विजली का क्या हाल था, वह आपको मालूम ही है। आपकी सरकार के सत्ता में आने के बाद अगले दिन यानी एक दिन बाद ही बिजली की पोजीशन हरियाणा में कैसे ठीक हो गई, यहू भी मैं आपको बता देता हू। उपाध्यक्ष महोदय, पहले हरियाणा राज्य की सारी बिजली दिल्ली वाले ले लिया करते थे। वे बहाना यह किया करते थे कि यह कैपीटल सिटी है, यहां पर जापान का प्रधान मन्त्री आता है, अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, फलां कला विदेशी राजदूत रहते हैं, फलां फलां फौरेन सैक्रेटरीज आते हैं और यहां दिल्ली में बड़ी बड़ी काफेसिज होती है जिनके लिए बिजली का कैपीटल मे होना बहुत आवश्यक है। कहते थे कि अगर बिजली नही होगी तो इससे देश की बदनामी होगी। इनको आनी बदनामी से अपना नाक कटने का खतरा था, बहाना तो दिल्ली वालों का

यह था जो मैंने बताया लेकिन असल में बिजली ये दिल्ली के कारखानों को देते थे। अगर उनको बिजली न मिलने के कारण अपनी नाक कटने का खतरा है तो बिजली की प्रोडक्शन वढ़ाने के लिए नए–नए प्लांट लगायें ताकि बिजली की कमी महसूस ही न हो। जब बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये प्लांट लगेगे तो बिजली की समस्या अपने आप खत्म हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पहले हरियाणा प्रदेश में जो नौमिनेटिड लोग थे, वे दिल्ली सरकार के थे। दिल्ली सरकार जिस प्रकार से उनका कान मरोड़ कर कोई काम करवाना चाहती थी करवा लेती थी, देहली के लिंए उनका इस्तेमाल कर लेती थी। उस समय हम यहां के बिजली मन्त्री से पूछा करते थे कि हमारी बिजली प्रधान मन्त्री यानी दिल्ली वाले क्यों खा रहैं हैं तो वे सीधा–सा एक जवाब दिया करते थे कि बिजली के तार मे जो करंट है उसको हाथ लगा कर मैने मरना नही है। यह मन्त्री पद चूकि हमें प्रधान मन्त्री से मिला हुआ है इसलिए हमारी जुबान कटी हुई है। इसलिये सवाल यह है कि जो बिजली की कटौती हो रही है उस कटौती को हम कैसे पूरा करें? पिछले सालों में बिजली की कटौती के कारण हरियाणा प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां के उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है, यहां के उद्योग एक तरह से तबाह हो गए थे। अब हम उन तबाह हुए उद्योगों को पांव पर खड़ा करने की कोशिश कर रहैं हैं। किसी उद्योग को खड़ा करने के लिए साधन की बात आ जाती है। साधन तभी होंगे जब पैसा होगा यानी साधन के लिए पैसे चाहिएं। पैसा टैक्स की मार्फत आता है। हमारे यहां पर

टैक्सिज ज्यादा हैं और दिल्ली में रिसोर्सिज मोबेलाइज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर टैक्स कम कर रखे हैं। हमने कई बार कहा है कि आप बराबर टैक्स क्यों नहीं करते? हमारे द्वारा बार–बार जोर डालने पर भी वे इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहैं। हमने कहा है कि इस मामले में हमको आपस में बैठ कर कोई फैसला कर लेना चाहिए। जो उचित और जायज बात निकलती हो, उसे एक बार तय कर लें और हरियाणा और दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में बराबर के टैक्स कर लें। चण्डीगढ़ की बात मैं इसलिये कर रहा हूं क्योंकि चण्डीगढ़ मे भी सारा बजट का पैसा सैन्ट्रल सरकार से आता है। इसलिए इन तीनों स्थानों के लिए बराबर के टैक्सिज कर दिए जायें तो फिर यहां के किसी भी कारखाने का मालिक दूसरी स्टेट में अपना माल बेचने की कोशिश नही करेगा या अपना सेल्ज औफिस दूसरी जगह पर नही खोलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में सैट्रल सरकार की नीयत खराब है। इसलिए वह ऐसा नही होने देना चाहती। डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुद फरीदाबाद जाते रहते हैं। वहां पर छोटी–बड़ी काफी इण्डस्ट्रीज हैं। फरीदाबाद मे बहुत बढ़िया कैल्वीनेटर फ्रिज बनता है जो भारत के तमाम प्रदेशों में भी जाता शै। यहं फ्रिज सब किस्म के लोगों के लिए है, चाहैं कोई इकोनोनिकली बीकर क्लास के लोग हैं, मीडिल क्लास के लोग हैं या अमीर लोग हैं, सब के लिए है। लेकिन दिल्ली में टैक्स कम होने की वजह से उन्होंने अपना औफिस दिल्ली में खोल रखा है। इस लिए वे अपना माल दिल्ली में ला कर बेचते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, कैल्वीनेटर

फ्रिज बनने में हरियाणा का तो नाम ही नाम है। कहने को तो यह. फ्रिज हरियाणा मैं बन रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में कैल्वीनेटर फ्रिज कम्पनी की लाईट जगमगाती रहती है और उसकी बड़ी शोहरत है लेकिन उसका फायदा सैंटर सरकार उठा रही है। हमें इसक। टैक्स नही आ रहा। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह फैक्ट्री हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद 'के अन्दर' लगी उस दिन न जाने किन–किन छोटे–छोटे जमीदारों की जमीन ली गई होगी, न जाने कितने लोगों को बेसहारा होना पड़ा होगा और उनकी आमदनी के साधन उनसे छिने गए होंगे। अगर उनकी आमदनी स्टेट गवर्नमैंट को जाती तो उन लोगों को सन्तोष होता और 'किसान सोचते कि चलो पैसा स्टेट को मिलेगा जिससे उनके लिए सड़कें बनेगी, पुल बनेगे, नहरे खुदेंगी वाटर वर्कस स्कीमे चलेगी और विकास के और कार्य होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वे किस बात पर सन्तोष करें? जिसके लिए उन्होंने अपने घर छोड़े, जमीनें छोड़ी, उससे जो आमदनी होती है वह सारी की सारी दिल्ली चली गई। इसी प्रकार गुड ईयर टायर बनाने की कम्पनी है। यह कम्पनी इतनी मशहूर है कि इनके बने टायर सारे देश के अन्दर सप्लाई होते हैं। उनकी भी यही हालत है। सामान तो बनता है हरियाणा में और बिकता है जा कर दिल्ली में। इस प्रकार जिस टैक्स पर हमारा हक है वह दिल्ली वाले ले जाते हैं। इन कम्पनियों के औफिसिज दिल्ली में नेहरू प्लेस और दूसरे प्लेसिज के अन्दर हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि दिल्ली की पापुलेशन कम की जाए दू सरी तरफ इस प्रकार की कम्पनियों के

औफिसिज को दिल्ली में बढ़ावा दिया जा रहा है। अकेले कन्साइनमैंट टैक्स की ही बात नही है। यदि ये औफिसिज हरियाणा मे बनें तो इनसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे पढे लिखे नौजवान जो बेकार घूम रहैं हैं, उनकों इन औफिसिज में काम. मिन सकता है। इस प्रकार यह हमारे रोजगार पर भी दिल्ली सरकार का आक्रमण है, अटैक है ताकि हरियाणा प्रदेश के लोग बेरोजगार रहैं। इन दफ्तरों के दिल्ली मे होने की वजह से सारे का सारा टैक्स सैन्ट्रल गवर्नमैंट के खजाने में चला बनाता है, जो कि नही होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में जो ट्रैक्टर बनते हैं उसका 70 प्रतिशत से भी फालतू हिस्सा हरियाणा में तनता है देश के अन्दर हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज ने बड़ा नाम कमाया है। डिप्टी स्पीकर, सर, दूसरी तरफ ट्रेक्टर इंडस्ट्रीज वाले बल्लभगढ़ में आगे से आगे और जमीन लेते जा रहैं हैं कभी 5 एकड़, कभी 10 एकड़ कभी 20 एकड़। इस प्रकार हमारी खेती की जमीन कम होती जा रही है और हमारे किसान बेघर और बेरोजगार होते जा रहैं हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि हमें हमारे साधन भी पूरे न मिलें तो हमारे साथ यह कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, हमें कितना नुकसान हो रहा है? लेकिन क्या करें वह टैक्स तो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली वाले तो यही चाहते हैं कि हमारे प्रगित की ओर बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया जाए। केन्द्र की आज यह कोशिश है कि इस छोटे से राज्य केजो सीमित साधन है उन साधनों को और सीमित कर दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह पुराने आकड़े हैं कि हमारी स्टेट को 50

करोड़ या 100 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान हो रहा है। आज की महंगाई को देखते हुए यह आकड़े कम पड़ते है। आज 150 या 200 करोड़ रुपये हर साल हरियाणा स्टेट को नुकसान हो रहा है। हमारी स्टेट का टोटल बजट 600 करोड़ रुपये का है और उसमें से 15 पौने 200 करोड़ रुपये का नुकसान हमें हो रहा है। यह नुकसान कोई थोड़ा नहीं है। इसलिए हरियाणा स्टेट के लिए यह चिन्ता का विषय बना हुआ है। केन्द्र राज्यों के साधनों को सीमित करके उन्हैं अपने काबू में रखना चाहता है। जैसे म्यूनिसिपल कार्पोरेशनें राज्य पर निर्भर रहती है, वैसे ही पैसे. के बल पर, गवर्नमैंट एड के नाम पर राज्यों को अपने काबू में रखने का खेल केन्द्र खेल रहा है। यह जो स्टेट्स के साथ ज्यादती हो रही है, चुनाव अप्ने वाले हैं और लोग इस ज्यादती को देख रहैं हैं कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट हरियाणा प्रदेश तथा दूसरे प्रदेशों का नुकसान कर रही है। आज एक–एक आदमी सोचता है, एक– एक पैसे का हिसाब रखता है, उसे मालूम है कि कहां क्या हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, आने वाले चुनाव में लोग देख लेंगे और एक–एक पैसे का हिसाब लेंगे। केन्द्र में जनता दल की सरकार होगी, वह दिन टूर नही है, जव आपकी सरकार कन्साइनमैंट टैक्स लागू करेगी हरेक स्टेट को उसका हक मिलेगा और सभी स्टेट्स को लाभ होगा। एक तरफ हम केन्द्र सरकार पर बार–बार दबाव डाल रहैं है कि कन्साइनमैंट टैक्स को लागू करो। दूसरी तरफ दूसरी स्टेट्स के लोग न जाने इस पर इतना जोर क्यों नही देते हैं? बडी बडी बैठकें होती हैं, प्लानिंग कमीशन की बैठकें होती है,

मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टरों की बैठकें होती है लेकिन इस मुद्दे पर जोर नही दिया जाता है। जिस समय यह संशोहधन संविधान में किया गया था, उस समय के प्रधान मन्त्री ने कुछ सोच कर ही यह संशोधन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, न मालूम इस देश के प्रधान मन्त्री की, इस लड़के की क्या सोच है ' उसे सोच लेना चाहिए कि थोडे ही दिन की सरकार है। अपने आखिरी दिनों में तो कम–से–कम कोई ऐसा काम कर दो जिससे जनता तुम्हारा बाद मे नाम ले कि वे हमारे प्रधान मन्त्री थे। डिप्टी स्पीकर सर, पिछले दिनों ऐसा हुआ कि फसल लहलहा रही थी, बरसात हुई और ओले पड़ गये, फसल को भारी नुकसान हुआ। ओले दिल्ली में भी पड़े और हमने युवा प्रधान मन्त्री अपने घर से वाहर निकले और ओलों पर चले। बर्फ पर चलने में उन्हैं बहुत आनन्द आया। फौरन अपनी पत्नी को बाहर बुलाया और बोले बाहर ओलों पर चलना अच्छा लग रहा है, काश ऐसा ही मौसम हर समय रहैं ताकि पिकनिक के लिये कहा बाहर न जाता पड़े। अजीब बात है एक तरफ किसान रो रहैं हैं कि ओलों से हमारी फसल नष्ट हो गई और दूसरी तरफ प्रधानमन्त्री जी पिकनिक मना रहैं हैं। उस आदमी को देश के बारे में कोई चिन्ता नही है कि किसानों का कितना भारी नुक्सान हुआ है।

श्री उपाध्यक्षः यह इन्फर्मेशन आपने कहां से ली?

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आप लोगों की वजह से मैं होम मिनिस्टर बना हुआ हू इसलिये कहीं न कही से

यह इन्फर्मेशन मिल जाती है और प्राईम मिनिस्टर से भी लोग मिलने के लिए जाते रहते है। लोगों ने ऐसे आदमी को भावनावश प्रधान मन्त्री बना दिया लेकिन उसे देश के बारे मैं कोई चिन्ता नही है। प्रधान मन्त्री कई बार तो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर आप भी नही जाते हो। वह तो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर न टेलीफोन है, न कोई साधन है लेकिन तम्बू में अपना बम्बू लगाने के लिए पहुंच जाता है और उसका वहां कोई मतलब नही हैं। यह आदमी बिना टेलीफोन और बिना साधनों के वहां घूमता फिरता रहता हैं और न जाने कैसे जानवरों के साथ खेल करता रहता है? वहां पर छोटे मोटे तालाबों में मछली पकड़ता रहता है, पता नही वहां क्या–क्या करता रहता है 1 इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसे आदमी पर तो चौक लगना चाहिए वरना इस देश को डुबो देगा। डिप्टी स्पीकर सर, जब देश को खतरा है चाहें वह देश के किसी पार्ट, जिले या गांव पर अटैक होता है तो इसका असर सारे देश पर पड़ता है।

जिस प्रकार से पंजाब में रोज वारदातें होती है। एक दिन में नौ –नौ और दस–दस वारदातें हो जाती हैं। कभी लोगों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, कभी दरखत पर टांग रहैं हैं और कभी कुछ कर रहैं हैं उसका थोड़ा बहुत असर हरियाणा प्रदेश पर भी पड़ता है। यहां पर भी कूछ वारदातें हुई। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा पुलिस ने जबरदस्त मुकाबला किया। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी का नेतृत्व था, सिपाहियों की पीठ पर

उनकी शाबाशी थी। उन्होंने बडे ढंग से लड़ाई लड़ी और मुकाबला किया। सारे आतंकवादियों को या तो मार दिया या वे जेलों में सलाखों के पीछे है लेकिन फिर भी, डिप्टी स्पीकर साहब, हम यह सोचते हैं कि कभी भी ऐसी कोई घटना हो सकती है, इसको रोका तो जाना चाहिए। वार–बार हैंम उनसे मांग करते हैं कि हमें हथियार दिये जायें। यह ठीक है कि हमारे नौजवानों का दिल मजबूत है क्योंकि चौधरी देवी लाल जी का उनकी पीठ पर हाथ है और उसकी वजह से ही वे लडाई लड़ रहैं है। पिछले दिनों काली रातों में बहुत ज्यादा सर्दी थी, कोई आदमी बाहर नहीं निकलता था लेकिन हमारी पुलिस बाकयदा पैट्रोलिग कर रही थी। हमारी पुलिस सड्कों, नहरों कें किनारे और बौर्डर पर दिन राव घूम रही थी। जब हम उससे हथियार मांगते है तो इन्कार कर दिया जाता शै। हमें नौजवानों की नफरी न दे रहैं हों तो हथियार तो दो। नौजवान हम अपने तैयार कर रहैं है लेकिन हमें हथियार तो दो। डिप्टी स्पीकर साहब, सैन्टर हमारे साथ मजाक करता है। हमने 1700 एस० एल० आर० नागी उसके बदले में 50 पकड़ा दी। अजीब मजाक है। इससे बटा मजाक हमारी स्टेट के माथ और क्या हो सकता है ? ये सोचते हैं कि केवल हरियाणा की सुरक्षा को खतरा है। मैं राजीव गांधी को चेतावनी देना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा को कोई खतरा नही हौ सकता।

श्री उपाध्यक्षः आप प्राईम मिनिस्टर को बोलें।

प्रो० सम्पत सिंहः ठीक है। प्राईम मिनिस्टर साहब को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा नही हो सकता। यहां का हर बाशिन्दा, हर नर–नारी उग्रवाद के खिलाफ लड़ रहा है और कतई तौर पर उनकी परवाह नही कर रहा है लेकिन हरियाणा प्रदेश को हथियारों की जरूरत है, प्रदेश को कारबाईन की जरूरत है, वायरलैस सैटस की जरूरत है, एस० एल० आर० की जरूरत है, हम सैन्टर से बार बार मांग करते है लेकिन वह तमाशा देख ' रहा है। हरियाणा प्रदेश में यदि ऐसी वारदातें होती रही तो फिर दिल्ली का क्या बनेगा? इसलिये प्रधान मन्त्री को इस बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली को हरियाणा प्रदेश ने दो बार बचाया है। एक बार तो जब सूखा पड़ा था तो दिल्ली में पानी की दिक्कत आ गई थी। लोग लोटा–बाल्टी लिए हुए सड्कों पर फिर रहैं थे, लोगों के फ्रिज सूख गये थे, कही पानी नही मिल रहा था, खुद प्रधान मन्त्री के निवास पर पानी की कमी आ गई थी। यह कांग्रेस सरकार, इस देश के श्वान मन्त्री के जीवन को भी खतरें में डाल रही थी। वहां पर दिल्ली में दूध तो मिलता था लेकिन गिनी नही मिलता था। चौधरी देवी लाल को चिन्ता हो गयी कि कहीं देश का प्रधानमन्त्री अगर कंठ सूखने की वजह से मर गया तो देश की नाक कट जायेगी और बदनामी आयेगी इसलिये चौधरी देवी लाल ने अपने किसानों का पानी दिल्ली को पीने के लिये दिया। तब जाकर इस देश के प्रधान मन्त्री को पीने के लिये एक गिलास पानी का मिला वरना तो वह मर जाते।

श्री हीरा नन्द आर्यः वहू तो डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः वह तो ठीक है लेकिन पानी होगा तभी तो उसको डिस्टिल्ड किया जायेगा। डिस्टिल करने के लिये कारखाना लगाना पड़ेगा और जब कारखाना लगेगा तो कन्साइनमैंट टैक्स भी लगेगा। मैं उदाहरण दे रहा था। दूसरा उदाहरण मैं एक और देना चाहता हूं। एक बार दिल्ली की तरफ ट्रक में कुछ उग्रवादी जा रहैं थे अम्बाला बौर्डर पर आपकी पुलिस ने उनको रोका। उनके हथियार जब्त किये। लोगोको भी पकड़ा और जो कम्पनी हथियार सप्लाई करती थी, उसको भी ऐक्सपोज किया वरना दिल्ली में बहुत तबाही हो जाती। उनको अपने घर को बचाने के लिये तो हरियाणा को मदद करनी चाहिये लेकिन वह दिल्ली को अपना घर नहीं मानते। वह तो कहते हैं कि राजगद्दी है, जितने दिन मौज ले सकते हो, ले लो, 'उसका शोषण करते रहो, जब यह दिल्ली किसी काबिल नहीं रहैंगी तो वह इसे छोड़ कर इटली चले जायेंगे। इस किस्म के मनसूबे उन्होंने बनाये हुए हैं। इस देश की सुरक्षा को कितना खतरा पैदा हो सकता है, अगर किसी को यह सोच हो, इसका अन्दाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इस देश का बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है। पालीटीकल प्रोसैस के लिये, हैल्दी डैमोक्रेसी के लिये, अपोजीशन की भी जरूरत होती है। उसके बिना बात नही बनती। अपोजीशन का आदमी अगर कोई आवाज उठाये तो उस आदमी की आवाज का भी कोई मतलब होता है। पिछले दिनों कुछ ऐसी बात सुनने में

आयी है। अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने देश के लिये आजादी की लड़ाई लड़ी है, वे स्वतन्त्रता सेनानी आज ज्यादातर देश की अपोजीशन में हैं। जिन लोगों की उस समय उम्र 15–20–25 या 30 साल की थी, आज उन स्वतन्त्रता सेनानियों की उम्र 65–70 – 75 या 80 साल के लशभग हो रही है। उन सारे के सारे लोगों ने उस वक्त देश के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था। आज वे लगभग सारे ही अपोजीशन पार्टीज में हैं। गिनती के ही कुछ लोग कांग्रेस में हैं, तो हैं वरना कांग्रेस में तम्भू –बम्बू वाले, फिल्मों वाले या दून स्कूल के लोग हैं। जो दून स्कूल के लोग हैं, वे तो इस देश की आजादी के बाद की प्रोडक्शन हैं। वे इस देश की आजादी के बाद इस संसार में आये हैं। एक तरफ तो वे लोग हैं और दूसरी तरफ जो सारे स्वतन्त्रता सेनानी है वे कांग्रेस की अपोजीशन में हैं। ये उन लोगों को यह कह रहैं हैं कि ये तो देशद्रोही हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस किस्म के आदमी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में यह कहते हैं कि ये देशद्रोही लोग है। अगर कोई कन्साइनमैंट टैक्स की बात कह दे तो क्या कोई देशद्रोही हो जाता है? लोगों के हितों की बात करने या प्रेदेश के हितों की बात करने से क्या कोई देशद्रोही हो जायेगा ? प्रदेश का हित अल्टीमेटली नैशनल इन्ट्रैस्ट है। अगर हरियाणा के लोग खुशहाल हैं, हरियाणा में प्रगति होती है, हरियाणा का विकास होता है, हरियाणा से बेरोजगारी दूर होती है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि यह देश के हित की बात है। आज देश के अन्दर क्या हो रहा

है? एक उदाहरण देने की मैं कोशिश करूगा। जिन लोगों ने 1947 से पहले देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई लडी, चाहैं वह किसान हो, जो खेत में काम करता था, या चाहैं वह गरीब मजदूर हो, चाहैं उसने राजनैतिक मूवमैंट में भाग लिया हो या न लिया हो, उनकी उम्र उस समय 15, 20 या 25 साल की रही होगी। ऐसे एक नही लाखों–करोड़ों लोग है। उनकी अब उम्र बहुत ज्यादा हो गयी है। उनके दिमाग में देश के बारे में एक सपना था उन्होंने बिना सोचे समझे यह लडाई नही लड़ी थी। उन्होंने सोचा था कि अगर देश तरक्कीकरेगा तो मैं भी तरक्की करूंगा और सारा देश खुशहाल होगा लेकिन नतीजा यह निकला कि आज सारा देश गरीबी के शिकंजे में फंसा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कही पर तो यह पोजीशन है कि मां और बेटी के पास एक ही साडी है और एके कही होने के कारण मां अगर काम पर जाती है तो वह साडी मां पहन कर जाती है और अगर बेटी काम पर जाती है तो बेटी उस साडी को पहन कर जाती है और मां अपनी झोंपडी में रहती है। ऐसी अवस्था अन्य। इस कांग्रेस सरकार ने कर दी है। दूसरी तरफ वे लोग जिनकी उमर 65 और 70 साल की हो रही है, जिन्होने इस देश के लिए आजादी की लडाई लड़ी, देश को स्वाधीन कराया उनकी कोई पर्वाह नही कर रहा था। न यह कांग्रेस सरकार परवाह कर रही थी और न ही देश परवाह कर रहा था सौभाग्य से इस प्रान्त मे चौधरी देवी लाल की सरकार आई और चौधरी देवी लाल जो स्वयं स्वतन्त्रता सेनानी रहैं है, का ध्यान इन लोग की तरफ गया। चौधरी देवी लोग ने इन लोंगो की

परवाह की, उनका इन लोगों की तरफ ध्यान गया और चौधरी देवी लाल ने सौ रुपया मासिक उनको पैन्शन दे दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह मासिक पैन्शन सम्मान है और स्वतन्त्रता संग्राम मे भाग लेने का मैडल है। कांग्रेस नौ जो एम० पी० है और यह जो राजेश पायलट आदि है वे इन बातों को क्या जानें? इस बात दरों केवल चौधरी देवी लाल ही जान सकते हैं। इसीलिए हरियाणा में आठ लाख लोगों को स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिए पैन्शन देकर सम्मानित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इंग्लैड और अमेरिका मे जाए तो सब से पहले इस काम के लिए देश को नाम आएगा कि हिन्दुस्तान ऐसा देश है जिसके अन्दर स्वतन्त्रता संग्राम मे भाग लेने वालों को इतना रुपया मासिक सम्मान के रूप में दिया जाता है। उसके बाद आएगा कि कौन सा प्रदेश हैं और कौन सा मुख्य मन्त्री है जिसने इन लोगों को सम्मानित किया है। कभी–कभी स्टेट को नुक्सान पहुंचाने के लिए अनजाने मे ये देश का नुक्सान भी कर बैठते है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सारा सदन चिन्तित है, सारा प्रान्त चिन्तित है और सारा देश चिन्तित है कि पिछले सात साल से कांग्रेस की सरकार और दिल्ली की यह सरकार कांस्टीच्यूशन में कोई अमैंडमैंट नहीं कर रही है। इस बात की परवाह नहीं की जा रही है कि स्टेट्स का कितना नुक्सान अमैंडमैंट न करने से हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, भाई रणजीत सिंह का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे वरिष्ठ साथी गृह मन्त्री प्रो० सम्पत सिंह जी ने बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इसका ताल्लुक केवल हरियाणा से ही नही है बल्कि यह पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार एक सतत चरनने वाली संस्था है। राजनीति में लोग आते हैं और चले जाते हैं। देश की जनता पर वे क्या प्रभाव छोड़ते हैं यह उनके काम से जाहिर होता है। कई बार जब हम कांग्रेस के माननीय सदस्यों की आलोचना करते है तो कहा जाता है, कि हमारे०पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी संख्या थोड़ी है इसलिए यह आलोचना की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप पिछले सदन में भी थे। यह प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के माननीय सदस्यों की रूचि क्या है यह उनकी अनुपस्थिति से जाहिर हो जाता है? उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश को पचास करोड़ की हानि लगभग प्रति वर्ष हो रही है। 1625 में ईस्ट इंडिय कमानी नाम की संस्था यूरोप से चलकर भारत में यानी कलकला में आई। उसका मकसद केवल अपना व्यापार बढ़ाना था लेकिन उन्होंने देखा कि देश आपस में बंटा हुआ हैं इसलिए उन्होंने देखा कि यहां पर राज्य भी किय जा सकता है और हम सत्र जानतें है कि दुर्भाग्य का दिन भारत की जनता को देखना पड़ा। आज की सरकार, जो दिल्ली में बैठी है, ने उपाध्यक्ष महोदय, 1982 में संविधान में तृक प्रावधान किय और बाकायदा

एक प्रोवीजन 46वें संशोधन के माध्यम से उसमें जोड़ दिय (गय (कि प्रान्त की सरकारों के कार्य क्षेत्र में जो उत्पादन होगा चाहैं कारखाने करें, चाहैं कोई छोटा उद्योग करे और चाहैं बडा उद्योग करे, जो चीज विरा धरती पर बनती है उसका उत्पादन शुल्क और क्रय विक्रय शुल्क इकट्ठा करने का वहां की सरकार को अधिकार रहैंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, बडे दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि आज हम 1989 में जी रहैं हैं। लग मग सात वर्ष इस बात को हो गये हैं। पांच और छः साल के बाद सरकारें बदलने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। किसी भी राजनीतिक दल और व्यक्ति की जो परफोमेन्स है उसकी जो कार्यशैली है, उसको बदलने के लिये भारत के लोगों ने पांच साल का समय रखा है। द्वारे देश में आजादी के बाद कई प्राईम मिनिस्टर आये हैं और हर प्राईम मिनिस्टर के कुछ दोप और गुण रहैं होंगे। हर प्राईम मिनिस्टर की पहचान यह देश किसी न किसी नाम से करता रहा है। उपाध्यक्ष जी, व्यक्ति तो एक नश्वर चीज है। उसने तो आना है और चले जाना है परन्तु जो व्यक्ति जितनी देर जितनी जिम्मेवारी पर रहता है उसकी जिम्मेवारी और उसके काम उतने ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं और उस आदमी के अपने काम देश के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अच्छे काम अच्छा प्रभाव छोड़ जाते हैं और बुरे काम बुरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भले ही हमारी राजनीतिक विचारधारा जवाहर लाल जी से कुछ मतभेद रखती हो परन्तु आजादी के बाद एक महान् स्टेट्समैन का दर्जा उन्होने लिया। उन्होंने देश को एक एर सी दिशा में बढ़ाया

कि सद्भाव की भावना उनके समय में ही स्थापित हुई। उनके बाद आये श्री लाल बहादुर शास्त्री। वे थोड़े से दिन रहैं। वह एक छोटे कद का बड़ा आदमी साबित हुआ। 18 मास का एक छोटा सा काल उन्होंने इस बड़े देश के प्राईम मिनिस्टर के तौर पर काटा और इतने थोड़े अर्से में उन्होंने बहुत कुछ किया। पाकिस्तान के साथ सिद्धान्तों पर लड़ाई लड़ी और देश के अन्दर जो अकाल पड़ा था, उसका सामना उन्हैं करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, हाथों को मजबूत करने के लिये खून चाहिये और खून के लिये आदमी को अनाज चाहिये परन्तु उस समय अनाज का संकट भी हमने महसूस किया। अनाज न देने के लिये अमरीका ने हमें चेतावनी भी दी परन्तु धन्य हैं श्री लाल बहादुर जी शास्त्री, जिन्होने ऐसी परिस्थिति में देश के मनोबल को०ंचा किया। उन्होंने कहा कि हम हर सोमवार के सोमवार भूखे रहैंगे लेकिन भीख का कटोरा लेकर अमरीका के पास नहीं जाएंगे। पूरे देश ने इस बात को स्वीकार किया। भारत की मिट्टी की पहचान तो वे अच्छी तरह से जानते थे। भारत के स्वाभिमान को जगाने का मनोबल उनके दिल में था। हमने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में दो बातों का सामना किया। एक अनाज के संकट का और दूसरा हमने पाकिस्तान को सरहद के०पर झेला। उन्होंने ''जय जवान जय किसान'' का नारा देकर सारे देश को जगा दिय था। देश की आने वाली पीढ़ियां इतिहास में उनके स्वर्ण युग को ध्यान में रखेगी। उसके बाद इन्दिरा जी का युग

आया। उनका युग कुछ विवादास्पद रहा चर्चा में रहा लेकिन एक बात उनकी भी यह भारत याद रखेगा। She was a lady who could decide a thing. वे फैसला करना जानती थी चाहैं अच्छा हो या बुरा हो। वे मामले को लम्बा नहीं लटकाती थीं। अब उनके बाद उनके प्रिय बेटे श्री राजीव गांधी आये। आज वे इस देश की 78 करोड़ जनता के प्रधान मन्त्री हैं। प्रधान मन्त्री होने के नाते हम उनका आदर करते हैं परन्तु उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण मामले सरकार की प्राथमिकता होती है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब पिछले सदन में सभी इकट्ठे थे। हम सब ने मिलकर संघर्ष किया। हमारे कुछ चुनाव वायदे थे। सड्कों पर, गांव की चौपालों में, दरख्तों के नीचे हमने लोगों को इकट्ठा किया, समझाया, अपने साथ लिया था और उसके बाद आप जानते हैं कि अपनी सरकार की प्राथमिकता क्या रही थी। हमने सूखे के दिनों में लोगों की हर मुमकिन सहायता की है। प्रोफेसर सम्पत सिंह जी ने ठीक ही कहा था कि दिल्ली प्यासी थी, हरियाणा के तीन जिले प्यासे थे। 1987 का समय मुझे याद है। सौभाग्य से, मैं बस इलाके से ही सम्बन्ध रखता हू जहां पानी की सब से ज्यादा कमी थी। पानी का जल स्तर 400 फुट नीचा था। पीने के पानी की जो पुरानी व्यवस्था थी, वह सब समाप्त हो चुकी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी देवी लाल जी की सरकार को इसके लिये बधाई देना चाहता हू कि इस हाहाकार के समय में पानी का संकट हरियाणा के लोगों को महसूस नही हुआ था। पूरी व्यवस्था को दुगना करके, जंगलाद के टैकों से पानी देते थे। प्राथमिकता के आधार पर हरियाणा के

हाली और पाली की रक्षा हमने की थी। हमने यह कहा था कि यह सरकार आने, के बाद चौधरी देवी लाल जी के सत्ता संभालने के बाद, हम बुजुर्गो का सम्मान करेंगे। यह भारत की विशेषता थी। भारत में जो बुजुर्ग है उनके महान मानते है। हाव की भाषा में जब कोई नई वह घर में आती है और सामान्य रूप मे परिवार में चची –गलती है तो उस ब्हू को कोई बूढ़ी मां कह देती है कि देखे बच्ची गंगा यमुना तीर्थ नही होते हैं बल्कि बूढ़े सास और ससुर तीर्थ होते है। हमने ठीक हरियाणा की रिवायतों को कायम रखा हुआ है। लोग हरियाणा की परम्पराओं के सामने सिर झूकाते हैं। आज हफ्ते हरियाणा में 8 लाख बूढे मां बाप का सम्मान किया है यह हमारी प्राथमिकता है। चाहैं कोई भी राजनीतिक मुद्दा आता रहैं, हरियाणा के लोग इसको नही भूल सकते। दुनिया के लोग याद करेंगे कि हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है, जहां राजनीति करवट बदलती है, हरियाणा दुनिया के लोगों को राजनैतिक दिशा देता है। चाहैं महाभारत का समय था या खैबर दर्रे से सोम नाथ के मन्दिर को लूटने का समय था या मुहम्मद गौरी को पानीपत मे रोकने का समय था, हम उसका मुआवजा नही लेना चाहते। लेकिन आज दिल्ली के लोग अभिमानी हो गए है, वे हमें भिखारी बनाना चाहते है। उपाध्यक्ष महोदय, वह खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रधात मन्त्री जी हो सकता है कल को प्रधानमंत्री न रहैं। हिन्दुस्तान दुनिया मे सब से महान प्रजातन्त्र देश है। उपाध्यक्ष महोदय, 1975 मैं कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई। उस समय जब हम जेल मे थे तो हमे जेल के दरोगा मजाक किया करते थे

कि तुम्हारी उमर अभी बहुत कम है, जिन्दा रुहने के लिए कोई और सोर्स सोचो। उसके बाद जब जनता वोट डालने के लिए जा रही थी तो हमें कहा गया कि कोई. दूसरा सक्ता देखो तीन दिन के बाद इन्दिरा जी फिर आने वाली है। उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी जिन्दगी का ख्याल करे। उन दिनों मेर मुझे बिहार की गया जेल में रहने का मौका मिला था। उस, समय क्तने दरोगा से कहा था कि तुम हमारे जिन्दा रहने या मरने की बात छोड़ दो। हमने कहा देश की जनता कम से कम उस प्रधान मन्त्री को जरूर हटाएगी जिसने देश में प्रजतन्त्र खत्म करने का एलान किदार। हमारा स्वप्न साकार हुआ। भारत कीं जनता ने वैसा करके दिखा दिया। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नही, है जहां का प्रधान मन्त्री इलैक्शन में हारा हो, उनके साथी तो हार जाते हैं परन्तु वह स्वयं नहीं हारता लेकिन धन्य है हमारे देश की जनता जिसने उस समय की प्रधान मन्त्री को चुनाव में पटक दिखाया। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि चाहैं प्रान्त की सरकार हो और चाहैं, देश की सरकार हो, हमे अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए। प्रदेश की सरकारों के बारे में यह नही समझना चाहिए कि वे उनकी गुलाम हैं बल्कि उनको सनका पूरा हक देना चाहिए। कोई प्रदेश विकास नही करेगा तो वहां के लोगों के चेहरे खुबसुरत नही होंगें, बच्चो के चेहरों पर मुस्कराहट नही होगी। अगर प्रदेश विकास नही कर सकेगे तो भारत भी विकास नहीं कर सकेगा। विकास के लिए आर्थिक साधनों की जरूरत है। आर्थिक साधन उत्पादन से आते हैं, औद्योगीकरण से आते हैं। हम हरियाणा के लोगों को सौभाग्य

प्राप्त है मिन हम दिल्ली के पास है हमारी भागौलिक स्थिति ऐसी है, हमारे लोग इतने मेहनती है, कि हम हरियाणा को औद्योगिक, क्षेत्र, में सब से आगे लाना, चाहते है लेकिन हमारे रास्ते, मे कन्साइनमैंट टैक्स की रुकावट डाल रखी हूँ। कोई भी मामला हो केन्द्रीय सरकार आ हमारे प्रति सोचने का तरीका ही दूसरा है। भाई सम्पत सिंह जी के पास कर विभाग भी रहा है, वे कह रहैं थे, कि हम पंजाब के पडोस में बसते हैं, उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है बेटी, और रोटी का रिश्ता है, हम एक तरह से रहते हैं, आटे खेतो का जलवायु एक है हम एक नदी का पानी, पीते है और हमारी खेत की जमीन के डोत मिलते है। जब कोई आग उधर लगती है तो उसकी तपश हमारे खेतों तक पहुचती है हमारे बदन तक पहुंचती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज पांच साल हो गए इतने खुशहाल पंजाब, में लहलाते पंजाब में, नाचते गाते पजांब में भगडा करते पंजाब में उग्रवाद की आग लगी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय हरभजन सिंह एक कवि है उन्होने बड़े जजबाती अलफाज में कहा था कि–

नी मां मैं सुनया अमृतसर एक गुरुद्वारा

सोने दीआं, ओहदीया इंटा, चांदी दा, लिगलया यारा

पर मैं कदी न सुनिया गुरुमत दा हुदा बंडारा।

यानों गुरुओ ने जो शिक्षा दी उसको भी काग्रैंस की सरकारें बांट कर खा रही है। जिस, स्वर्ण मंदिर में लोंग अपने

पापों का सकंट मिटाने के लिए आशीर्वाद लेने जाते थे, जिस स्वर्ण मंदिर में लोग मानसिंक तानसिक, और अधयात्मिक आशीर्वाद लेने के लिए जातें थें, आज वहां गोलियों की बौछार होती हैं। सुबह लोग अपने घर से निकलते हैं, शाम को वापिस अपने बच्चो के पास नही पहुंच पाते। ऐसी दर्दनाक और वेदनापूर्ण घटनाए पंजाब की धरती पर हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज, पंजाब मै ऐसें हालात हो रहैं हैं जिसका कोई हल नहीं है। एक मजदूर मजदूरी करने के लिऐ गया और जब वह रोटी खाने के लिए दोपहर को अपने घर लौटा तो उसकी मां ने कहा बेटा मैं तेरी सुबह से इन्तजार कर रही हूं तू रोटी खाने के लिए क्या नही आया। तो उस मजदूरी ने अपनी मां से कहा कि मां बड़ी भूख लगी है। मां नें कहां अच्छी बेटा मैंने सब्जी नहीं बनायी, तू बाजार से दही भल्ले ले आ, मैं तेरे लिए रोटी सेकती हूं। वह मजदूर कच्छे बनियान में, मिट्टी से लथपथ शरीर में ही बाजार से दही भल्ले लेने जाता है। एक अनचाही गोली उसके बदन से निकल जाती है और वह दही भल्ले समेत वहीं पर ढेर हो जाता है। उसकी मां थाली में रोटी परोस कर लाती है, उसे पता लगता है कि उसका लाल तो खत्म हो गया है। जब लोग उसको दाहसंस्कार के लिए कंधों पर उठा कर चलते हैं तो पीछे सै वह मां थाली में रोटी परोस कर दही भल्ले रख कर ले जाती है और कहती है ए लोगों मेरे बेटे को भूखा तो शमशान घाट पर मत ले जाओ इसको रोटी तो खिला कर ले जाओ। वह मां हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से पूछती है कि बताओ मेरे बेटे का दोष क्या है

उपाध्यक्ष महोदय, हम इन्सान हैं। आदमी और पशु में इतना अन्तर है कि आदमी संवेदनशील है और पशु सोचता नहीं है। पशु के पास विवेक नही है, वह फैसले नही कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, क्या पंजाब मे यह घटनाक्रम पिछले पांच साल से बंद नहीं होना चाहिए था, क्या यह प्राथमिकता का विषय नही था? क्या 1984 के लोकसभा चुनावो में श्रीमान राजीव गांधी ने हिन्दुस्तान के हर चौराहैं से इस बात को बुलंद नहीं किया था कि जो विरोधी पक्ष के लोग है, जो भारतीय जनता पार्टी, लोकदल और जनता दल के लोग हैं ये आनन्दपुर प्रस्ताव का समर्थन करते है? पंजाब की समस्या का हल मेरी जेब में है, में उसको दो मिनट में हल कर सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि भाई राजीव गांधी की या तो वह जेब कट गई, या ध्यान कट गया है, कुछ न कुछ कट जरूर गया है वरना इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता। पर, इस काल खण्ड में हजारों लोग इस दुनिया से चले गए, पंजाब में किलकारिया है। हजारों बेटों के सिर से बाप के साए उठ गए, हजारों बहनों के मांग के सिंदूर मिट गए, हजारों बुजुर्गों की लाठी के सहारे टूट गए हजारों माताओं की गोद खाली हो गई लेकिन इस देश का प्रधान मन्त्री पंजाब में आने लायक नहीं हैं। प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी, पंजाब में एक बार आ करके तमाशा करके चले गए। इस देश का प्रधान मन्त्री जा सकता है हिन्दुस्तान के कलाकर अमिताभ बच्चन के घर, हम अमिताभ बच्चन के विरोधी नही है क्योंकि वह मेरे कद का आदमी हैं। वह यदि बीमार हो जाए तो इस देश का प्रधान मंत्री उसको

मिलने के लिए विदेशों की याता छोड़ कर जा सकता है परंतु इस देश के प्रधान मंत्री को पंजाब में आने की फुरसत नही है। पंजाब में सरदार हरचंद सिंह लौगोंवाल कत्ल हो जाए, पंजाब मे भाजपा के प्रधान हितअभिलाषी कत्ल हो जाए, पंजाब में कृष्ण लाल मनचंदा कत्ल हो जाएं पजाब में सरदार अवतार सिंह अटवाल, डी० आई० जी० कत्ल हो जाएं, कोई कत्ल हो जाएं लेकिन इस देश के प्रधान मन्त्री का दिल इतना संवेदनशील नही है कि वह पंजाब में आएं। उनको किसी के मरने औंर जीने के बीच में कोई फर्क मालूम नहीं है। इस देश के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को देखने उसके घर जा सकते हैं। हिन्दुस्तान की सरहदों के रक्षक, हिन्दु स्नान के सूरमा सिपाही जनरल वैद्य को पूना में अनाथ आदमी की तरह गोली मार दी, इस देश का प्रधान मन्त्री उसकी लाश को कंधा देने लायक नहीं हुआ। भाई राजीव गांधी की हवाई अड्डे पर एक फौजी हैलीकौप्टर इंतजार करता रहा कि इतने बड़े देश का सेनापति इन हालति में मारा गया है तो जरूर इस देश के प्रधान मंडी उसकी लाश को कंधा देने के लिए जाएंगे। यह सोच कर सेना का हैलीकौप्टर हवाई अड्डे पर इन्तजार करता रहा लेकिन दुर्भाग्य है मेरे देश का, इस देश के प्रधान मंत्री को ताश खेलने से फुरसत नहीं है वहां कैसे जा सकते थे? प्रधान मंत्री जनरल वैद्य की लाश को कंधा देने के लिए नहीं गए। अगर प्रधान मन्त्री जनरल वैद्य की लाश को कंधा देने के लिंए नहीं गए तो यह जनरल वैद्य का अपमान नहीं है। जनरल वैद्य ने अपने कर्तव्य पर अपनी जान की कुर्बानी दी है। जनरल वैद्य की आत्मा

आज स्वर्ग में सुख से है। उनकी आत्मा को संतोष है कि उन्होंने अपने हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए अपने जवानों को संकट की घड़ी में आदेश दिया था। स्वर्ण मंदिर पर बल्यू स्टार आप्रेशन का जो फैसला था वह जनरल वैद्य का फैसला नहीं था। इस देश में फैसले राजनीतिक लोग लेते हैं और हमारी सेना उन फैसलों की पालना करती है। इस देश की सेना इतनी वफादार है, इस देश का सिपाही इतना वफादार है कि हर राजनीतिक फैसने पर अपनी जान की बाजी लगा. देता है। लेकिन दुर्भाग्य है राजीव गांधी की राजनीति को, इस देश की राजनीति को, जिसके द्वारा किए हुए फैसले पर जिस आदमी ने अपना सिर चढ़ा करके स्वागत किया उस आदमी के अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिए इस देश का प्रधान मंत्री न जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हम जजबाती आदमी हैं, हमारे साथ बदसलूक होता है, केवल कन्साइनमैंट टैक्स में ही नही, पहले बाढ़ आई, फिर सूखा पडा उसमें भी ऐसा ही हुआ। हमारे प्रदेश में सूखा था जिसके लिए हमें केन्द्रीय सरकार की ओर से केवल 32 करोड़ रुपए का रिलीफ मिला जबकि राजस्थान प्रान्त को 488 करोड़ रुपए मिले। राजस्थान को 488 करोड़ रुपए मिलने पर हमें कोई दुख नहीं, राजस्थान हमारे प्रान्त से बड़ा प्रान्त है। राजस्थान में सूखे के कारण हमसे ज्यादा तबाही हुई है। उनकी यह तबाही हमने अपनी आखों से देखी थी। मैं और चौधरी देवी लाल जी जब राजस्थान के इलाके बीकानेर जा रहैं थे तो रास्ते में हमें पशुओं के देर के ढेर मरे नजर आये। हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से यह दृश्य देखा नही गया। हमने उन लोगों को देखा,

रनों वहां नर जमा हुए थे। हम उन के पास गए। चौधरी देवी लाल जी के मन में किसानों के प्रति वे दूसरे के प्रति कितना दर्द है उसी संबंध में मैं यह बात कह रहा है। जब हम उन लोगों के पास गए तो चौधरी देवी लात जी ने पूछा कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो तॉ वहां पर एकदम 40–50 नर–नारियों का झुण्ड हमारे पास इकट्ठा हो गया। जब हमने उनके चेहरों को देखा तो उनके चेहरे मुरझाये हुए थे। मैं कह रहा था कि जब हमने उनसे पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो तो वे कहने लगे कि हुन जव घर मे चने तो अपने साथ 100 डंगर लेकर चले थे लेकिन 10 कभी मर गए, 20 कभी मर गए, 40 कभी मर गए और अब सभी मर गए हैं। वे यह भी कहने लगे कि जब हम अपने घर से सूखे के कारण निकले तो अपने बच्चों को कह करे आये थे कि जब आसमान में बादल आएंगे और पानी बरसेगा तो जितने पशु हमारे पास बाच पाएगे उनको वापस जाकर अपनी जिन्दगी दुवारा नए सिरे से शुरू करेगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं एक किसान के बेटे हैं। आपको पता है कि किसान के लिए पशु सबसे बडी दौलत है। किसान अपने पशु को अपने बेटे से ज्यादा प्यार इसलिए करता है क्योंकि उसकी मफ्ता उसमें चली जाती है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि जब हम यहां पर एक जगह पर सरकारी कैम्प में ठहरे हुए थे तो राजस्थान सरकार की तरफ से पक पशु के लिए तीन सेर तूडी एक दिन के मिप मिलती थी। इसमे से पक सेर तो चला गया कांग्रेस की राजनीति में। बाकी दो सेर मे से आधा सेर मिट्टी है और बाकी जो डेढ़ सेर तुड़ी बची उससे क्या

एक दिन कें 'लिए एक पशु का काम चल सकता है? उससे चूंकि पशु का पेट नहीं भर सकता इसलिए हमारे सारे पशु धीरे धीरे मरते चले गए। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने हमारे सीथ तो भेद भाव के आधार पर सूखे के नोम पर बहुत कम सहायता दी थी लेकिन केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को 488 करोड़ रुपये की सहायता दी थी। उन 438 करोड़ रुपयों का क्या हुआ यह हम उनकी ही राजनीति पर छोड़ते हैं रै मेरे कहने का भाव यही है कि इतने पैसे मिलने पर भी वहां की सरकार अपने लोगो के लिए व वहां के लोगों के पशुओं के लिए कुछ नही कर पाई। इस दहस में हम नही पडना चाहते कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। एक बात मै अवश्य कहना चाहूंगा कि उस सूखे के दौरान राजस्थान के 80 फीसदी लोगों की पशु पूंजी मारी गर्म थी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे, कहने का मतलब यह है कि हमारे हरियाणा में बहुत कम सीमित साधन होने के बावजूद भी हमारी सरकार ने हरियाणा में किसी भी पशु को चारै के अभाव में नहीं मरने दिया, आदमियों की तो बात छोड़िये। यह काम हमने लोगों के' लिए उस सूरत में किया है जब हमारे पास पैसे के पूरे साधन नही थे और केन्द्र सरकार ने इस मामले में हमारे साथ थोड़ा नहीं बहुत अधिक भेद भाव किया था। उपाध्यक्ष महोदय, अपने सीमित साधनों के बावजूद भी हमने लोगों की इननी अधिक सहायता की है जिसका कोई हिसाब नही लगायीं जा सकता। यह सारी सहायता हमने केन्द्र की सहायता मिले बिना की है। उपाध्यक्ष महोदय, आज चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि चौधरी देवी

लान जी की इस लोकप्रिय सरकार के पास कौन सी ऐसी जादू की थैली है कि यह हाफने लोगों को बुढ़ापा पैन्शन भी दे रही दे और दूसरो ओर काफी सहायता भी किसी न किसी रूप मे दे रही हैं। केन्द्र सरकार अपने गुप्तचर हरियाणा के लोगों के पास कभी टेलीविजन वाले बना कर भेजती है तो कमी कुछ बना कर भेज रही है। व लोग हरियाणा में जा कर यहां के बूढ़े और अनपढ़ लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम्हैं सचमुच में ही बुढ़ापा पैन्शन मिन रही है या चौधरी देवी लाल की सरकार वैसे ही शोर मचा रही है? उनकी इस बात का जवाब यहां के बूढ़े अच्छी तरह देते हैं। जब केन्द्र के गुप्तचर इस बात को पूछते हैं तो उनमें से गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब में से पोथिया निकाल कर दिखाया कि ये मनीआर्डर के पैसे चौधरी देवी लाल जी ने बुढ़ापा पैन्शन के ही भिजवाये हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल कांग्रेस में नए नए युवा कांग्रेसी भर्ती हो रहैं हैं। वे अपने बूढ़े मां–बाप से और दूसरे लोगों से पूछते हैं कि तुम इस सरकार के इतने गुण क्यों गाते हो, यह सरकार तुम्हैं क्या दे रही है? इसी प्रकार से एक फौजी भी अपने बूढ़े बाप को और दूसरे लोगों को चिढ़ा रहा था कि यह सरकार तुम्हैं क्या देती है तो इस पर उसके बाप ने अपनी जेब में से जो 800 रुपये बुढ़ापा पैन्शन के मनीआर्डर के आए. हुए थे, निकाल कर दिखाये और कहने लगा कि तने नौकरी करते हुए 10 साल हो गए, मुझे आज तक 100 रुपये का एक नोट भी नहीं दिया है। यह सरकार ही हमें ये 100–100 के नोट दे रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने इतनी कल्याणकारी

योजनाएं इस हरियाणा के लोगों के लिए शुरु की हैं जो अब सारे देश में फैलेंगी और जिसका अनुसरण बाकी सरकारें भी करेंगी। अब जो नीतियां हरियाणा सरकार ने लागू कीं, उन पर हिन्दुस्तान के लोग सोच–विचार कर रहैं हैं। ऐसी सरकार को भी यदि आर्थिक साधनों के लिए तडपाया जाए तो यह बहुत भारी अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि केन्द्र सरकार हमारे साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी जैसा व्यवहार कर रही है। ये लोग कहते हैं कि अब लोगों का अपना राज है लेकिन हम लोग कैसे महसूस करें? हरियाणा के लोगों को पता है कि हमारे साथ पक्षपात होता है, आर्थिक साधनों के मामले में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। इस पक्षपात के कारण हरियाणा के लोगों में बड़ा गुस्सा है। उपाध्यक्ष जी, मुझें दुःख उस समय होता है जब हमारे कुछ लोग जो केन्द्र में वजीर बने बैठे हैं, गाहैं–बगाहैं व्यान दे देते हैं। पहले श्रीमान् जी कहने लगे कि चौधरी देवी लाल मुख्य मन्त्री नहीं बन सकते, वे मुख्य मन्त्री बने तो फांसी खा लूंगा, फिर कहने लगे सरकार एक महीने में गिर जाएगी, फिर कहने लगे सरकार तीन महीने में गिर जाएगी, लेकिन चौधरी देवी लाल की सरकार अभी तक दनदनाती चल रही है। आजकल वे श्रीमान् सम्मेलन कर रहैं हैं। कन्साइनमैंट टैक्स के बारे में प्रोविजन 1982 में हिन्दुस्तान के संविधान में संशोधन के माध्यम से जुड़ गया था। उपाध्यक्ष जी, उसको लागू करने में उनको क्या गुरेज हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है? फिर वे हरियाणा के हितों पर ध्यान देते हैं कि मैंने तो मुख्य मन्त्री का पद छोड़ दिया। हरियाणा

के हितों से वे कितना जुड़े हुए हैं, इस का अनुमान सहज ही हो जाता है। उनकी पत्नी इस गरिमामय महान् सदन की माननीय सदस्या हैं। लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हैं चुन कर भेजा है। वे अपने लोगों के हितों का कितना ध्यान रख रही हैं इसका सभी को पता है। वे जो बात कहते हैं उसका कोई और ही मतलब होता है। वे कहते हैं कि मैंने मुख्य मन्त्री के पद से त्याग–पत्र दे दिया क्योंकि हरियाणा के हितों की हानि हो रही थी। वे इस प्रकार की कलाकारी दिखा रहैं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि इन्हैं हरियाणा के हितों से कुछ भी लेना–देना नहीं बै। जब रंज बुतों ने दिया तो खुदा याद आया। जब कोई दूसरी बात उनको पूरी तरह से फिट न आई तो झट पैतरा बदल लिया और व्यान दाग दिया। इस आदमी ने हरियाणा के हितों के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। हरियाणा के लोग उनसे कुर्बानी की उम्मीद भी नही करते। जब आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश में आन्दोलन चल रहा था, उस समय हमारे महापुरुष लोकमान्य तिलक ने पश्चिमी बंगाल से और पंजाब से लाला लाजपतराय ने बढ़–चढ़ कर कुर्बानी दी। बाल–पाल–लाल का नाम आज भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उस समय जाति–पाति रंग–भेद और वेशभूषा की कोई बात नहीं थी। उस समय सिर्फ एक ही जज्बा था कि कौन माई का लाल सबसे–ज्यादा कुर्बानी दे सकता है। कहां पंजाब और कहा पश्चिमी बंगाल? आपस में कुछ भी नही मिलता था, न वेश–भूषा, न खान–पान और न रहन–सहन। उनका उद्देश्य एक था, एक ही

संकल्प था कि फिरंगी को इस देश से भगाने में कौन कितनी कुर्बानी करता है। आजादी के बाद हक्मत कांग्रेस के हाथ मे आई। उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस का नेतृत्व. किन लोगों के हाथ में है? कांग्रेस महात्मा गांधी से शुरू हो कर आज वैजयन्ती माला और अभिताभ बच्चन के हाथ में पहुंच गई है और कमलापति त्रिपाठी जैसे नेता एक कोने में बैठे हैं। आज कांग्रेस के पास जनसभाओं में भीड इकट्ठा करने के लिए कोई भी नेता नहीं धै और यह बात उनको मालूम है। आज जनसभाओं में भीड़ इकट्ठी करने के लिए सिनेमा के कलाकारों के अलावा इनके पास और कोई नही है। उपाध्यक्ष महोदय, जनता दल के अध्यक्ष श्री वी० पी० सिंह इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहैं थे। क्योंकि कांग्रेस को पता था कि उनके पास भीड इकट्ठी करने वाला कोई नेता नहीं है इसलिए उन्होंने एक नय तरीका अपनाया। उन दिनों दूरदर्शन पर ''रामायण'' सीरियल दिखाया जा रहा था। यह सीरियल उन दिनों लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय था। जो व्यक्ति इस सीरियल में हनुमान का तेल कर रहा था यानी दारा सिंह, उसको व हां पर भीड़ इकट्ठी करने के लिए ले जाया गया। इसी तरह सीरियल में श्री राम का रोल करने वाले गोविल को वहां ले जाया गया। सीता का रोल करने वाली दीपिका के पास जब ये गये तो वे बेचारी कहने लगी कि काग्रेस के लिए काम करने के बाद वह सीता जैसी सतवंती का रोल मन से नहीं कर सकती। आज कांग्रेस इस तरह की राजनीति पर ठहर गई है। यह ठीक है कि ये लोग हरियाणा में चुनाव हार गये। लेकिन चुनाव में हारने के बाद इन्होंने किस तरह की

राजनीति करनी शुरू इनर दी? कभी राजेश पायलट को ला कर सम्भालखा में गुजर सम्मेलन करते हैं, कभी हांसी मे बेचारे गरीब ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब रोहतक और करना न में पंजाबियों को इकट्ठा कर लिया, उनका वावेला खड़ा कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हैं लानत है कि ये इस प्रकार की बातें कर रहैं हैं जो नही होनी चाहिए। कांग्रेस वालों ने राजनीति में बावेला खडा कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप पेशे से वकील हैं, आप पाक आदमी हैं लेकिन आपको मालूम होगा कि सरदार भिंडराबाला जब अमृतसर से चला था तो उस समय वहां के लोगों ने कहा था कि जो पंजाब के सन्त सिपाहियों की परम्परा है, पंजाब की नानक की परम्पर। है, भोले–भाले किसान की परम्परा है, सूफी लोगों की जो परम्परा है, यह उसके विरुद्ध है। उन्होंने कहा था कि इन्दिरा जी, सरदार भिंडरावाले जैसे आदमियों के लिए स्वर्ण मन्दिर में जगह नहीं है, यह पवित्र स्थान ऐसे लोगों के लिए नहीं है लेकिन उनकी एक भी बात नही मानी गई। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कभी वे राष्ट्रपति के यहां जा रहैं होते और कभी कोई उनके सम्मुख झुक रहा होता। उस समय पंजाब के भोलेभाले लोगों ने सोचा कि चूंकि यह कोई अवतारी पुरुष है इसलिए कांग्रेस पार्टी इसे गिरफ्तार नही करना चाहती। आप जानते हैं कि जब लाला जगतनारायण की हत्या के सिलसिले में उनके वारन्ट कटे और उन्हैं गिरफतार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया तो लोगों ने उस समय कहा था कि इसे क्यों छोड़ा गया है ? आज यह कांग्रेस के भाई इस बात का जवाब दें कि

उसे उस समय क्यों छोड़ा गया था? हमारे यहां हरियाणा में चन्दोकला हिसार जिले में एक जगह है जहा से उन्हैं गिरफतार किया गया था। हमारे डी० आई० जी० खान साहब, जो आजकल हिसार रेंज के डी० आई० जी० हैं, ने उसे गिरफ्तार किया था लेकिन दिल्ली से बड़े आदमियों को भेजा गया कि उन्हैं गिरफतार मत करो। उन्हैं कहा गया कि इनको पुलिस की ऐस्कोर्ट में बाइज्जत मेहता चौक छोड़ कर आओ। उपाध्यक्ष महोदय, देश में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं लेकिन सारे देश में एक कानून होता है, देश में कुछ रिवायात होती हैं लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जिस आदमी पर 302 का केस हो और बहादुर अफसरों ने गिरफ्तार कर लिया हो, उसके बारे में केन्द्र कहता है कि इसे छोड़ दो। उन लोगों ने सारी परम्परा, सारी व्यवस्था, सारे कानून को चरमरा दिया। केवल राजनैतिक सत्तो की भूख के कारण मेरे मित्रों ने ऐसा किया। राजनैतिक सत्ता की एक चाह होती है, यह कोई बुरी बात नही है। महात्मा गान्धी ने एक बार कहा था कि जो रास्ता नैतिक तौर पर गलत है वह मनुष्य को कभी अच्छी मंजिल पर नहीं ले जाता लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब डन्को यही नही पता कि गणतंत्र और स्वतंत्रता का क्या रास्ता होता है तो वे सही रास्ते पर कैसे चलेगे? उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के माध्यम से यानी जिस पर पिछले सत से बहस हो रही है, सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने लहजे और अपनी अपनी जानकारी के हिसाव से विस्तृत चर्चा की है। यह सही बात है कि यह कन्साइनमैंट का प्रस्ताव है और इस से हरियाणा

प्रदेश को काफी फायदा है परन्तु इससे तो अन्य सभी प्रान्तों को भी फायदा होगा। केन्द्र की सरकार सभी साधनों को अपने पास रखना चाहती है। आखिर दिल्ली केन्द्र की ही नही है वह तो सारे भारत की है। हमने संघीय ढांचे को संविधान में स्वीकार किया है। हमारी मान्यता है कि केन्द्र की सरकार मजबूत होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, उसके पास विकास के कामों के लिए साधन होने चाहिए। केन्द्र मजबूत कब होगा, जब स्टेट्स के साधन ठीक होंगे। जब उसके हाथ मजबूत होंगे, उसके पैसा इकट्ठा करने वाले मजबूत होंगे, रिक्वरी हैन्डज मजबूत होंगे तभी सैन्टर मजबूत हो सकता है। यह दिल तभी मजबूत हो सकता है जब उसके हाथ और पैर मजबूत होंगे। यह एक प्रक्रिया है, बायोलोजिकल प्रोसैस है। उपाध्यक्ष महोदय, बिना प्रदेशों के सहयोग के केन्द्र कभी मजबूत नहीं होता। केन्द्र में बैठे हुए लोगों को पांच साल की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उनको तो काफी बड़ा बहुमत मिला है। केन्द्र में बैठे हुए कुछ लोग यह समझते हैं कि जनता भोली–माली है, इस देश की जनता को नारों में बहका देंगे, कभी मां की लाश दिखा कर बहका लेंगे और कभी जवाहर लाल के नाम से बेरोजगारी की संस्था बना कर बहका लेंगे, यह बहुत दिनों तक चलने वाली बात नही है। अब केन्द्र ने एक नया शीशा छोड़ा है कि गरीब औरतों को साड़ियां देंगे। दैनिक ट्रिब्यून में ''ताउ बोला'' में यह निकला है। उस कालम में बड़ा अच्छा लिखा है कि वह साड़ी वोट देने से पहले मिलेगी या पीछे मिलेगी। उपाध्यक्ष

जी, साडी चाहैं पहले दो चाहैं बाद में दो। इनके बहकावे में अब लोग नहीं आयेगे। (हंसी)

12.00 बजे।

श्री उपाध्यक्षः आप तो बीसवीं सदी की बात कर रहैं हो। (हंसी)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष जी, जिस सदी में हम हैं उसी की बात कर सकते है न पीछे की बात कर सकते है और न आगे की, क्योंकि हम योगी नहीं हैं। हम तो बीसवी सदी की ही बात करेंगे। (विघ्न)

उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समापन की ओर ले जाते हुए इस सदन के माध्यम से यह गुजारिश करूंगा कि कई बार ऐसा लगता है कि प्रस्ताव पास करने से केन्द्र की सरकार के०पर क्या फर्क पड़ेगा परन्तु फिर विचार आता है कि कम से कम हम अपनी जिम्मेवारी का वहन कर रहैं हैं, यह तो संतोष हमें रहैंगा। हम जानते हैं कि केन्द्र में जो लोग बैठे है, उनको न तो राजनीतिक तजुर्बा है न ही राजनीतिक संकल्प है, न ही कोई राजनीतिक विल्ल है और न ही वह इस देश की समस्याओं को जानते है। एक बार प्रधान मन्त्री उड़ीसा के कालाहांडी नाम के एक गांव में गये ' आपको पता ही है कि टेलिविजन वालों को कुछ न कुछ दिखाना होता है। टेलिविजन के डायरैक्टर ने कहा कि आप किसी गरीब के घर में जाना, फिर हम आपका ऐसा प्रस्तुतिकरण

करेंगे कि आपको गरीबों का मसीहा दिखायेंगे। उनके कहने से वे चले तो गये परन्तु इनको पता तो है नहीं कि भारत कहां बसता हैं, झोपड़ी क्या होती है, झोपड़ी में कौन रहते हैं, उनकी दुःख तकलीफ क्या होती है ? एक बूढ़ी बेचारी एक फटी पुरानी साडी लपेटे बैठी थी जिसमें भारत का नक्शा बना हुआ था। उसका न तो ब्लाऊज था और न ही पेटीकोट था। एक माल तीन गज का जीर्ण–शीर्ण कपड़ा लपेटे हुए थी। एक कोने में वह दुबकी हुई बैठी थी। एक तरफ चूल्हा, उसके०पर ठीकरे का बर्तन रखा हुआ था और एक तरफ घास लगी थी। राजीव गांधी ने पूछा मां, यह क्या है?

श्री उपाध्यक्षः शर्मा जी, आप नाम न ले, केवल प्राईम मिनिस्टर कहैं।

श्री राम बिलास शर्माः आपकी बात ठीक है। गलती. हो जाती है क्योंकि उनको राजीव गांधी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। Since he is not acting like a Prime Minister, therefore, his recognition has become so. उन्होंने जो पहचान बनायी है, वह राजीव गांधी के नाम से ज्यादा बनायी हैं, प्रधान मन्त्री के नाम से कम बनायी है। उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाह रहा था कि उस बूढ़ी मां से प्रधान मंत्री जी पूछने लगे कि तुम्हारें घर में पशु तो कोई नही है, यह घास किसलिये लगा रखी है? उस बेचारी बूढ़ी ने अपनी जबान में यह बताया कि ललवा, यह घास पशु के लिये नही है। जब यह सुहांजना और इमली के दरख्तों के

पत्ते खत्म हो जाते हैं तब मैं इस घास को पानी में डाल तया उबालकर इसका पानी पीकर अपने पेट की आग बुझाती हूं। इसके बावजूद भी ये वात इक्कीसवीं सदी की कर रहैं हैं। एक बार इनसे किसी विद्वान पत्रकार ने पूछा कि गरीब की बात आप करते हो, गरीब के लिये योजना की बात भी आप करते हो लेकिन गरीब आप किसको समझते हो? वह कहने लगे कि गरीब वह है, जिसके पास कलर टैलीविजन न हो और पूरानी कार हो। इस हिसाब से तो इनको भारत में कोई गरीब नही मिलेगा। उपाध्यक्ष जी, जिन लोगों के हाथ में योजनाएं बनाना है, वह दर्द को महसूस नही करते। यह तो अनूभव से आता है। आपकी सरकार ने बूढ़ों को पैंशन क्यों दी? क्योंकि आप सब लोग ऐसे घरों से आये थे। चौधरी देवी लाल को अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से यह मालूम है कि जब आदमी इस उम्र में जाता है तो बच्चों का क्या रवैया हो जाता है। हमने 24 घंटे बिजली का प्रोवीजन भी इसलिये किया कि भारत की रीढ़ की हड्डी किसान है। खेती जब लहलहायेगी नही, जब खेतों में हरियाली नही होगी तो बाजारों मे रौनक खत्म हो जायेगी। यह हम अपने अनुभव से जानते है। हम झोपड़ों से, किसानों के खेतों से और खलिहानों से आये हुए हैं। इसलिये हम जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। यह भाई जानते नही है कि कन्साइनमैंट टैक्स को लगाने से प्रान्तों की सरकारों को अधिक साधन देने से क्या फायदे है। इनको मालूम नही हैं। यह तो ड्रामे में और नाटकबाजी में विश्वास रखते हैं। भारत नाटक को बर्दाश्त नही कर सकता। भारत की जनता गरीब हो सकता है भारत की

जनता कम पढ़ी–लिखी हो सकती है परन्तु इसमें डैमोक्रैटिक सैसं पूरी है। भारत की सैस को दुनिया ने 1975 और 1977 में माना है। 1977 के चुनाव परिणाम इस बात की गवाही हैं कि चाहैं राजीव गांधी साड़ी बांटने का प्रोंवीजन करें या चाहैं बेरोजगारों को डराने या लालच देने की बात करें परन्तु हिन्दुस्तान की जनता ऐसी बातों को समझती है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से राजीव गांधी को इस महान सदन के माध्यम से कहना चाहता हू कि आज तक हिन्दुस्तान मै जो राजनीतिक प्रोसैस हरियाणा के लोगो ने शुरू कर दिया है, वैह राजनीति पूरे देश के अन्दर शुरू होने वाली है। कांग्रेस का सफाया राजनीति में से हरियाणा में लोग शुरू कर चुके है। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी 1982 से यह संविधान संशोधन लटकाये हुए हैं, कन्साइनमैंट टैक्स का प्रोवीजन करने के लिए ऐक्ट मैं अमैंडमैंट नहीं कर रहैं हैं। बेशक न करें हम भीख नहीं मगेंगे। मेरी अपनी सरकार के प्रतिनिधियों ने 1984 मे भी और अभी एक मुख्य मत्रिंयों की कान्फ्रैस हुई थी उसमें हमारे मुख्य मन्त्री, माननीय उप–मुख्य मन्त्री और हमारे योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जी गये. थे। हम इस बात को जानते है कि इन्हैंने बड़ी हिम्मत से बात कही थी कि आप लोग चाहैं तो गिडगिड़ाए लेकिन हम कभी गिड– गिड़ायेंगे नही। आप लोग यदि चाहैं कि हम राजीव गांधी के खिलाफ बोलना छोड़ दें, अन्याय के खिलाफ हम आवाज न उठाए तो यह नही हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय हम अपने लोगों को थोड़ी सी तकलीफ भूगतने देंगे लेकिन आने वाले

समय में ऐसा लगता है कि हमारे हाथों से ही यह संविधान संशोधन होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यही समाप्त करके अपना स्थान नेता है।

श्री उदय भान (हसनपुर–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 'साल सैशन में भाई रणजीत सिंह जी का कंसाइनमैंट टैक्स के०पर जो प्रस्ताव आया था उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 1982 में केन्द्रीय सरकार ने 46 वां संशोधन करके अपने अन्दर यह शक्ति अर्जित की कि वह कंसाइनमैट टैक्स लगाए लेकिन यह बड़े खेद की और अफसोस की बात है कि सात वर्ष होने के बाद भी केन्द्रीय सरकार ने राजीव गांधी की सरकार ने इस ओर बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मई, 1984 में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था और उसमें कांग्रेस के और विपक्ष के सब मुख्य मन्त्री गए थे। उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि कंसाइनमैट टैक्स शीघ्रातिशीघ्र लगाया जाए। लेकिन बड़े खेद की बात है कि इतना होने के बावजूद इस ओर केन्द्रीय सरकार न बिल्कुल भी ध्यान नही दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इस प्रसताव का समर्थन किया था लेकिन उसको भी बिल्कुल नजर अन्दाज किया गया। इससे' पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार संघीय ढांचे को विल्कुल बरबाद करना चाहती है और राज्य सरकार के अधिकारी को सीमित करना चाहती है। यह बड़ी खेदजनक बात है। फरवरी, 1989 में भी इस

बात पर जि शेष चर्चा हुई थी लेकिन बड़े खेद की बात है कि इस देश के प्रधान मन्त्री इतना भी नही जानते, उनको इतना भी नहीं मालूम कि इस बारे में सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है। प्रधान मन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन मै यह कहा कि सर्वसम्मति से इस बारे में फैसला नहीं हुआ है। यह बड़े अफसोस की बात है कि जिस देश के प्रधान मन्त्री को किसी फैसले के बारे में पता ही न हो, वह क्या प्रधान मन्त्री बनने के लायक है? मैं बड़े फख से कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल ने ललकारा और कहा कि हम कठपुतली नहीं हैं और हम आपसे भीख नही मांगते। कसाइनमैंट टैक्स के बारे में सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है। वहीं पर कर्नाटक के मुख्य मन्डी ने 1984 का फैसला दिखा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिसको हिन्दुस्तान का मानचौस्टर कहा जाता है वहां पर बहुत बड़े–बड़े उद्योग लगे हुए हैं। गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद और धारूहैंड़ा आदि में बहुत बडे–बड़े उद्योग लगे हुए हैं। मेरा जहां तक अन्दाजा है इन जगहों से हरियाणा प्रदेश को कम से कम सौ करोड रुपये का टैक्स मिल सकता है लेकिन इसके न मिलने से प्रदेश को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए किसानों 'से जमीन लेकर सस्ती कीमत पर उद्योगपतियों को देती है। बिजली मुहैया करती है, पानी मुहैया करती है और प्रदेश के पैसे की मदद से वे उद्योग स्थागित होते हैं लेकिन जव टैक्स की बात आती है तो केन्द्रीय सरकार सारे पैसे को अपने पास ले लेती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह नुक्सान केवल हरियाणा

की सरकार को नहीं हो रहा है बल्कि सारे प्रदेशों की सरकारों को हो रहा है। अगर यह टैक्स हमारी सरकार को मिल जहर तो न हमें पानी की कमी महसूस होगी, न हमें बिजली की कमी महसूस होगी। हमारे यहां स्कूल और कालेजिज ज्यादा खुल सकेंगे और हम गरीब लोगों के विकास के लि।! और कल्याण के लिए काम कर सकेंगे लेकिन केन्द्रीय सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहती। केन्द्र सरकार ने हरियाणा के साथ जिस तरह से भेदभाव बरता हुआ है, उसको देखकर बड़ा अफसोस होता है। वह हर सरकार पर अपना अंकुश रखना चाहती है जिससे कि हर सरकार उसकी कठपुतली बन जाए। हर मामले मे हरियाणा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोच फैक्टरी जो हरियाणा में लगनी थी और जिससे हजारों आदमियों को रोजगार मिलना था उसको पंजाब में स्थानान्तरित कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० के मामले में केन्द्र सरकार ने पूरी तरह से उदासीनता दिखायी है। इसी तरह से करनाल तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन भी श्री राजीव गाधी जी ने किया था जोकि लगभग 1500 करोड़ रुपये की लागत से लगाया जाना था और वह कारखाना 1999 में तनकर तैयार हो जाना था परन्तु बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उस कारखाने का अभी तक कोई भी कार्य आरम्भ नही किया गया है। यह सुना गया है कि शायद अब वे कारखाने को यहां से शिफ्ट करने का सोच रहैं हैं। इस तरह का भेदभाव केन्द्र सरकार हमारे हरियाणा के साथ कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों को भी मुख्य धारा में लाने के लिये सरकार योजना बना रही है लेकिन कटारिया साहब ने शायद ठीक ही कहा है कि सरकार इन्दिरा विकास योजना नही बल्कि हरिजन वनवास योजना बना रही है। मैं उन से सहमत हू। हरिजनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से मनुस्मृति काल मैं अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्य धारा से अलग करने के लिये गांव से बाहर बसा दिया गया था, उसी तरह से आज केन्द्र सरकार भी हरिजनों के लिये जो विकास योजना बना रही है, वह एक प्रकार का हरिजनों के साथ षड्यन्त्र रचा जा रहा है। भेदभाव की नीति हरिजनों के साथ बरत रही है। लेकिन हमारी चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने हरिजनों को प्रोत्साहन देने के लिये उनके वजीफे भी दुगुने कर दिये। मकान बनाने के लिये जो कर्जे की राशि 2 हजार रुपये थी, उसको बढ़ाकर अब पांच हजार कर दिया गया है। हरिजनों के जो कर्जे थे, उनको माफ किया गया है। इसी तरह से हरिजन चौपालों के लिये काफी सहायता सरकार की ओर से दी जा रही हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हम केन्द्र सरकार से भीख नहीं मांगेंगे और न ही हमें मांगनी चाहिये। मैं इस कसाइनमैंट टैक्स के लिये हाउस के सभी आदरणीय मैम्बरान व सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये केन्द्र सरकार के०पर पूरा दबाव डाला जाए कि 1982 में कंसाइनमैंट टैक्स के बारे में जो अमैंडमैंट की गयी थी, उसको लागू किया जाए ताकि हरियाणा सरकार को उसका फायदा हो

सके। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा (नारनौल): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल सैशन के दौरान चौधरी रणजीत सिंह जी ने जो संकल्प रखा था, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में तीन चार मुद्दे ऐसे हैं जिनके आधार पर मेरे से पहले भाई सम्पत सिंह व श्री रामविलास शर्मा जी ने विस्तार से सिद्ध किया है कि केन्द्र सरकार का रवैया हरियाणा के प्रति कैसा है? एस० वाई० एल० जिसे हम हरियाणा की जीवनधारा कहते हैं, उसी तरह से यह कनसाइनमैंट टैक्स विशेष रूप से सारे देश के लिये लाभदायक है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लिये तो यह जीवनधारा है क्योंकि हरियाणा की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि इसने राजधानी दिल्ली को चारों, ओर से घेरा हुआ है दिल्ली के आस पास बड़ी–बड़ी फैक्टरियां हैं। केन्द्र सरकार भी विशेष रूप से इस कोशिश में रही है कि वहां पर और बडी–बड़ी फैक्टरियां लगाई जाएं ताकि इन फैक्टरियों से केन्द्र सरकार को अधिक मात्रा में टैक्स मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ा उद्योग मारुति उद्योग है जोकि हरियाणा में गुड़गांव के अन्दर लगाया गया है और वह दिल्ली के नजदीक पड़ता है लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े उद्योग का लाभ, जहां हरियाणा की जनता को मिलना चाहिये था, वह आज हरियाणा की जनता को न मिल करके केन्द्र सरकार

के पास जा रहा है। आपको याद होगा कि जब यह मारुति उद्योग हरियाणा में लगना था उस वक्त उस जमीन की कीमतों का विवाद उठ खड़ा हुआ था। उस वक्त जब इस उद्योग के लिये भूमि अधिग्रहण की गयी थी, तब इस हरियाणा की भूमि की बड़ी कीमत थी। भूमि अधिग्रहण के समय विरोधी पक्ष के भाइयों ने आवाज भी उठाई थी कि जो यह सोना उगलने वाली जमीन है, इसको कौड़ियों के भाव क्यों बेचा जा रहा है? उस वक्त बड़े पैमाने पर आन्दोलन भी चला था। अगर इस जमीन की सही कीमत दी जाती तो लोगों को बहुत ज्यादा लाश होता लेकिन उस समय कौड़ियों के भाव वह ली गयी यह कहकर कि उद्योगों का विकास करना है। उस मारुति उद्योग को बिल्कुल दिल्ली–हरियाणा बौर्डर पर, दिल्ली के समीप गुड़गांव जिले में लगा दिया गया। परन्तु आज वह जमीन सचमुच में सोना उगलने लगी है। जब उस' फैक्टरी में उत्पादन होने लगा तो उसका सारा पैसा, सारा धन टैक्स के रूप में केन्द्र सरकार के पास जा रहा है और प्रदेश सरकार इससे वंचित रह रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में बैठे हुए अगर कुछ कांग्रेसी मित्रों का यह विचार है कि केन्द्र को मजबूत करने के लिए स्टेट को कमजोर कर दिया जाए तो यह उनकी बात गल्त है। जैसा कि भगई राम बिलास जी कह रहैं थे कि यह जो देश व राष्ट्र है, यह शरीर के समान है और यह जो प्रदेश हैं, ये उसके अंग हैं। अगर कोई किसी अंग को कमजोर करके शरीर को मजबूत करने की

बात करता है यानी किसी राज्य को कमजोर करके केन्द्र को मजबूत करने की बात करता है तो इससे भयंकर कोई और गल्ती हो नही सकती। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रैस ने स्वयं ऐक्सपैरिमैंट करके देख लिया है लेकिन पता नहीं उनको क्यों समझ नहीं आता। उन्होंने सारी शक्ति का केन्द्रीयकरण कर दिया। उन्होंने अपने मुख्यमत्रिंयों को कठपुतलियां बना कर रखा हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने और केन्द्र की पार्टी ने भी प्रदेशों की पार्टियों के नेताओं को एक ऐसा बल्ब बना कर रख दिया कि अगर उसका फ्यूज केन्द्र से जोड़ देते हैं तो वह जत जाता है और अगर केन्द्र से औफ कर देते हैं तो वह बुझ जाता है। परिणामस्वरूप आज 8–9 स्टेट्स में इनका सफाया हो चुका है। वास्तव में इस बात को लेकर हरियाणा के उप मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास गुप्ता तथा अधिकारी भी अनेक बार उनसे मिले हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि सैन्टर स्टेट्स रिलेंशज में सुधार के लिए सरकारिया कमीशन खुद सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने नियुक्त किया था। सरकारिया कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रदेशों को शक्ति देने के लिये आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण किया जाए और कन्साइनमैंट टैक्स लगाने की पावर प्रदेशों को दी जानी चाहिए। आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते है कि जब 1982 के अन्दर संसद ने महसूस किया संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की तो सरकार को 46वां संशोधन संविधान में करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आज सात साल 'तक उस पर विचार नहीं किया गया। इसका क्या कारण है। इसका एकमात्र कारण यही

है कि कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार राजनैतिक रूप से कमजोर हो गई है। जव उसने महसूस किया कि हम विरोधी दल के मुकाबले में राजनैतिक मंच अरेंज नही कर सकते हैं, हम जनता के बीच मे जाकर विरोधी दलों के सामने टिक नही सकते तो उन्होंने यह रास्ता निकाला। उन्होंने विरोधी दल की सरकारों को आर्थिक चे पहुंचाने की कोशिश की। विरोधी दल के मुख्य मन्त्रियों की बैठक कलकत्ता में हुई। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री एन० टी० रामा राव ने इस विषय को जोर से उठाया। सभी मुख्य मन्त्रियों की मांग थी कि कन्साइनमैंट टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को दिया जाए परन्तु उसके बाद भी केन्द्रीय सरकार के कानों पर जूं नही रेंगी। मेरी जानकारी है किं जब 1979 मे बाबू मूल चन्द जैन, चौधरी देवी लात के मन्त्रिमण्डल में वित्त मन्की थे तो उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया था और हरियाणा में इस बात की लागू करने का विचार बनाया था लेकिन उसके बाद जत भजन लाल जी मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने इसको कानूनी रूप नही लेने दिया। हरियाणा के साथ काफी समय से इस मामले में ज्यादती हो रही है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने भी केन्द्रीय सरकार के सामने यह बात रखी कि हरियाणा को इस वजह से सौ करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा बै। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार वास्तव में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहती है, उसने सारे देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कल्याणकारी सरकार कैसी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि सारे देश में यही ऐसी सरकार है जो समस्याओं को ढूढती है, जो स्वयं जाकर

पता करती है कि लोगों क्रो कोई तकलीफ तो नहीं है। यहां पर लोगों को अपनी तकलीफ दूर कराने के लिये प्रार्थना पल नही देने पडते। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह चौधरी देवी लाल को और अधिकार दे नशा और पैसा दे ताकि वै प्रान्त में अच्छे काम कर सकें लेकिन केन्द्रीय सरकार उसमें रोडा अटकाने की बात करती है। बेरोजगारी भले को मामले में भी मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने सारे देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। छोटे से राज्य ने हरियाणा के बेरोजगारी की समस्या को हल किया है। भले ही उनकी पूरी आवश्यकता पूर्ण नही हुई परन्तु हमने एक रास्ता पकड़ा है कि हम उनको बेरोजगारी भल्का देना चाहते हैं। जब सरकार कल्याणकारी योजनाए चलाती है तो आर्थिक साधनों की भी आवश्यकता होती है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उनको जो कट करने की कोशिश त्ही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय रणजीत सिह जी ने खेप कर के विषय में जो प्रस्ताव पेश किया है, उस पर चर्चा कर रही है। वास्तव में यह प्रस्ताव प्रदेश की सरकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहरने सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स के सिलसिले मे सविधान मे यह प्रावधान था कि कानून बनाने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को होगा। लेकिन जब प्रान्तीय सरकारों और विरोधी पक्ष के नेताओं ने

केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया कि अगर प्रान्तीय सरकारों को ठीक ढंग से चलाना है तो कन्साइनमैंट टैक्स ऐक्ट अनैक्ट किया जाये। प्रान्त की सरकारों को ठीक ढंग से चलाने के लिए बैलैस्ड टैक्स के सिलसिले में उनको धन उपलब्ध कराया जाये ताकि उनके टैक्स के रिसोर्सिज का बैलैसं बना रहैं तब 1982 में संविधान मे 46वां संशोधन दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करना बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे देश का संविधान संघीय है, जिसमें कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों के हैं और कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार को है और कुछ अधिकार, कंकरैंट लिस्ट में हैं। इस विषय में केन्द्रीय सरकार के साथ काफी जदोजहद हुई और उसको यह स्वीकार करना पड़ा। 1982 में संविधान में संशोधन करना पडा जिसके अनुसार सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स के विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाया गया जिसके तक कारखानों के उत्पादन पर जो टैक्स लगता है वह संबंधित सरकारों को मिले। पहले कानून में यह प्रावधान था कि कोई भी उद्योगपति अपना कार्यालय कहीं पर भी खोल सकता है। उसके अनुसार जिस प्रदेश में जो उत्पादन होता था और उस पर जो टैक्स लिया जाना था वह उस प्रदेश को नहीं मिलता था। केवल केन्द्रीय सरकार को ही मिल पाता था। इसके' कारण प्रान्तीय सरकारों को धन का अभाव रहता था। इसलिए केन्द्रीय सरकार को चारों तरफ से दवाव के कारण मजबूर हो कर संविधान में यह संशोधन करना पड़ा। केन्द्रीय सरकार ने 1982 में संविधान में संशोधन तो कर दिया लेकिन पता नहीं उनकी समन में नही आता

या किन्हीं और कारणों की वजह से उन्होंने अभी तक सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स ऐक्ट में जो अमैंडमैंट करनी थी, जिसके तहत प्रदेश की सरकारों को जो अधिकार देना था, वह अधिकार अभी नही दिया गया। उसमें डिले की जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब स्वाभाविक तौर पर जब किसी काम में डिले होती एं तो –वही बात होती है जैसे इंगलिश में कहते हैं justice delayed is justice denied जब ज्यादा डिले हो जाती है तो आपस में शंकाएं पैदा होना स्वाभाविक है। जब एक पार्टी की सरकार केन्द्र में राज्य करती हो और प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार हो तो इस प्रकार की बात होती है और आपस में शंकाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। देश की अखण्डता और एकता के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी परम्परा नही है। केन्द्रीय सरकार ने जब एक अच्छी बात को मान लिया है तो उसको लटकाने से क्या लाभ है? आज सारे देश में दुर्भाग्य से इस प्रकार की बात चल पड़ी है कि अगर किसी प्रकार की बात प्रान्तीय सरकार के बस की न हो तो वह उस बात को केन्द्रीय सरकार पर डालने की कोशिश करती है और जो बात केन्द्रीय सरकार के बस की न हो वह प्रदेश की सरकारों पर डालने की कोशिश करती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि देश के प्रधान मन्त्री सारे विपक्ष को उग्रवाद के लिए दोषी बता रहैं हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात आजाद देश के लिए और दूसरी नही हो सकती। अफसोस है कि जो कुछ उन्होंने कहा वह अपनी समझ के अनुसार कहा लेकिन यह देश के हित' में नहीं है। यह बड़ी खेदजनक बात है। उपाध्यक्ष महोदय,

प्रधान मन्त्री चाहैं कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन वह सारे देश का प्रधान मन्त्री है। प्रधान मन्त्री हमारे देश का है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, यदि हम उनके खिलाफ कोई बात कहैंगे तो बड़ी सोच समझ कर कहैंगे। वह प्रधान मन्त्री केवल एक पार्टी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्रधान मन्त्री है लेकिन इस प्रकार की बाते कहना उनको शोभा नही देता। ऐसी बातें कहने का परिणाम आज हमारे सामने है। चाहैं आसाम हो, चाहैं आन्ध्र प्रदेश हो, चाहैं नागालैड हो और चाहैं पंजाब हो सभी में उग्रवाद और विघटन की बात चल रही है। यह उन्हीं की सोच का ह परिणाम है कि आज इस तरह के हालात हो रहैं हैं। केन्द्र सरकार को इस विषय में गम्भीरता से सोचना चाहिए और सोच समझ करके कोई इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए जिससे सभी की शंकाएं निर्मूल हो सकें। किसी हद तक इन शंकाओं को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने सरकारिया कमीशन बनाया भी था। उस सरकारिया कमीशन ने स्वाभाविक रूप से काफी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट राज्यों और केन्द्र के संबंधों के बारे में तैयार करके दी है। वह रिपोर्ट हमने देखी तो नही है लेकिन मालूम हुआ है कि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि केन्द्र और प्रान्त का आपस में क्या संबंध हो, क्या अधिकार राज्य सरकारों के पास हों और क्या अधिकार केन्द्र सरकार के पास हों। इसी प्रकार से उस रिपोर्ट में गवर्नर्ज के बारे में भी त्रिखा है कि गवर्नर किस प्रकार से काम करेंगे और किस प्रकार केन्द्र का रोल प्रांत की सरकारों के प्रति होगा। उस रिपोर्ट में इस प्रकार का सारा विवरण दिया हुआ है। हम भी चाहते हैं कि उस

रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी सव की सहमति हो, यानी इस रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार और प्रान्तीय सरकारों और विपक्षी पार्टियों को बैठ कर सोच–विचार करना चाहिए। इस समय केन्द्र में जो सरकार बैठी है वह अपनी मर्जी से सब कुछ उलट काम कर रही है। इस समय केन्द्र सरकार की मन्शा यह रहती है कि जिन प्रान्तों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें काम कर रही हैं, उनको तोड़ दिया जाये या उन पर किसी न किसी रूप मे अपना दबाव रखना चाहती है। मैं उनको यह बतला देना चाहता हूं कि यह कुर्सी किसी की जायदाद नही है। आज जो कुर्सियों पर बैठे है, चाहैं प्रधान मन्त्री या मुख्य मन्त्री ही क्यों न हो अगर गलत काम करेंगे तो उन्हैं बाद में भी दण्ड दिया जा सकता है। अगर आज कोई मुख्य मन्त्री या और कोई किसी पद पर बैठा है और वह गलत काम करेगा तो कल को वह जेल की सलाखों में भी बन्द किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुर्सी किसी की जायदाद नही है। यक्ष कुर्सी इस देश और प्रदेश के नागरिकों की है। जो आज के दिन विधान सभाओ में मैम्बर हैं या पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, वे एक पब्लिक सर्वेन्ट के तौर पर लोगों की नुमायन्दगी करने के लिए विधान सभाओं और पार्लियामेंट में जाते हैं इसलिये उनका यह फर्ज बनता है कि वे ऐसी कोई बात न कहैं जिससे देश का विघटन हो और देश कमजोर हो। सभी लोगों को इस देश को जोड़ने की हीँ बात कहनी चाहिए। यह अलग बात है कि जाने–अनजाने में कई बार गलती होती रहती है। अमी भी केन्द्र सरकार के पास समय है कि वह समय रहते हुए कुछ सोचे और

केन्द्र सरकार अपनी नीतियों के बारे में पुनः नही सोचेगा तो उसको केन्द्र की कुर्सी से जाना पड़ेगा। अब इस देश के नागरिक इतने अनजान नहीं हैं। वे भला बुरा सब जानते हैं। अब एक दुसरे पर आरोप डाल कर काम चलने वाला नहीं है। ओज के दिन लोगों की बहुत गम्भीर समस्याएं है। किसी की बेरोजगारी की समस्या है तो कहीं पर भ्रष्ट्राचार का बोलबाला है। इस भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जहां साधनों की आवश्यकता होती है वहां साधनों के साथ साथ नेक नीयती का होना भी बहुत जरूरी है। Where there is will, there is a way. अगर नीयत ठीक हो तो सारी समस्याओं का समाधान चाहैं न हो सके लेकिन फिर भी उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है यानी उस समस्या के प्रति कदम बढ़ाया जा सकता है, उसके निपटारे के लिए प्रयास किया जा सकता है। आज इस देश की गद्दी पर बाई चांस ऐसे लोग बैठे हैं, जिन्हैं ड्राईविंग करनी चाहिए थी। आज के दिन वे देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए है। वे जहाज चलाने में निपुण हो सकते हैं लेकिन इस देश को चलाने में निपुण नहीं हो सकते। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश की पार्लियामेंट में और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में भी काफी ऐसे लोग मैम्बर बने बैठे है जिनकी जगह विधान सभाओं में या पार्लियामेंट में होने की बजाये जेल में होना चाहिए थी। ये ऐसे लोग है जो इस देश के लोगों का शोषण करने में जुटे हुए है। जब तक ऐसे लोगों को दूर करने के लिये दूसरे लोग आगे नही आयेगे वे शोषण करते रहैंगे। इस देश मै पहले अंग्रेज भी

फूट डालो और राज करो' की नीति पर राज करते रहैं हैं। अब दुर्भाग्य से इस देश की कांग्रेस पार्टी जो केन्द्र में बैठी है वह भी अंग्रेजों की भान्ति फूट डालो और राज करो' की नीति पर ही चल रही है। यह वह कांग्रेस नही रही जिसने पहले कभी इस देश की आजादी के लिए यानी इस देश को आजाद कराने के लिये मेहनत की थी और लड़ाई लड़ी थी। देश की आजादी के बाद धीरे धीरे काग्रेस की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में चली जा रही है जिनके कारण कही पर पंजाबी सम्मेलन हो रहा है, कहीं पर गूजर सम्मेलन हो रहा है और कहीं पर ब्राहमण सम्मेलन टो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश और प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति एक प्रदेश का मुख्य मन्त्री रह चुका हो और अब केन्द्र में कृषि मन्त्री बना बैठा हो और फिर वही कहीं पर पंजाबी सम्मेलन को सम्बोधित कर रहा हो और यह कह रहा हो, जिसके बारे में पता नही कितना सल्व है या झूठ है, हमने अखबारों में पढ़ा है कि मैंने मुख्य मन्त्री के पद से इस्तीफा इसलिये दिया क्योंकि केन्द्र ने, प्रधान मन्त्री ने मुझ पर दबाव डाला और यह कहा कि हिन्दी भाषी फाजिल्का और अबोहर तथा चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिये जाएं। मैं उस दबाव के आगे झुका नही और हरियाणा के हितों कैं खिलाफ हुए इस फैसले के परिणामस्वरूप मैंने मुख्य मन्त्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश का मुख्य मन्त्री और पार्टी के केन्द्रीय मन्त्री अगर ऐसा कहते हैं और अपने देश के प्रधान मन्त्री के खिलाफ होते हैं तो इससे साफ जाहिर हैं कि देश का प्रधान मन्त्री जिसके लिए सारे प्रान्त बराबर

होने चाहिए, देश के सारे प्रान्तों को बराबर नही समझता और इस प्रकार की भेदभाव की भावना रखता है। जिन प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं बल्कि दूसरी पार्टियों की सरकारें सत्ता में है उनके प्रति यदि ऐसा रवैया अपनाया जाता है तो इससे ज्यादा कोई और दुखदाई बात नही हो सकती और इस प्रकार की बातों की जितनी निन्दा की जाए कम है। इसी प्रकार जो जातिका सम्मेलन करने की बात है उससे साम्प्रदायिकता की भावनाएं फैलती हैं। कुछ व्यक्ति इस प्रकार की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। जब हरियाणा और पंजाब नही बना था तो कुछ लोग पंजाब में रहते थे और पंजाबी बोलते थे लेकिन उन्होंने अपनी मातृभाषा हिन्दी लिखवाई। आज 40 साल के बाद उनके दिमाग में यह बात रहनी ही नहीं चाहिए थी कि वे पंजाबी हैं या कोई और भाषा–भाषी हैं। यदि यह स्थिति एक बार शुरू हो गई तो देश को, समाज को तबाह कर देगी। आज की परिस्थितियों में यदि इस प्रकार के सम्मेलनों की इजाजत दी गई तो मुझे डर है कि देश में साम्प्रदायिकता का विष न घुल जाए। पंजाब की जो आत्म' विकराल स्थिति है, मुझे डर है कहा सारा देश इसकी लपेट में न आ जाए और देश को यह साम्प्रदायिक आग जलाकर न रख दे। इस प्रकार के जातीय सम्मेलन देश के, लिये बहुत घातक होते हैं। कुछ लोग अपने राजनैतिक स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। हो सकता णै ऐसे व्यक्तियों को अश्वनी स्वार्थ सिद्धि मे सफलता मिल भी जाए और वें उससे लाभ उठा ले लेकिन किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी जाति से

ताल्लुक रखने वाले लोग, मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस प्रकार की संकीर्ण भावनाओं से देश को तबाही की और ले जाते है। भूखेकी जाति है उसकी रोटी, नंगे की जाति है उसका कपडा और मकान, बीमार की जाति है दवाई और डाक्टर। ऐसे व्यक्ति जो सद्बुद्धि रखते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं जो प्रगति–शील विचार रखते है जातिवाद की संकीर्ण विचारधारा का विरोध करें और इस प्रकार के सम्मेलनों का बहिष्कार करें। उन्हैं लोगों को इस बारे मे जागरुक करना चाहिए कि जो नेता लोग इस प्रकार की स्वार्थ सिद्धि के लिए जिस प्रकार जातिवाद को बढ़ावा दे रहैं हैं, वह देश के लिए घातक हैं। मिस जाति विशेष के लिए इस प्रकार का सम्मेलन किया जाता है, वह व्याक्ति विशेष के लिए थोडी देर के लिए लाभदायक हो सकता है लेकिन उस जाति विशेष का शोषण होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को जाति, मजहब, पार्टी की संकीर्ण धारा से०पर उठकर अपना फर्ज निभाना चाहिए और इस प्रकार की बातों का विरोध कर समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए। नासमझी और अज्ञानता का यह अंधकार तभी दूर हो सकेगा जब सभी को बराबर का अधिकार मिले। इसी प्रकार सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स का उदाहरण है। आज सुबह तेल शोधक कारखाने के बारे में भी बात आई थी। जिसका शिलान्यास प्रधान मन्त्री कर जाएं उसके बारे में बाद में यदि प्लानिंग कमीशन या केन्द्रीय सरकार यह कहैं कि हमने इस पर विचार किया है और यह उचित नही है कि यह कारखाना यहां पर खोला जाए तो यह स्थिति ठीक नही है। लोगों

को गुमराह करने के लिए, लोगों से ठगी करने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए ऐसी जौ बाते की जाती है उनसे ज्यादा देर तक लोगों को बहकाया नही जा सकता। गलत व्यानी, गलत बातें, गलत आश्वासन देकर कोई व्यक्ति ज्यादा देर टिक नही पाता है। जो लोगों के सामने आश्वासन दिये जाते हैं जनता के प्रतिनिधि बने कर आने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि उन को पूरा किया जाये, उन बातों को लागू किया जाये ताकि जिस साधारण व्यक्ति का वोट ले कर हम आते है उन्हैं सन्तुष्टि हो कि हमारा प्रतिनिधि ठीक प्रकार से काम कर रहा है लेकिन दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान में जो नैतिकता की बात स्वतन्त्रता सैनानियों में थी उसमें गिरावट आयी है। अब एक प्रवृनि चार पड़ी है, केन्द्र चाहना है कि सारी शक्तियां केन्द्र के पास हों, उनका केन्द्रीयकरण हो। वह सारी शक्तियां अपने पास रखना चाहता है और प्रान्त यह चाहता है कि सारी शक्तियां मेरे पास रहैं। प्रान्त यह नहीं चाहता कि कमेटियों और पंचायतों को ताकत मिले। केन्द्र और प्रान्त का यह फर्ज बनता है कि शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण किया जाये।०पर से ले कर ग्राम में, पंचायतों में और म्यूनिसिपल कमेटी में अधिकार दिये जायें और जो आपस की कडवाहट है यह न हो। ऐसा करना प्रजातन्त्र के संघीय ढांचे को ठीक रखने के लिए जरूरी है। आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इस प्रकार की बातें उठाने के लिए मैं अपने आदरणीय 'मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल का धन्यवाद करता हूं और उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। वह प्रेरणा भी इस बात से मिनती णै कि जब प्रान्तों के अधिकारों की बात

छायी तो हमारे मुख्य मन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों की कांफ्रैस में पिछले दिनों कहा कि प्रधान मन्त्री जी हम किसी व्यक्ति विशेष की कठपुतली नहीं हैं, मैं जनता द्वारा चुना हुआ मुख्य मन्त्री हूं। इस बात पर उनकी बहादुरी की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। वे बधाई के पात्र हैं। लोगों को उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे मुख्य मन्त्री इतने बहादुर और निर्मीक व्यक्ति हैं तो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि देश के लिए प्रदेश के लिए या पार्टी के लिख जब कोई भी काम घातक और हानिकारक होने जा रहा हो तो चाहैं कोई मुख्य मन्त्री हो मन्त्री हो या प्रधान मन्त्री हो हमें उनकी नाराजगी की परवाह न करते हुए गिर्भीक हो कर बात कहनी चाहिए। अगर कोई अपने आप को चौधरी केवी लाल का फौलोर मानता है तो उसे निर्भीक हो कर ठीक बातों को कहना चाहिए। उस कार्यकर्त्ता में हिम्मत होनी चाहिए कि वह सही बात कह सैके वरना वह चौधरी देवी लारव का अनुयायी नही है वह उनका दुश्मन है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी चौधरी रणजीत सिह ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मकसद है कि हमारे प्रदेश में जो मात्र तैयार होता है, उसपर जो टैक्स लगता है वह प्रान्तीय सरकार को मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे प्रान्त में कारखाने लगें लेकिन उनके तैयार किये हुए माल पर टैक्स भी तो हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। यह बात उन्होंने ठीक रखी है और ठीक समय पर ठीक मुद्दा उठाया है। वास्तव में यह सराहनीय प्रस्ताव है।

हमारी विधान सभा ने एक प्रस्ताव और भी पास करके भेजा था जिस पर भी केन्द्र सरकार ने कोई अमरन नही किया। मैं आपके द्वारा एक बात बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने आजादी मिलने के बाद काग्रेस पार्टी के बारे में एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी प्राप्त करने के लिये एक आन्दोलन चलाया था। हमें आजादी मिल गई है इसलिये अब कांग्रेस पाटी को खत्म करके अपनी अपनी विचार धारांओं के आधार पर राजरैतिक पार्टी बना लेनी चाहिए लेकिन उनकी वह बात रही मानी गई। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने एक झण्डे के नीचे काम करके आजादी प्राप्त की उसी प्रकार दूसरी पार्टियों ने भी प्रजातन्त्र में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों दो ग्रीवैंन्सिज रीड्रैस करने के लिए अपनी योजना और घोषणापत्र को लागू करने के लिए अलग से पार्टियों का निर्माण किया और अपनी पार्टी के लिए अलग अलग झण्डे अपनाए लेकिन जो राष्ट्रीय झंडा है और कांग्रेस का झंडा है वे दोनों ही तरंगे हैं। कांग्रेस का झंडा भी तीन रंगों का है। साधारण व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि इनमें राष्ट्रीय झँडा कौन सा है और कांग्रेस का झण्डा कौन सा है। पिछले दिनों जब लोक दल की सरकार बन गई तो लोग गांवों में कहने लगे कि सरकार तो लोकदल की बनायी थी लेकिन इन्होने कांग्रेस का झण्डा क्यों लगा रखा है? राष्ट्रीय झण्डे और कांग्रेस के झंडे में कोई विशेष अन्तर उन लोगों को नजर नहीं आता है इसलिए कानून बनाना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडेसे मिलता जुलता झंडा किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। ये उसका

नाजायज और गलत तौर पर लाभ उठा रहैं हैं, मिसयुज कर रहैं हैं। इन्हैं उस झण्डे के बदलने के लिए कहना चाहिए हमारी विधान सभा ने चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में इस प्रकार का प्रस्ताव सब से पहले केन्द्र सरकार को भेजा था। लेकिन आज तक उसके बारे में भी केन्द्रीय सरकार ने कोई. कानूनी कार्यवाही नहीं की। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि अगर प्रान्तीय सरकारों की इस तरह की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो उसका परिणाम विरोध हो सकता है। वह विरोध सही या गलत तरीके से देश और प्रदेश के लिये घातक सिद्ध हो सकता है। देश के टुकड़े होने की नौबत आ सकती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को समय रहते, जैसे सरकारिया कमीशन ने राज्यों और देश की केन्द्रीय सरकारों के बीच सम्बन्धों के बारे में सिफारिशात की हैं कि किसी प्रकार से विरोधी दलों के नेताओं को बुलाकर बात करें क्या– क्या उनके अधिकार हैं, उनको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा कहना यह है कि मजबूती से उस कमीशन की सिफारिशों को इम्पलीमैंट किया जाना चाहिये। उस वक्त यह भूल जाना चाहिये कि हमारी पार्टी कौन सी है, हमारा नेता कौन सा है और हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी अपने नेता के प्रति है। सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी देश के नागरिकों के प्रति बै। देश के प्रति आपकी जिम्मेवारी है। बाकी सारी बातें बाद में हैं। अगर यश देश रहैंगा तो पार्टी भी रहैंगी, नेता भी रहैंगा और प्रजातन्त्र भी रहैंगा। अगर देश खत्म हो गया तो यह देश और समाज खत्म व तबाह हो जायेगा। प्रजातन्त्र भी खत्म हो जायेगा।

इसलिये केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि ऐसी बातों की तरफ बिना कोई ढील किये विचार करे। यह जो प्रस्ताव चौधुरी रणजीत सिंह जी ने पेश किया है, उसको समझने के बाद इस सदन के सारे सदस्यों ने उस पर अपने अमूल्य विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने भी निसंकोच होकर अपना यह प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव से विशेष रूप से हरियाणा को 200 या 250 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी हो सकती है। अगर यह रैवेन्यू प्रदेश में आ जाये तो मेरा जो अगला प्रस्ताव है, जो देश में नशाबन्दी का है, और जिसके लागू करने से 200 करोड़ के आस–पास शराब के टैक्स से जो आय होती है, उसकी कमी पूरी हो सकती है। महात्मा गांधी जी का जो सपना था, उसको साकार करने के लिये और चौधरी चरण सिंह और मोरार जी देसाई जैसे लोगों की भावनाओं पर चलने वाले चौधरी देवी लाल अगर कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार को महात्मा गांधी द्वारा दिखाये गये रास्ते पर चलने के लिये कहना चाहैंगे तो उस मेरे प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। इसलिये मेरे उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन है कि अब इसको पास कर दिया जाये और अगले प्रस्ताव पर चर्चा कर ली जाये। इसी भावना और शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद!

13.00 बजे।

श्री बलवीर ल्हि चौधरी (फतेहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी रणजीत सिंह जी ने 24 मार्च, 1988 को यह प्रस्ताव इस महान सदन के सामने पेश किया था। 1982 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सैट्रल सेल्ज टैक्स ऐक्ट को अमैंड करने की पावर ली थी, लेकिन इतने लम्बे समय में इसे अमैंड नहीं किया गया। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य थी आत्मा राम गोदारा पदासीन हुए) आज जिस प्रदेश के कारखानों से माल बनकर बाकी प्रदेशों में या देश के दूसरे हिस्सों में जाता है उस प्रदेश को उससे कोई टैक्स नहीं मिलता। सभापति महोदय, यह कितनी विडम्बना है कि प्रदेश के अन्दर, प्रदेश के 'बजट से सबसिडी लेकर, प्रदेश की जमीन पर, प्रदेश की बिजली से और इसी तरह से सब प्रकार के साधन प्रदेश से लेकर जो कारखाने स्थापित हों और जिनके द्वारा पैदा किया हुआ पोल्यूशन भी प्रदेश को भुगतना पड़े तथा हजारों लाखों लोग दूसरे प्रदेशों से आकर इस प्रदेश के अन्दर रोजगार पाएं, हमारे प्रदेश के मजदूरों को और गरीब लोगों को रोजगार मिलने में अड़चन आए, हमारे लोगों की जमीन छीनी जाए और उसके बाद जो कारखानें लगे और उनमें जो उत्पादन हो उससे प्रदेश को कोई आय न हो। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? पिछले चालीस साल में लगातार कांग्रेस शासन में हरियाणा के अन्दर जो तरक्की हुई उसमें साढ़े पांच लाख नौजवानों का ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेंजिज में नाम दर्ज है। मैं यह भी कह सकता हूं कि शायद इससे ज्यादा गरीब लोगों और नौजवान मजदूरों को

यह पता भी नहीं होगा कि नौकरी के दफ्तर में नाम दर्ज कराना जरूरी है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि चालीस साल के शासन में हरियाणा में जो बेकारी आई है वह बेकारी किस तरह से दूर की जाए वह इस प्रस्ताव पर अमल होने से दूर हो सकती है। मैं इस महान सदन के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो हमारा बजट है उससे अनएम्पलाएमैंट दूर हो सकती है। कृषि से पैसा काटकर कल कारखानों पर लगाया जाए और कल कारखाने लगाने के लिए बजट में ऐलोकेशन हो लेकिन फिर भी उन कारखानों में जो उत्पादन हो उससे हमें टैक्स की आमदनी न हो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? आज हरियाणा के बजट में 17 प्रतिशत कारखानों के लिए और इंडस्ट्री की डिवैल्पमैंट के लिए विधान है। आज कितने ही गांव हरियाणा के ऐसे हैं जहां पीने का पानी नही है, कितने ही छोटे गांव ऐसे हैं जहां छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं हैं। आज भी गांवों में रात को जब रोशनी की जरूरत होती है तो बिजली नही होती। हमारे पास बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसका गांवों में स्ट्रीट लाइट के लिए और घरों में रोशनी पहुंचाने के लिंए इस्तेमाल किया जा सके। वह हरियाणा जिससे भाखड़ा डैम का पानी आता है उस पानी के बावजूद आज भी हरियाणा कें गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। रोशनी के लिए गांव के लोगों के पास कोई इन्तजाम नहीं है। वे लोग अन्धेरे में रहते हैं। सभापति महोदय, पिछले साल हरियाणा के बहुत बड़े इलाके में सूखा पड़ा और इससे पहले भी चार पांच साल तक लगातार सूखे की स्थिति बनी रही लेकिन

एस० वाई० एल० बीच में पड़ी हुई है। इसलिए सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने की जरूरत है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि चाहैं आज हरियाणा हिन्दुस्तान में तरक्की के मामले में नम्बर एक पर हो लेकिन अन्दरूनी तौर पर हरियाणा की दशा को देखा जाए तो आज भी हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ है। हरियाणा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, गांव में मिडल स्कूल और प्राईमरी स्कूल खोलने के लिए, गांवों में अस्पताल खोलने और उनमें दवाएं देने के लिए, गांव में पशु अस्पताल खोलने के लिए, गांव में विजली का इन्तजाम करने के लिए, गांव में पीने के पानी का इन्तजाम करने के लिए और हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए आय के स्रोत चाहिए। प्रदेश की सरकार का खर्च चालीस–पैंतालीस महकमों पर हऐता है और केन्द्रीय सरकार का खर्च केवल डिफैन्स, कम्युनिकेशन और इसी तरह के चन्द महकमों पर होता है लेकिन उसके आय के स्रोत अनलिमिटिड हैं। जो भी कारखानों में माल तैयार होता है उसकी ऐक्साइज ड्यूटी केन्द्रीय सरकार ले लेती है। हमारे पास सेल्ज टैक्स है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स के नाम पर टैक्स लगाया हुआ है यह कितनी अनुचित बात है? बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले दिनों हरियाणा के अन्दर इस तरह से भयंकर बाढ़ आयी और बहुत बड़ा इलाका पानी में डूब गया। फसल नष्ट हो गयी। लोगों का साजो–सामान खत्म हो गया। लोगों के ट्रैक्टर बगैरह तबाह हो गये और लोग दाने–दाने को तरसने लगे। इस तरह से मौत का साया हरियाणा के बहुत बड़े क्षेत्र के०पर पड़

गया। इतना होने के बावजूद हरियाणा सरकार ने अपने सीमित साधनों से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की और लोगों को पानी से निकालने की व्यवस्था की। चेयरमैन साहब, यह कितनी विडम्बना है कि चौधरी भजन लाल जो आज हरियाणा की ओर से केन्द्र में कृषि मन्त्री के पद पर विराजमान हैं। वे इस तरह का ढोल पीट रहैं हैं कि केन्द्रीय बजट का 40 परसैन्ट पैसा आज किसानों के उत्थान के लिये लगाया जा रहा है। मैं यह कहता हूं ? कि आज यह कहते हुए उन्हैं शर्म आनी चाहिये। चुल्लू भर पानी भी शायद उन्हैं नहीं मिल रहा जिसमें वे डूब मरें क्योंकि आज जिन किसानों का सर्वनाश हो चुका है उनको केन्द्र सरकार की ओर से एक भी पैसा नही मिल रहा है। न ही प्रदेश सरकार के पास इतने साधन उपलब्ध हैं कि जिन से किसानों को पूरा कम्पनसेशन दिया जा सके। हिन्दुस्तान के अन्दर, केन्द्र सरकार किसानों की सहायता का ढोल पीटती है। आज हजारो किसान परिवार ऐसे हैं जोकि बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, बे–जमीन हो चुके हैं और खेतीहर छोटे–छोटे मजदूर आज बिछल बेकार हो गये है। उनको पैदावार का कोई हिस्सा नही मिल रहा है। इने लोगों के पास अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिये कोई निश्चित साधन नहीं हैं। खेत डूब गये हैं। छोटे छोटे मालिक आज पूरी तरह से डिसऐबल हो गये हैं। आज हमारे देश व प्रदेशों में बहुत से आर्थिक विकारों की लड़ाई चल रही है। पंजाब का मसला आज इस बात का एक उदाहरण है कि आर्थिक लड़ाई के कारण, सैन्टर और स्टेट रिलेशन्ज के कारण, आज जो केन्द्र के

पास प्रदेशों का गला घोंटू कानून है उसके कारण देश में अव्यवस्था फैल रही है। आज चण्डीगढ़ को छोडने के लिये हरियाणा के हजारों लोगों का कत्लेआम होना शुरू हो गया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश है। इसको और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिये हरियाणा को आर्थिक सहायता 'की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके मुकाबले में केन्द्र सरकार की जो नीति है, वह क्लीयर नही है। इस टैक्स पर स्टेट के हक के लिये 28— 5—84 को चीफ मिनिस्टर्ज ने रिकमैन्ड किया, रिजनल कौंसिल ने युनैनीमसली इसकी रिकमैन्डेशन की और फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन ने और नैशनल डिवैल्पमैन्ट कौंसिल ने इसको इंडोर्स किया। कितने ही एम० पीज० ने इस के बारे में पार्लियामैन्ट में आवाज उठायी। बहुत से चीफ मिनिस्टर्ज ने भी केन्द्रीय सरकार से मांग की कि इस फैसले को जल्दी इम्पलीमैंट किया जाए। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने भी केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया लेकिन उसके बावजूद भी आज तक सन 1982 में हुए संशोधन का कुछ नहीं हुआ। यह कितनी विडम्बना है? बहुत सालों की मांग के बाद 1982 में इसमें संशोधन किया गया लेकिन अब 1989 आ गया है। प्रधान मन्त्री राजीव गांधी की जो लायबिलिटी थी या जिम्मेदारी थी कि देश में अव्यवस्था न हो, देश के अन्दर सैट्रल—स्टेट्स रिलेशज के लिए जदो—जहद न हो, देश के अन्दर गुर्बत न बढ़े, इसके लिए जरूरी था कि इस संशोधन क आधार पर सैट्रल सेल्ज टैक्स ऐक्ट में अमैंडमैंट की जाती या कोई नया कानून लाया जाता जिसके

आधार पर प्रदेश सरकारों को एक यूनिफार्म टैक्स लगाने का अधिकार मिलता। मैं इन शब्दों के साथ इस महान सदन से मांग करता हूं कि जो प्रस्ताव चौधरी रणजीत सिंह जी ने रखा है उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया जाए कि अति शीघ्र इस कन्साइनमैंट टैक्स का प्रावधान सैट्रल सेल्ज टैक्स ऐक्ट में करे या कोई नया कानून बना कर ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि हरियाणा प्रदेश तथा दूसरे प्रदेश तरक्की कर सकें। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

श्री रतन लाल कटोरिया (रादौर–अनुसूचित जाति): मान्यवर चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव चौधरी रणजीत सिंह द्वारा सदन में रखा गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वास्तव में वर्षों की लम्बी राजनैतिक लड़ाई जीतने के बाद यह देश आजाद हुआ। बाबू राजेन्द्र प्रशाद, डा० भीम राव अम्बेदकर और पंडित जवाहर लाल जैसे महान नेताओं ने इस बात का अध्ययन किया कि इस मुल्क के अन्दर सरकार चलाने का सिस्टम किस प्रकार का होना चाहिए। हमें साढ़े तीन सौ वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहना पड़ा और यूनाइटिड किंगडम में यूनिटरी सिस्टम औफ गवर्नमैंट था। अंग्रेजों की यह नीति थी कि जब भी कोई ऐक्ट बनाया जाता था तो उसके अन्दर स्ट्रौंग केन्द्र की बात की जाती थी। लेकिन संविधान की ड्राफ्टिग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेदकर ने डिफरैटं कन्ट्रीज के संविधानों को पढ़ा। उन्होंने अमेरीका, आयरलैडं, फ्रांस और जर्मनी वगैरह देशों के संविधान

पढ्ने के बाद एक निष्कर्ष बनाया कि हिन्दुस्तान चूंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी लम्बाई चौड़ाई साढ़े चार हजार किलोमीटर है, हर हजार या आठ सौ किलोमीटर पर लोगों की भाषा बदल जाती है और यहां पर कई प्रान्त बहुत बड़े हैं, इसलिए मुल्क को कन्ट्रोल करते के लिए संघीय ढांचे को अपनाया जाना चाहिए यानी फैड्रल सिस्टम औफ गवर्नमैंट को अपनाया जाना चाहिए। इस देश के जो महान नेता थे उनका यही निष्कर्ष था कि हिन्दुस्तान में भिन्न–भिन्न समुदायों में भिन्न–भिन्न भाषाएं होते हुए भी हमें एक स्ट्रौंग सैंटर चाहिए लेकिन उसके साथ–साथ अपनी संस्कृति के विकस के लिए प्रदेशों का विकास होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए उनका विचार था कि संविधान में कोई इस प्रकार कॉ सिस्टम अपनाया जाए जिसमें हमारी संस्कृति और प्रदेशों को विकास हो। लेकिन जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय से केन्द्रीय सरकार की यह मंशा रही है और उसने शुरू से ऐसी नीति अपनानी शुरू की कि जितने भी अधिकार थे वे सारे के सारे अधिकार केन्द्रीय सरकार आहिस्ता–आहिस्ता अपने हाथ में लेती गई। उसके पीछे मूल भावना यही थी कि प्रदेशों के अन्दर ऐसा कोई नेतृत्व न उभर जाए जो कल को सैंटर के लिए खतरा बन जाए। उस खतरे से बचने के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशों को कम अधिकर दिए ताकि प्रदेश अपने अधिकारों के लिए बिलखते रहैं। चेयरमैन साहब, यह ठीक है कि आज पंजाब के अन्दर उग्रवाद छाया हुआ है और आज उसका मूल कारण दूसरा बन गया है, आज वह कारण नही है लेकिन जिस समय पंजाब में

यह लड़ाई शुरू हुई थी उस समय इसका– मूल कारण यही था कि पंजाब के लोग राज के विकास के लिए अपने अधिकारों की मांग करते थे लेकिन केन्द्र अपने हाथ सिकोड़ता रहा और उनको अधिकार नही दिए। उसके परिणामस्वरूप देश के अन्दर अनएम्पलायमैंट तो बढ़ी ही उसके साथ–साथ राज्यों में असंतोष भो बढ़ा। केन्द्र की जो मंशा थी वह पूरी नही हुई उल्टे उनको कई प्रदेशों के अन्दर मुंह की खानी पड़ी। आन्ध्र प्रदेश मैं सत्ता का परिवर्तन हुआ। उसके भी मूल कारण यही थे कि केन्द्र की आन्ध्र प्रदेश के प्रति जो मंशा थी वह सही नही थी। तामिलनाडु के अन्दर भी अभी चुनाके के दौरान केन्द्र को बड़ी जबरदस्त मुह की खानी पड़ी। उसके भी मल कारण यही थे कि तामिलनाडु के प्रति भी केन्द्र की मंशा सही नही थी। आज की केन्द्रीय सरकार में ऐसे–ऐसे लोग पहुंच गए जिनको राजनीतिक तजुर्बा नही है। आज की केन्द्रीय सरकार मे अमिताभ बच्चन और वेजैन्ती माला जैसे लोग पहुंच गए जिनको राजनीतिक तजुर्बा नही है। जिस समय चीन ने डिगो गारसिया के अन्दर अपना हवाई पैड बनाया उस समय अमिताभ बच्चन पार्लियामैंट के मैम्बर होते थे। उनसे हमारी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण अडवानी जी ने जब पूछा कि आप चूंकि हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट के मैम्बर हो इसलिए चीन के यह जो बुरे इरादे हैं इनके बारे में आप अपनी राय दें तो उस समय अमिताभ बच्चन का यह विचार रहा होगा कि 'मेरे अंगने में चीनियों का क्या काम है, मैं तो फिल्म वाला हूं मेरा तो पहले ही बड़ा नाम है। (हंसी) ऐसे–ऐसे लोग

आज की पार्लियामैंट में घुसे हुए हैं। आज की केन्द्रीय सराकर को तमिलनाडु के चुनावों में जनता ने यह फतवा दिखा दिया कि जनमो अब आपसे प्रभावित होने वाली नही है। गोविल–फोविल जो चेहरे इलाहाबाद के इलैक्शन में गए थे उनको वहां की जनता ने दिखा दिया कि हम आपसे प्रभावित होने वाले नहीं हैं। चेयरमैन साहब तमिलनाडु के चुनावों में एक दिलचस्प बात देखने में आई। अपने देश के प्रधान मंत्री ने एक फिल्म ऐक्ट्रैस के पिता जी को कहा से कांग्रेस पार्टी का टिकट दे दिया। वह ऐक्ट्रैस बहुत मशहूर है। नगीना फिल्म में उसका एक गाना भी हिट हुआ है। उस एक्ट्रैस का नाम श्रीदेवी है। उसके पिता जी को चूकि कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला हुआ था इसलिए राजीव गांधी ने सोचा कि श्रीदेवी को उसके पिता जी के हल्के में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाए। जिस समय श्रीदेवी अपने पिता जी के हल्के में प्रचार करने के लिए गई तो जनता उसको केवल फिल्म ऐक्टैरस समझते हुए सारे सिनेमा हाल खाली करके वहां पर पहुंच गई और वहां पर दूसरे जितने भी नेताओं की पब्लिक मीटिग थों वह फेल हो गई। लाखों की संख्या मैं लोग उसकी पब्लिक मीटिंग में पहुंच गए लेकिन जिस दिन वोट डालने का समा आया उस समय उसको कोई वोट नही डाला गया। मेरे ख्याल में उसकी जमानत ही जब्त हो गई यानी लोगों ने अपना मन बना लिया है कि जो फिल्म ऐक्टर्ज है ये देश को नही चला सकते। ऐसे–ऐसे लोग आज इस देश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं विनके कारण हमारा जो पार्लियामैट्री सिस्टम औफ गवर्नमैट था उसको बड़ा आघात पहुंचा

है। कहां पर तो सरदार पटेल जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने देश को बनाने में कोई कसर नही छोड़ी। निजाम हैदराबाद ने सरदार पटेल को आख दिखा दी कि मैं अपने आपको हिन्दुस्तान के अन्दर शामिल नही करना चाहता। सरदार पटेल ने उसको 24 घंटे के अन्दर–अन्दर धाराशाही कर दिया और उसको हिन्दुसतान के अन्दर शामिल करके दिखा दिया। ऐसे–ऐसे लोग इस देश में पैदा हुए। चेयरमैन साहब, राम बिलास शर्मा जी ने ठीक ही कहा है कि कहां पर तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग थे जिसने ताशकंद समझोते में हिन्दुस्तान की युनिटी के लिए आने प्रागों का बलिदान दिया और हिन्दुस्तान की एक इन्च जमीन भो छोडो के लिए तैयार नही हुए। कहां पर तो हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी ऐसी हस्तियां पैदा हुई ओर कहां पर आज अमिताभ बच्चन और वैजयन्ती माला जैसे लोग पहुंच गए जिसके कारण आज पार्लियामैंट सिस्टम औफ गवर्नमैंट में कमी आई। ये जो हमारे वर्तमान प्रंधान मंत्री हैं इनकी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने लाटरी खोल दो। जो व्यक्ति जहाज चलाया करता था आज वह हिन्दुस्तान चला रहा है। यह ठीक है कि वह जहाज चलाने में निपुण होगा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय–, इस हिन्दुस्तान मुल्क की आबादी 80 करोड़ है, इसको चलाना इतना आसान काम नहीं है। उस दुर्घटना के बाद जो पार्लियामैंट के चुनाव हुए उसमें उनको इतना जन समर्थन मित्रा कि पार्लियामैंट में कांग्रेस पार्टी को 425 सीटें मिल गई। जिन परिसितियां में वर्तमान प्रधान मन्त्री ने प्रधान मन्त्री का पद सम्भाला था उसने लोगों ने सोचा था कि यह व्य–छा

काम करेगा लेकिन अब तो लोगो ने यह सोच लिया कि यह तो बहुत ही बुजदिल और ना–तुजर्बेकार निकला है। आज के हमारे प्रधान मंत्री 15 अगस्त को बुलेटप्रूफ शीशे में खड़े हौ कर 'भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम डरो मत, बहादुर बनो। जिस देश का प्रधान मंत्री खुद बुलेटप्रूफ शीशे में खड़े हो कर लोगो को कह रहा हो कि तुम बहादुर वनों और डरो मा, इससे उनकी बहादुरी का पता लगता है कि वे कितने बहादुर है। जो प्रधान मंत्री देश के स्वतंत्रता दिवस पर बुलेटप्रूफ शशि मे खड़ा हो कर बहकी वहकी बातें करता हो और जो स्वतंतता दिवस को गणतंत्र दिवस कहने लग जाये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री महाशय पीछे अमेरिका में गए थे। वहां पर वे एक युनिवर्सिटी के अन्दर बोल रहैं थे। वे वहां पर बोल रहैं थे जहां पर बड़ी बड़ी इन्टेलीजेन्सियां बैठी थी और बड़े बड़े प्रोफैसर्ज बैठे थे। उस समय वे वहां पर बोल्ते हुए कह रहैं थे कि आई० ए० एस० या आई० पी० एस० बनना कोई बड़ी बात नही है कोई भी अनपढ़ आदमी आई० ए० एस० या आई० पी० एस० बन सकता है। वे सब सोचने लगे किं एक प्रधान मंत्री कैसी वहकी बहकी बाते कर रहा है। इसमें इस बेचारे का भी कोई दोष नही है क्योंकि उनकी जो किचन केबिनेट बनी हुई है उस मे ऐसे–ऐसे लोग लिए हुए है जो उनको सही दिशा नही दे सके। वे जिस तरफ भी कदम बढ़ाते है धड़ाम से गिर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जिस रैजोल्यूशन की बात अब हम कर रहैं हैं इस पर एक अमैडमैंट बिल 1982 मे लाया गया था।

इस अमैंडमैट को लाये हुए आज 7 साल हौ गए है लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा अमल' नही किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा के अन्दर कोई कारखाना लगे तो उसके लिए जमीन तो हम दें, बिजली हम दे और उस कारखाने को लगाने के लिए दूसरे कम्पनसेशन हम दें लेकिन उस कारखाने का टैक्स ले जाये प्रधान मन्त्री यानी केन्द्र सरकार। स्वीकर साहब, यह कहां का इन्साफ है कि किसी कारखाने को लगाने के लिए सब कुछ तो हम करें और फिर टैक्स ले जाये केन्द्र सरकार? केन्द्र सरकार राज्यों को सता सता कर मारना चाहती है। हम भी केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहैं व्यवहार के कारण निराशावादा नही हुए। आज हमारे साथ राजीव गांधी जिस तरह का सलूक कर रहा है उसका जवाब मैं एक शेयर के रूप में देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह शेयर इस प्रकार है

हंस हंस के जवां दिल के, हम क्यों न चुनें टुकडे,

हर शख्स की किस्मत में ईनाम नहीं होता,

बहते हुए आसूओ ने हमसे कहा,

जो मय से पिघल जाये, वह जाम नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, हम इतने डरपोक नहीं कि जब चाहैं हमें परेशान कर दिया जाये। चौधरी देवी लाल जी ने एक बार केन्द्र को डट कर जवाब दिया कि हम किसी की कठपूतली नहीं है कि जब चाहैं जैसा नाच नचा लें। अध्यक्ष मदोदय, आप भी इस

बात को जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश एक छोटा सा प्रान्त है। लेकिन मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा यह छोटा सा प्रान देश के 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज की हर छठी बोरी दे रहा है। हमारा यह छोटा सा प्रान्त देश को गन्ना दे रहा है, दूध और चावल दे रहा है। हमारे यह का बासमती चावल सारे हिन्दुस्तान में मशहर है। इतना कुछ हरियाणा प्रान्त केन्द्र को दे रहा है लेकिन जब केन्द्र द्वारा कोई चीज इस प्रदेश को देने की बात आती है तो केन्द्र सोचता है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार को कम जोर किया जाये। लेकिन जिन लोगों का मनोबल०ंचा होता है जब वे कारवां के रूप में निकल पड्हैं हैं, प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जैसे लोग उन्हैं रोकने में सफल नहीं होंगे। मैं इसके समर्थ न में यह कहना चाहता हूं कि आज वक्त का तकाजा है, हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ने जाने के लिए इस देश को जैसे पहने सोनें की चिड़िया कहा जाता था, इसे सोने की चिड़िया बनाने के लिए, मैं इस महान सदन के माध्यम से इस नातजुर्बेकार प्रधान मन्त्री से कहना चाहता हूं कि वह सभी को बराबर का हक दें। जो गिने–चुने दिन उसके रह गये हैं उनमें उसको चाहिए कि कम–से– कम कुछ ऐसे काम कर ले जिससे आने वाले लोग उसे भी हिन्दुस्तान की तरक्की में शरीक करें और प्रदेश सरकारों की टागें खींचने के बजाये प्रदेश सरकारों को कुछ न कुछ सहयोग दें। मैं आज इस फोरम से हरियाणा के हितों की मांग करना चाहता हूं। पिछले 20 महीने में जगह–जगह पर इस प्रकार के इन्सटांसिज हैं कि सैंटर की तरफ से हरियाणा सरकार

की टांगें खींची गई। चाहैं यह मू बे का माम ना था या बाढ़ राहत का, केन्द्र ने वांछित सहयोग नहीं दिया। जितना सूखा हरियाणा मैं पड़ा इतना पिछले 100 साल में भी नहीं पड़ा था। जिन तरह से उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान को करोडों रुपयों की मदद दी गई, उसी तरह हरियाणा प्रदेश को मदद देने में क्या तकलीफ थी? इसके बाद बाढ़ ने प्रदेश में अभूत पूर्व तबाही मचाई। प्रधान मन्त्री जी को चाहिए था कि वे खुले दिल से सैंटर–स्टेट्न रिलेशन्ज को कौर्डियल बनाते। प्रान्त सरकारों की लीडरशिप का मत जीतने के लिए फराखदिली से काम लेते और ऐसे काम करते जिससे सैटर–स्टेट रिलेशन और अधिक कौर्डियल होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नही किया। फैडरल सिस्टम में जिस तरह का प्रावधान बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर नैं किया था या जैसा प्रोविजन. बनाया था कि स्टेट्स और सैंटर के आपस में कौर्डियल रिलेशल्ज रहैं और वे एक–दूसरे के साथ मिल–जल कर चलें जिससे सारे हिन्दुस्तान को परम वैभव की ओर ले जाया जा सके, उसको उन्होंने नही अपनाया। इसके लिए सैंटर द्वारा बार–बार जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं इनकी तरफ हमें गम्भीरता से सोचना होगा। आज मैं इस फोरम से सैटर से यह मांग करता हूं कि हरियाणा की इस लोकप्रिय सरकार से जो भेदभाव किया जा रहा है उसे समाप्त किया जात तथा विकास कार्यों के लिए राज्यों का शोषण वन्द किया जाए। 1982 के कन्साइनमैंट टैक्स के लागू हो जाने से सारे हरियाणा प्रदेश में प्रगति की लहर छा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं एक और बारा कहना चाहता हूं कि चीजों

के उत्पादन और उनके विक्रय मूल्य के बीच में भी सामंजस्य बनाये जाने की कोशिश होनी चाहिए। आज जिस तरह से फैक्टरियों में उत्पादन होता है और जिस भाव पर चीजें उपभोक्ता को मिलती हैं, उनमें तालमेल होना चाहिए। उदाहरणतया सोनीपत में ऐटलस साईकिल की फैक्टरी है। वहां पर हमारे ऐक्सपर्ट को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि एक साईकिल पर उत्पादन लागत कितनी आती है और वह साईकिल बाजार में कितने की बिकती है। स्पीकर साहब, इस मामले में लूट हो रही है और खुले आम लूट हो रही है। उत्पादन मूल्य और विक्रय मूल्य में भोरी अन्तर है। जो साईकिल 500 रुपये में बनती है वह बाजार में 700 या 800 रुपये में बिकती है। स्पीकर साहब, उत्पादन के बाद उस वस्तु का बिक्री का मूल्य निर्धारित होना चाहिए और जायज मुनाफा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 20 प्रतिशत मुनाफा फैक्टरी वाले ले लें लेकिन लूट तो न मचाएं। आज गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है, किसान क्यों पिसता जा रहा है? मजदूर की मजदूरी तो बढ़ती है एक रुपया या आठ आना लेकिन बाजार में वस्तुओं के भाव बेतहाशा' बढ़ जाते हैं। किसान की फसल जब पक कर तैयार होती है तो केन्द्र सरकार बहुत बड़ा तीर मारने की कोशिश करती है और कहती है कि हमने किसान की गेहूं का भाव बढ़ा दिया है लेकिन मूल्य कितना बढ़ा है? 2 रुपये या 5 रुपये प्रति क्विंटल? एक मजदूर की मजदूरी साल में आठ आना या एक रुपया वढ़ती है गेहूं का भाव दो रुपये या पांच रुपये क्विंटल बढ़ता है लेकिन एक मारूति कार की कीमत कितनी बढ़ती है, 3,000 या 5,000 रुपये

सालाना? स्पीकर साहब, लूट मची हुई है। उत्पादन मूलय और बाजार के भाव में तालमेल होना चाहिए, कोई सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हरियाणा सरकार को किसी प्रकार की बाधा नही है। इस प्रकार की जो बिग फैक्टरीज हैं, उतमें जो माल बनता है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान् सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो माल फैक्टरीज से बन कर निकलता है और जो बाजार में बिकता है, उसका मुल्य फैक्टरी से माल निकलते ही तय हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः कटारिया साहब, आप बैठिए। आप कटिन्यू करेंने। अब हाउस, मंगलवार, 7 मार्च, 1989, बाद दोपहर 2.00 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

13.30 बजे।

(तत्पश्चात् सदन मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 1989, बाद दोपहर 2:00 बजे तक स्थगित हुआ।)